वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

ग्लोबल साउथ के विकास को सुनिश्चित करना

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

विषय सूची

महानिदेशक की रिपोर्ट vii

1. वैश्विक शासन और सतत्ता में भारत का दूरदर्शी नेतृत्व 1

2. सतत विकास, लाइफ (LiFE) और हरित विकास 7

3. व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाएं और आर्थिक मजबूती : समावेशी और नवोन्मेषी भारत की ओर 13

4. कनेक्टिविटी, गलियारे, बुनियादी ढांचा और वित्त 19

5. भारत की विदेश नीति में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग 27

6. विज्ञान नीति और प्रौद्योगिकी शासन 39

7. पारंपरिक चिकित्सा और आरोग्य 45

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद 51

सुखमय चक्रवर्ती पुस्तकालय एवं आंकड़ा सूचना केन्द्र 65

अभिस्वीकृति 70

मानव संसाधन 71

वित्तीय विवरण 81

संचालन परिषद

पदेन सदस्य

राजदूत संजय कुमार वर्मा
(7 जनवरी 2025 से)

पदेन सदस्य

श्री विक्रम मिस्री
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय

श्री अजय सेठ
सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
(जून 2025 तक)

सुश्री अनुराधा ठाकुर
सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
(जूलाई 2025 से)

श्री राजेश अग्रवाल
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(अक्टूबर 2025 से)

श्री सुनील बरतवाल
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(सिंतबर 2025 तक)

प्रोफेसर अभय करंदीकर
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री दामु रवि
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय
(अगस्त 2025 तक)

श्री सुधाकर दलेला
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय
(सितंबर 2025 से)

अपदेन सदस्य

श्री शेषाद्री चारी
अध्यक्ष, चाईना स्टडी सेन्टर,
माहे, मनीपाल

श्री जयंत दासगुप्ता
डब्ल्यूटीओ में भारत के
पूर्व राजदूत

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
पुर्व उप गवर्नर, आरबीआई

सदस्य सचिव (पदेन)

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस
(7 सिंतबर 2025 तक)

प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा
महानिदेशक, आरआईएस
(8 सिंतबर 2025 से)

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अध्यक्ष

श्री एस. टी. देवरे
पूर्व राजदूत

सदस्य

प्रोफेसर पुलिन बी. नायक
भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
(4 फरवरी 2025 तक)

सुश्री सिंधुश्री खुल्लर
भूतपूर्व सीईओ,
नीति आयोग

डॉ. रघुराम एस.
संयुक्त सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय
(अगस्त 2025 तक)

सुश्री अपर्णा रे पाई
संयुक्त सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय
(सितंबर 2025 से)

विशेष आमंत्रित सदस्य

डॉ नागेश कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी,
औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान
(आईएसआईडी), नई दिल्ली

प्रोफेसर एस.के. मोहंती
विशिष्ट फैलो, आरआईएस

सदस्य सचिव

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस
(7 सितंबर 2025 तक)

प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा
महानिदेशक, आरआईएस
(8 सितंबर 2025 से)

महानिदेशक की रिपोर्ट

प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा

सर्वप्रथम, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रतिष्ठित संस्थान आरआईएस के महानिदेशक के तौर पर इसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। इसके लिए, मैं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का आभारी हूं। मैं अपने पूर्ववर्तियों –संस्थापक महानिदेशक आदरणीय प्रोफेसर वी.आर. पंचमुखी से लेकर प्रोफेसर नागेश कुमार, प्रोफेसर बिस्वजीत धर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हूं। अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान बिरादरी में आरआईएस की भूमिका को मजबूती प्रदान करने की दिशा में दिए अपार योगदान के लिए हम सदैव इन सभी के आभारी रहेंगे। इनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, आरआईएस के 'ग्लोबल साउथ की आवाज़' बनने के दायित्व को पूरा करना मेरा मुख्य उद्देश्य होगा।

आरआईएस की कार्ययोजना का फोकस दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग, व्यापार, वित्त, निवेश और प्रौद्योगिकी पर है, इसलिए वर्ष 2024–25 के दौरान, संस्थान ने साक्ष्य–आधारित विश्लेषणात्मक नीतिगत अनुसंधान से संबंधित इनपुट प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करते हुए कई नीतिगत संवादों का आयोजन और कई प्रकाशनों का विमोचन किया। इसके कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में: ''त्रिकोणीय सहयोगः नए तौर–तरीके और नई उम्मीद; ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत की जी–20 की अध्यक्षता; ग्लोबल साउथ में विकास को आगे बढ़ाना; त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से संबंधों को बेहतर बनाना; ग्लोबल साउथ के लिए कृषि में डिजिटल तकनीकें; ग्लोबल साउथ में सतत कृषि और कृषि–पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण; विकास सहयोगः ग्लोबल साउथ का परिप्रेक्ष्य; सहयोग बढ़ाना : जी–20, एसडीजी और सार्वजनिक नीति पर आरंभिक प्रशिक्षण कार्यशाला; असमानता, आर्थिक विकास और समावेशन; ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रम्प; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वित्तीय समावेशन; भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) को आगे बढ़ाना; बिम्सटेक क्षेत्र में कृषि व्यापार से संबंधित तालमेल : क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन; दूसरा हिंद–प्रशांत आर्थिक सम्मेलन (आईपीईसी); भारत की सांस्कृतिक संबद्धता; भारत–जापान आर्थिक संबंध; सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) तथा विकासात्मक साझेदारियां; भारत के वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष पदचिन्हों का इन–स्पेस तक विस्तार; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में साइबर सुरक्षा; स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : जिम्मेदार एआई की दिशा में मिलकर सीखना आदि शामिल हैं।

इसी तरह, साल भर में आरआईएस प्रकाशन के अंतर्गत कवर किए गए कुछ मुख्य विषयों में : ट्रम्प्स ट्रेड पॉलिसीज पेरिल ग्लोबल इकोनोमिक स्टेबिलिटी; एमएसएमई डिजिटलाइजेशन इन इंडियाः करंट स्टेट्स एंड चैलेंजेस; इंडियाज़ एक्सपीरिएंस इन इंसोलवेंसी लॉज़ः लर्निंग्स फॉर द ग्लोबल साउथ; डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्सः अ माइक्रो–लेवल ट्रेड स्ट्रेटेजी; स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ मिनरल सिक्युरिटीः फ्रॉम एफर्ट्स टू एक्शन; इंडिया–मिडिल ईस्ट–यूरोप इकोनोमिक कोरिडोर (आईएमईसी) : स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड वे फॉरवर्ड; असेसिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया; सीफररज़ वेल बीइंग एंड मिटिगेशन ऑफ चैलेंजिज इन द इकोसिस्टम; बे ऑफ बंगाल एंड इंडिया–जापान इकोनॉमिक रिलेशन्स; बिम्सटेक सिनर्जीज इन एग्रीकल्चरल ट्रेडः प्रमोटिंग रिजनल ग्रोथ; कल्चर फॉर रीजनल कोहेशन एंड ग्लोबल एंगेजमेंटः द केस ऑफ आसियान; आसियान–इंडिया कोऑपरेशन –अ न्यू परस्पेक्टिव बेस्ड ऑन द अंडरवॉटर डोमेन अवेयरनेस (यूडीए) फ्रेमवक; एन्हैंसिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू सस्टेनेबल एग्री–फूड सिस्टम्सः लेसन्स फ्रॉम इंडिया एंड आसियान इनिशिएटिव्स; अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ आसियान–इंडिया रीजनल वैल्यू चैन– शामिल हैं।

आरआईएस अपने केंद्रों, जैसे दक्षिण, आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र, समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी) और फोरम फॉर इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन (एफआईटीएम) और ब्लू इकोनॉमिक फोरम (बीईएफ), फोरम फॉर इंडियन डेवेलपमेंट कोऑपरेशन (एफआईडीसी) और फोरम फॉर इंडियन साइंस एंड डिप्लोमेसी (एफआईएसडी) जैसे मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक मसलों और विकास साझेदारियों पर नीतिगत सामंजस्य की प्रक्रिया में गहन रूप से संलग्न रहा। यह संस्थान जी20, ब्रिक्स, इब्सा, बिम्सटेक, आईओआरए, आदि जैसी अनेक बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग पहलों की अंतर–सरकारी प्रक्रियाओं में शामिल रहा।

इस वर्ष भी हमारे संकायों के युवा सदस्यों ने विभिन्न अध्यायों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें वर्तमान में जारी हमारे अनुसंधान कार्यक्रमों और दूसरी संबंधित गतिविधियों के अलग–अलग पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। हम उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और उनके भावी अनुसंधान एवं शैक्षणिक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

अतीत की तरह, हमें इस वर्ष भी आरआईएस शासी परिषद एवं शासी निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्यों और आरआईएस अनुसंधान सलाहकार परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों से निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। हम अपनी कार्ययोजना से निकट संबद्धता के लिए विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और भागीदार संस्थानों के सदैव आभारी रहेंगे। इसके अलावा, आरआईएस के अनुसंधान के एजेंडे को प्रभावी ढंग से लागू करने और साल भर विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए आरआईएस के संकाय सदस्यों और प्रशासनिक टीम का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस सहायता और सहयोग के लिए उन सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद। मेरे महानिदेशक पद संभालने की संक्रमण अवधि के दौरान अपार समर्थन प्रदान करने के लिए प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी का भी मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि इस रिपोर्ट की विषय वस्तु आपको दिलचस्प लगेगी।

सचिन कुमार शर्मा

1 वैश्विक शासन और सततता में भारत का दूरदर्शी नेतृत्व

दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंची है। जैसे–जैसे पारंपरिक शासन संरचनाओं को चुनौती मिल रही है, एक नवीन, आत्मविश्वास से भरपूर और सक्रिय ग्लोबल साउथ उभर रहा है, जो ना केवल वैश्विक मंचों पर अपनी जगह ही नहीं मांग रहा है, बल्कि उन मंचों की संरचना और दिशा को भी नया आकार दे रहा है। भारत इस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो वैश्विक सहयोग का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है, जो मांग पर आधारित, न्यायसंगत और टिकाऊ हो। भारत का दृष्टिकोण पारंपरिक सहायता से परे, साझेदारी, साझा सीख और नैतिक ज़िम्मेदारी पर आधारित एक 'विकास समझौता' है। विकास

के लिए व्यापार, प्रौद्योगिकी साझाकरण, सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण और परियोजना–विशिष्ट रियायती ऋण और अनुदान जैसे तौर–तरीकों से संचालित इस समझौते के माध्यम से भारत वैश्विक शासन में केवल भागीदार भर नहीं रह गया है, बल्कि इसके भविष्य की दिशा भी निर्धारित कर रहा है। भारत अपने नैतिक मॉडलों, लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) जैसी दूरदर्शी पहलों और संस्थागत सुधार के अपने दृढ़ एजेंडे के माध्यम से, अधिक सशक्त और समावेशी दुनिया की ओर अग्रसर हो रहा है।

वैश्विक शासन संरचना में सुधारों का नेतृत्व करना

ग्लोबल साउथ के देशों को तीसरी दुनिया, विकासशील देश, अल्प विकसित देश, उभरती अर्थव्यवस्थाएं, परिधीय और बहुसंख्यक विश्व जैसे भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता है। ये राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय शब्द दर्शाते हैं कि इन देशों के पास वैश्विक मंच पर एजेंडा निर्धारित करने की शक्तियों का अभाव है। आर्थिक परिवर्तन ग्लोबल साउथ के इन देशों के उत्थान के प्रमुख प्रेरक रहे हैं और तीव्र आर्थिक विकास ने उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख इंजन, महत्वपूर्ण बाज़ार और निवेश के स्रोत बना दिया है। वैश्विक मामलों के प्रबंधन में उनके महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव को नज़रअंदाज़ करना असंभव हो गया है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता को उजागर किया है। व्यवस्था को स्थिर करने और सुधार को गति देने के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण की बड़ी, गतिशील अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकता थी। इसने एक अनूठे अवसर का सृजन किया। अंत में, दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) तथा ब्रिक्स और आईबीएसए जैसे दक्षिण ी समूहों के उदय ने विश्व मंच पर उनकी सामूहिक आवाज़ और मोल–भाव करने की शक्ति में वृद्धि करते हुए रणनीतिक समन्वय का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

इस संबंध में भारत के वैश्विक नेतृत्व का मूल आधार वैश्विक शासन की प्राचीन संरचनाओं में सुधार के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता है। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ–साथ बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) का वर्तमान ढांचा 21वीं सदी की आर्थिक वास्तविकताओं और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने में प्रायः विफल रहा है। भारत इन संस्थाओं को जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और वैश्विक असमानता की चुनौतियों के प्रति अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली, लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बनाए जाने की हिमायत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख

त्रिकोणीय सहयोग पर विचार–मंथन सत्र में विख्यात वक्ता

मंचों का रणनीतिक रूप से लाभ उठाता रहा है। जी–20 की सफल अध्यक्षता इसका प्रमाण है, जिसने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद किया और वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने के उच्च पटल पर उनकी चिंताओं को दृढ़ता से रखा। भविष्य पर गौर करें, तो 2026 में भारत की आगामी ब्रिक्स अध्यक्षता इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रस्तुत करती है, जो कोटा हिस्सेदारी, मताधिकार और विरासत संस्थानों के संचालन संबंधी दायित्वों में ठोस सुधारों पर जोर देती है। इन बड़े समूहों के साथ–साथ, आईबीएसए (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) जैसे गतिशील गठबंधन समान विचारधारा वाली दक्षिणी शक्तियों के लिए रणनीति का समन्वय करने और वैश्विक शासन में सुधार के लिए आम सहमति बनाने हेतु महत्वपूर्ण मंच का कार्य करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बहुपक्षीय प्रणाली उद्देश्य के लिए उपयुक्त है और सभी देशों के लिए अपने वादों को पूरा करने में सक्षम है।

ग्लोबल साउथ का उत्थान और भारत का नेतृत्व

ग्लोबल साउथ का आर्थिक उत्थान 21वीं सदी की महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक दास्तान है। हालांकि, भारतीय नेतृत्व का यह मानना है कि आर्थिक प्रभाव को रचनात्मक एजेंडा–निर्धारण शक्ति में परिवर्तित किया जाना चाहिए। भारत की भूमिका एक सेतु और एक प्रकाश स्तंभ की है: ब्रिक्स और आईबीएसए जैसे मंचों के माध्यम से रणनीतिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए वसुधैव कुटुम्बकम (समूचा विश्व एक परिवार है) के अपने सभ्यतागत मूल्यों का लाभ उठाते हुए, भारत वैश्विक चुनौतियों के व्यावहारिक समाधानों को आगे बढ़ा रहा है।

भारत का मॉडल विलक्षण है। यह अतीत के पितृसत्तात्मक परिप्रेक्ष्यों को नकारता है और इसके बजाय गरिमा, पारस्परिक सम्मान और साझा नियति पर आधारित साझेदारी का मॉडल प्रस्तुत करता है। यह एसएससी के कठोर अभ्यास के माध्यम से कार्यान्वित होता है, जहां विकास से संबंधित भारत की विरासत, जिसे 1983 से आरआईएस द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, को वैश्विक जन कल्याण के लिए साझा किया जाता है। यह कूटनीतिक दावा भर नहीं है; यह एक नैतिक शासन संरचना को लागू करने की प्रक्रिया है, जो मानव–केंद्रित विकास को प्राथमिकता देती है। यह प्रतिबद्धता हमारी पहलों द्वारा स्पष्ट होती है जो स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवीन समाधानों पर विचार–मंथन के लिए ग्लोबल साउथ के हितधारकों को एक साथ लाती हैं। ये कार्यशालाएं भारत और उसके साझेदारों की सफल प्रमुख योजनाओं को अपनाया जाना और साझा चुनौतियों के समाधान` के लिए उन्हें दोहराया जाना सुनिश्चित करते हुए विस्तारित किए जाने योग्य समाधानों के संग्रह को संकलित करने के मंच के रूप में कार्य करती हैं।

त्रिकोणीय सहयोग: वैश्विक भलाई के लिए रणनीतिक केंद्र के रूप में भारत

टीआरसी ने विकास सहयोग के परिदृश्य में रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि यह एसएससी की शक्तियों को पारंपरिक दानदाताओं या बहुपक्षीय एजेंसियों के संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है। पूरी तरह विकासशील देशों के बीच आदान–प्रदान पर निर्भर रहने वाले एसएससी के विपरीत, टीआरसी परियोजनाओं के विस्तार, उन्नत तकनीक तक पहुंच और व्यापक वित्त पोषण को सक्षम बनाता है। यह मॉडल समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देते हुए क्षमता संबंधी खामियों को मिटाता है। भारत ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षमता निर्माण, अवसंरचना, स्वास्थ्य और डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के साथ–साथ यूएनडीपी जैसे संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से टीआरसी का रणनीतिक लाभ उठाया है। इसे ध्यान में रखते हुए, आरआईएस ने इन मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए दो प्रमुख सत्र आयोजित किए। एक विचार–मंथन सत्र ''त्रिकोणीय सहयोग: नए तौर–तरीके और नई उम्मीद'' विषय पर आयोजित किया गया। यह सत्र त्रिकोणीय सहयोग के संबंध में संचालित किए जा रहे आरआईएस–जीआईजेड अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग था और इसका उद्देश्य विकास में सहयोग देने वाली एजेंसियों, थिंक टैंक और सिविल सोसायटी संगठनों सहित त्रिकोणीय सहयोग के विभिन्न प्रतिभागियों के बीच इंटरैक्टिव और स्पष्ट विचार–विमर्श को बढ़ावा देना था।

इसी क्रम में, आरआईएस ने भारत और पड़ोसी देशों – नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश–से आए दक्षिणी विचारकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किया। इन प्रतिभागियों में शिक्षा जगत, विकास कार्यों से जुड़े कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और सहयोग के उभरते क्षेत्र में शामिल अन्य प्रमुख हितधारकों सहित एक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व था। सत्रों के दौरान महिला सशक्तिकरण में त्रिकोणीय सहयोग की

वित्तीय समावेशन और नवाचार पर भारत के स्वयं के सफल प्रयासों पर विचार–मंथन सत्र

भूमिका, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में खाद्य मानकों के निहितार्थ और त्रिकोणीय सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियां जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। अफ्रीका में त्रिकोणीय सहयोग के लिए भारत–जर्मनी साझेदारी पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इस केस स्टडी में ऐसे सहकारी उपक्रमों की परिचालन गतिशीलता और प्रभाव को दर्शाया गया।

लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) को वैश्विक लोकाचार में शामिल करना

भारत के दूरदर्शी नेतृत्व का आधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्व ारा प्रस्तुत अवधारणा–लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) का वैश्विक स्तर पर प्रचार है। लाइफ, स्थिरता को विशुद्ध रूप से सरकार–दर–सरकार नीतिगत ढांचे से आगे बढ़ाकर जन–केंद्रित वैश्विक मुहिम में बदलती है। यह पर्यावरणीय कार्यों को व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार से जोड़कर उन्हें नैतिक बनाती है, जिससे स्थिरता एक दूरस्थ प्रोटोकॉल के बजाय रोजमर्रा का व्यवहार बन जाती है।

हम लाइफ के सिद्धांतों को विकास से संबंधित अपने सहयोग के प्रयासों में सीधे तौर पर जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल परिवर्तन से संबंधित हमारे विचार–विमर्श, न्यायसंगत डिजिटल पहुंच और स्थायी जीवनशैली को सशक्त बनाने वाले वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार, स्थायी कृषि पर हमारा कार्य, प्रकृति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके लाइफ के अनुरूप कृषि–पारिस्थितिकीय प्रथाओं को बढ़ावा देता है। यह दर्शन हमारे अनुसंधान का केंद्रबिंदु है और यह आगामी क्षमता–निर्माण कार्यक्रमों का प्रमुख स्तंभ होगा, जो ग्लोबल साउथ के प्रतिभागियों को एक ऐसी जीवनशैली का दूत बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जो सांस्कृतिक रूप से उनकी जड़ों से जुड़ी होने के साथ ही साथ विश्व के प्रति उत्तरदायी भी हों।

आगे की राहः भविष्य की रूपरेखा तैयार करना

भविष्य पर गौर करें, तो भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और भी प्रभावशाली होती जाएगी और आरआईएस इस यात्रा में बौद्धिक नेतृत्व के लिए तैयार है।

- ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026ः भारत अपनी अध्यक्षता का उपयोग वैश्विक शासन और बहुपक्षीय संस्थानों में तत्काल सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए करेगा, और ऐसी प्रणालियों का समर्थन करेगा, जो अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, उत्तरदायी और न्यायसंगत हों। आरआईएस व्यापक आउटरीच और अनुसंधान के माध्यम से इस संवाद को आगे बढ़ाएगा।
- ज्ञान की संप्रभुताः हम दुनिया को अपनी कहानी अपनी आवाज़ में सुनाना सुनिश्चित करते हुए ग्लोबल साउथ के विचारक समूहों में ठोस ज्ञान और नवाचार नेटवर्क बनाने के प्रयासों में और तेज़ी लाएंगे – इसका प्रमाण हमारा स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी में प्रकाशन करना है। यह सीधे तौर पर अंग्रेजी भाषी दुनिया से परे समाधान

साझा करने के हमारे मिशन को आगे बढ़ाता है, जैसा कि ब्यूनस आयर्स में डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू के स्पेनिश संस्करण के सफल विमोचन में देखा गया।

- सतत विकास लक्ष्य और नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली : वैश्विक सहयोग के साथ–साथ स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल समाधानों को मज़बूती प्रदान करने के हमारे प्रयास यह दर्शाते रहेंगे कि भारत के नैतिक शासन मॉडल किस प्रकार सुदृढ़ता और न्यायसंगतता स्थापित कर सकते हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े निरंतर समन्वित प्रयास शामिल हैं, जो कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं में मजबूती लाने में सहायता करते हैं और हमारी अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं में साझा की गई सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाते हैं।
- भविष्य के लिए क्षमताः आरआईएस में विज्ञान कूटनीति, सतत विकास और दक्षिण–दक्षिण सहयोग जैसे विषयों पर आईटीईसी समर्थित पाठ्यक्रमों का पुनरारम्भ विकासशील देशों के नेताओं की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करेगा, जो लाइफ और नैतिक साझेदारी के सिद्धांतों से प्रेरित होंगे।

अंत में, भारत केवल वैश्विक परिवर्तन की धाराओं को ही पार नहीं रहा है; बल्कि एक नया मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली, सतत विकास और वास्तविक साझेदारी मॉडल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से –जो संस्थागत सुधार और ठोस, समाधान–आधारित सहयोग की वकालत के माध्यम से प्रदर्शित होती है–भारत दुनिया को सहयोग का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान कर रहा है जो अधिक मानवीय, समावेशी और हमारे समय की गहन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।

अर्जेंटीना में डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू के स्पेनिश संस्करण का विमोचन।

आरआईएस द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

- 24 अप्रैल, 2024 को ''त्रिकोणीय सहयोगः नए तौर–तरीके और नई उम्मीद'' पर विचार–मंथन सत्र।
- 1 जून, 2024 को कार्य के भविष्य के लिए विद्यालयी शिक्षा को आकार देने पर सत्र।
- 16 अप्रैल 2024 को ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत की जी–20 अध्यक्षता पर संगोष्ठी।
- 2 अगस्त, 2024 को सीईओ स्पीक्स श्रृंखलाः थिंक टैंकों के बीच सामंजस्य।
- 9 अगस्त, 2024 को सीईओ स्पीक्स श्रृंखलाः ग्लोबल साउथ में विकास को आगे बढ़ाना।
- 19–20 सितंबर 2024 को त्रिकोणीय सहयोग के ज़रिए सेतु बनाने पर क्षमता निर्माण से संबंधित कार्यक्रम।
- 30 अगस्त 2024 को ग्लोबल साउथ के लिए कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला।
- 16 दिसंबर 2025 को जी–20 की अध्यक्षता कर चुके ग्लोबल साउथ के देशों की ओर से मार्गदर्शन : दक्षिण अफ्रीका के लिए संदेश विषय पर वेबिनार।
- 15 नवंबर 2025 को डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू के स्पेनिश संस्करण का विमोचन।
- 22 जनवरी 2025 को ग्लोबल साउथ में सतत कृषि और कृषि–पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण पर कार्यशाला।
- 28 फरवरी 2025 को विकास सहयोगः ग्लोबल साउथ का परिप्रेक्ष्य विषय पर वेबिनार।
- 8 अगस्त 2024 को टेलीहेल्थ– परिवर्तनकारी डिजिटल स्वास्थ्य समाधान पर कार्यशाला।

प्रमुख प्रकाशन

पत्रिकाएं

- डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू खंड 7 अंक 1 जनवरी–मार्च 2024
- डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू (स्पेनिश भाषा में विशेषांक)
- डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू खंड 7 अंक 2 अप्रैल–जून 2024
- डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू खंड 7 अंक 3 एवं 4 जुलाई–दिसम्बर 2024
- जी–20 डाइजेस्ट

चर्चा पत्र

- # 301: ग्लोबल साउथ शुड ऐम एट अ कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज फॉर एड्रेसिंग इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज नीलिमेश बरुआ द्वारा

लोकप्रिय लेख

- ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन : डेवेलपमेंट कॉम्पैक्ट शुड बी सेंट्रल टू द पैक्ट ऑफ द फ्यूचर। डॉ. सब्यसाची साहा, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस इंडियाब्लूम्स, 19 अगस्त, 2024

2 सतत विकास, लाइफ (LiFE) और हरित विकास

सतत विकास का परिप्रेक्ष्य सभी आयामों में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए पारिस्थितिकीय सीमाओं का ध्यान रखने वाली, अंतर–पीढ़ीगत न्यायसंगतता सुनिश्चित करने वाली तथा नवाचार, उद्यमिता, शहरीकरण जैसे अर्थव्यवस्था के विकास इंजनों को बढ़ावा देने वाली संतुलित प्रगति पर जोर देता है। सतत विकास से संबंधित एजेंडा 2030 को अपनाना बहुपक्षवाद की सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था, जब सभी देश सार्वभौमिक, परस्पर सम्बद्ध और अविभाज्य प्रकृति के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के एक सामान्य ढांचे पर काम करने पर सहमत हुए। व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी सतत विकास के एजेंडे

के मुख्य घटक हैं। ये घटक – जिन्हें कार्यान्वयन के साधन के रूप में पहचाना जाता है – गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और औद्योगीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, एक दशक के बाद, जब वैश्विक समुदाय महामारी, संघर्ष और खंडित वैश्वीकरण की मौजूदा चुनौतियों से जूझ रहा है, इस निर्बलता के कारण एसडीजी हासिल करने के लिए जरूरी कार्यान्वयन के साधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे बंटे हुए विश्व में, जहां राष्ट्रीय सरकारें अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रही हैं और अपने स्वार्थ सिद्ध करने पर अधिक ध्यान दे रही हैं, सामूहिक विकास और साझा समृद्धि के महत्व पर फिर से जोर देना अनिवार्य हो गया है।

आरआईएस में सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता आर्थिक प्रगति को पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समावेशन के साथ एकीकृत करने वाले एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। यह दृष्टिकोण दो परस्पर संबद्ध स्तंभों के माध्यम से व्यक्त होता है: पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ़) और हरित विकास, जो मिलकर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप राष्ट्रीय और वैश्विक विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने की रूपरेखा प्रदान करते हैं। आरआईएस स्थिरता को एक स्वतंत्र नीति के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक नियोजन, नवाचार प्रणालियों, बुनियादी ढांचे के डिज़ाइन और व्यापार रणनीतियों में अंतर्निहित एक अंतर्संबंधित सूत्र के रूप में देखता है।

लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) पहल उत्पादन और उपभोग के पैटर्न का रुख कम कार्बन, संसाधन–कुशल प्रणालियों की दिशा में मोड़ने के लिए स्थानीय संदर्भ पर आधारित और वैश्विक रूप से प्रासंगिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। 2023 की यूएनईपी उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी दुनिया के औद्योगीकरण ने वर्ष 1800–2021 के बीच ऐतिहासिक कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन में 80 प्रतिशत का योगदान दिया। विकास का यह मॉडल न केवल अनुचित है, बल्कि ग्रह के लिए अव्यवहारिक भी है। जैसे–जैसे ग्लोबल साउथ के देश तीव्र गति से आर्थिक विकास कर रहे हैं, हमारे द्वारा उसी रास्ते के जोखिम दोहराए जाने का जोखिम है। बढ़ती आमदनी अक्सर पश्चिम की नकल करते हुए कार्बन की भारी खपत और जीवनशैली में बदलाव लाती है। 2015 में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स में अपने लेख में कहा था कि ''मुट्ठी भर लोगों की जीवनशैली विकास के प्रथम पायदान पर खड़े लोगों के अवसरों को बाधित न करें।'' इस बात ने वैश्विक स्तर पर मौजूद अत्यधिक उपभाग और अस्थायी जीवनशैलियों की चुनौतियों को पहली बार स्पष्ट रूप से उजागर किया, जिसका उल्लेख पेरिस समझौते के मूलपाठ में भी किया गया। लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) की अवधारणा, जिसे 2021 में ग्लासगो में सीओपी 26 के दौरान पहली बार प्रस्तुत किया गया था, भारत के जी–20 एजेंडे का भी एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी। वाराणसी, भारत में जी–20 के सदस्य देशों के विकास मंत्रियों ने सतत विकास के लिए जीवनशैलियों से संबंधित नौ उच्च–स्तरीय सिद्धांतों (एचएलपी) पर सहमति व्यक्त की। जी–20 नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी के विकास, उपयोग और प्रसार के माध्यम से इन एचएलपी के कार्यान्वयन का समर्थन किया।

लाइफ और हरित विकास: क्या हम विकास के एक नए परिप्रेक्ष्य को आकार दे सकते हैं?

आरआईएस की संरचना के भीतर लाइफ और हरित विकास, लाइफ अर्थव्यवस्था के एक सुसंगत ढांचे के रूप में विकसित हुआ है। इस बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में पांच प्रमुख पहलू शामिल हैं:

- सतत उपभोग और उत्पादन (एससीपी) की परिपाटियों को बढ़ावा देना। लाइफ मौजूदा असमानताओं को दूर करते हुए सतत उपभोग को मूल में रखती है।
- प्राकृतिक पूंजी, बुनियादी जरूरतों, असमानताओं और नकारात्मक पर्यावरणीय बाह्यताओं जैसे कारकों को शामिल करते हुए जीडीपी से परे कल्याण का आकलन करना।
- प्रयासों के स्थानीयकरण को बढ़ावा देते हुए, सतत और न्यायसंगत विकास के लिए सामाजिक उद्यमों और सामुदायिक भागीदारी को अपनाना।
- ग्लोबल साउथ के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास वित्त को पक्षपात रहित और नैतिक विचारों की ओर पुनर्निर्देशित करना।
- प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक शासन प्रणाली को मजबूती प्रदान करते हुए नैतिक और मूल्य–आधारित आर्थिक प्रणालियों को मुख्यधारा में लाना।

आरआईएस हरित विकास और लाइफ को विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत रखता है, जो उत्पादन और उपभोग की अस्थिर परिपाटियों का विरोध करता है। यह

सभी के लिए एक समान समाधान के मॉडलों का विरोध करता है और इसके बजाय ग्लोबल साउथ के संदर्भ में विशिष्ट समाधानों को प्राथमिकता देता है। वर्ष के दौरान, आरआईएस सतत विकास पर नीतिगत चर्चा को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के संवादों, कार्यशालाओं और सहयोगात्मक पहलों में संलग्न रहा।

इन आयोजनों ने पारिस्थितिक और सांस्कृतिक संदर्भों को पर्याप्त महत्व दिए बिना विकास को प्राथमिकता देने वाले रूढ़िवादी आर्थिक मॉडलों को चुनौती देते हुए ग्लोबल साउथ के लिए विकास के नए परिप्रेक्ष्यों पर बहस को आगे बढ़ाया। लाइफ पहल को विकास के ऐसे मार्गों की नए सिरे से परिकल्पना करने में घरेलू योगदानकर्ता के रूप में रेखांकित किया गया, जो कम कार्बन वाली और सामाजिक रूप से समावेशी दोनों हैं। ऐसी क्षेत्रीय रणनीतियां बनाने पर ज़ोर दिया गया, जो स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय शासन संरचनाओं का लाभ उठाएं तथा बाहरी मॉडलों और पूंजी प्रवाह पर निर्भरता में कमी लाएं। सत्रों और सम्मेलनों के विषयगत अन्वेषणों में असमानता, कार्य का भविष्य, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की भूमिका और सामाजिक एवं पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ आर्थिक विकास का अंतर्संबंध शामिल रहा।

वर्ष के दौरान नीतिगत संवादों में प्रगति के प्राथमिक मापदंड के रूप में जीडीपी से आगे बढ़ने का आह्वान किया गया, और ऐसे कल्याण संकेतकों का समर्थन किया गया, जो पारिस्थितिक स्वास्थ्य, सामुदायिक दृढ़ता और मानव पूंजी को समाहित करते हों। विचार–विमर्श के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जलवायु परिवर्तन, असमानता और गरीबी की चुनौतियों से निपटने के लिए केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ–साथ कौशल विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन की दिशा में लक्षित हस्तक्षेप भी आवश्यक हैं।

असमानता और सतत विकास लक्ष्यों के बारे में

असमानता, आर्थिक विकास और समावेशन परस्पर संबद्ध हैं और एक–दूसरे को सशक्त करते हैं। ये सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का आधार भी हैं, जो एक व्यापक विषय के रूप में सभी विषयों में समान रूप से शामिल है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 आर्थिक असमानता के रुझानों, उनके चालकों और निहितार्थों के बारे में समझ प्रदान करती है।

प्रोफेसर शोभित माथुर, कुलपति, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी; डॉ. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार; और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस

रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक धन संबंधी असमानताएं, आय की असमानताओं से भी अधिक स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक आबादी के सबसे गरीब 50 प्रतिशत लोगों के पास कुल संपत्ति का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोगों का 76 प्रतिशत संपत्ति पर नियंत्रण है। इसी प्रकार, सबसे धनी 10 प्रतिशत व्यक्तियों को वैश्विक आय का 52 प्रतिशत प्राप्त होता है, जबकि सबसे गरीब आधी आबादी के लोग केवल 8.5 प्रतिशत आमदनी कमाते हैं। भारत में, धनी लोगों पर कर लगाने की बहस इस आशंका के साथ शुरु होती है कि ऐसे उपाय आर्थिक विकास को धीमा कर सकते हैं और पूंजी का बाहर जाना शुरु हो सकता है, जो "अनपेक्षित परिणामों के नियम" का एक उदाहरण है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, समावेशी विकास का सही मापदंड केवल असमानता दूर करने के बजाय गरीबी उन्मूलन में निहित है।

एक ओर, मानव विकास में निवेश करने और लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए धन की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए प्रायः सशक्त पुनर्वितरण नीतियों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, अत्यधिक वित्तीयकरण और पूंजी के निर्बाध प्रवाह के दौर में अति–धनी लोगों पर कर लगाने से एक क्लासिक गेम–थ्योरी की दुविधा उत्पन्न होती हैः जितने अधिक देश वैश्विक कर व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध जताते हैं, किसी एक

देश के लिए इससे बाहर निकलने और पूंजी पलायन को आकर्षित करने का प्रोत्साहन उतना ही अधिक होता है। यह पहेली एक वैश्वीकृत दुनिया में आर्थिक व्यावहारिकता के साथ समता के संतुलन की कठिनाई को रेखांकित करती है।

बुनियादी ढांचे के स्पिलओवर प्रभाव और हरित वित्त

आरआईएस के कार्य का एक प्रमुख क्षेत्र बुनियादी ढांचे की दोहरी भूमिका– आर्थिक गतिविधि के चालक के रूप में तथा प्राकृतिक व भौतिक पूंजी के बीच एक कड़ी के रूप में और क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर बुनियादी ढांचे के स्पिलओवर प्रभाव की पड़ताल करना रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास से, विशेष रूप से बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय आर्थिक लाभ होते हैं। इस तरह के निवेश न केवल तत्काल रोजगार के अवसरों का सृजन करते हैं और नए व्यवसायों की स्थापना को बढ़ावा देते हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण कर राजस्व में भी वृद्धि करते हैं। इन परियोजनाओं के स्पिलओवर प्रभाव प्रत्यक्ष परिणामों से बढ़कर होते हैं; ये संपत्ति का बढ़ाते हैं और कॉर्पोरेट विकास को प्रोत्साहन देते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में उत्थान की बदौलत स्थानीय, कॉर्पोरेट और अन्य प्रकार के कराधान में वृद्धि होती है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडीज के अनुभवजन्य साक्ष्यों ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) ढांचे की अतीत की कमियों को दर्शाया है, जिन्होंने ढांचागत परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सामान्यतः बाधा डाली है। सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच जोखिम–साझा करने में चुनौतियों, दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों और नियामक अनिश्चितताओं की पहचान महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में की गई है। इन कमियों को दूर करने के लिए अधिक पारदर्शी जोखिम आवंटन, मजबूत नियामक ढांचे और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन की रणनीतियों की आवश्यकता है।

बुनियादी ढांचे के विस्तार और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करने में हरित वित्त पर विमर्श महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरकर सामने आया है। पर्यावरण से संबंधित सरोकार बुनियादी ढांचे में निवेश का अभिन्न अंग रहे हैं। पारदर्शी जोखिम साझेदारी ढांचे को अपनाना, कार्बन कर व्यवस्था लागू करना, प्राकृतिक पूंजी के नुकसान का आकलन करना, नियामक तंत्रों को मजबूत बनाना, और मिश्रित वित्त जैसे नवीन वित्त पोषण साधनों को

अवसंरचना और वित्त पर संगोष्ठी में श्री सुमन बैरी, उपाध्यक्ष नीति आयोग

लागू करना, पारिस्थितिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हुए निजी निवेश को आकर्षित करने के आवश्यक उपाय माने गए हैं। इन उपायों से हरित विकास के सिद्धांतों को बुनियादी ढांचे के विकास के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है।

क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से एसडीजी के ढांचे को सुदृढ़ बनाना

आरआईएस विशेषकर ग्लोबल साउथ में एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखे हुए है। इस वर्ष की विशेषता जी–20, एसडीजी और सार्वजनिक नीति पर केंद्रित सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ रही, जिनका उद्देश्य ज्ञान के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना और देश के भीतर राज्य, जिला, नगर या ग्राम स्तरों पर टिकाऊ प्रथाओं के दस्तावेज़ीकरण को सुगम बनाना था। इन पहलों ने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को वैश्विक स्थिरता ढांचों को स्थानीय संदर्भों के अनुकूल बनाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इन संवादों में जलवायु अनुकूलन, जैव विविधता संरक्षण और दक्षिण–दक्षिण सहयोग का महत्व प्रमुखता से सामने आया, जो आरआईएस के इस दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है कि वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों को अनिवार्य रूप से क्षेत्र–विशिष्ट कार्य योजनाओं में परिवर्तित किया जाना चाहिए। विमर्श में इस बात की भी पुष्टि हुई कि एसडीजी प्राप्त करने के लिए सरकारों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी महत्वपूर्ण है।

सतत विकास ढांचे के भीतर, आरआईएस ने न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने में मानव पूंजी की भूमिका पर भी गौर किया। समर्पित सत्रों में कार्यबल वितरण, कौशल अंतराल और नियामक ढांचों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों को मजबूती प्रदान करने की रणनीतियों की पड़ताल की गई। स्वास्थ्य प्रणालियों को बदलती जनसांख्यिकीय और महामारी विज्ञान संबंधी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए चर्चाओं में व्यापक क्षमता निर्माण, शिक्षा सुधारों और बेहतर सेवा प्रदाता तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। वैश्विक संदर्भ में, डब्ल्यूएचओ के अनुमानों में इंगित किया गया कि 2013 में आवश्यकता से कम स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के कुल मामलों का 99 प्रतिशत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पाया गया। 2030 तक, उच्च और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मांग लगभग 33.3 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आपूर्ति पक्ष के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए अनेक रणनीतिक विकल्पों की आवश्यकता है। इनमें मानव संसाधनों के लिए समग्र क्षमता निर्माण, संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायियों के लिए नियामक ढांचे को बढ़ाना, स्वास्थ्य से संबंधित पेशेवर शिक्षा में सुधारों को लागू करना और सेवा प्रदायगी करने वाले तंत्रों को अनुकूलित करना शामिल था।

इस कार्य में विशेषकर संसाधन–विहीन परिस्थितियों में, मातृ देखभाल और टीकाकरण में सुधार लाने में, डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका की जांच भी शामिल थी। पूरे ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों के संबंध में हुए अध्ययनों ने दर्शाया कि इलेक्ट्रॉनिक टीकाकरण रजिस्ट्री, ओरल वैक्सीन और समावेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे नवाचार सामुदायिक सहभागिता व स्थानीय ज्ञान प्रणालियों संग एकीकृत होने पर स्वास्थ्य परिणामों में सुधार ला सकते हैं।

भविष्य के अनुसंधान क्षेत्र

इस वर्ष सतत विकास, लाइफ और हरित विकास के क्षेत्र में आरआईएस के कार्य को इसके प्रकाशनों के माध्यम से और आगे बढ़ाया गया। अनुसंधान के इन परिणामों और नीतिगत कार्यों के माध्यम से आरआईएस ने इस विषय पर चर्चा जारी रखी कि किस प्रकार सतत विकास को स्थानीय स्तर पर आधारित, वैश्विक रूप से प्रासंगिक और जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समानता और आर्थिक सुदृढ़ता की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। आगामी वर्ष में आरआईएस लाइफ की अवधारणा और स्थानीय विकास को वैश्विक स्थायित्व से जुड़ी आवश्यकताओं के साथ आगे बढ़ाने के नवोन्मेषी विचार को स्थापित करने के तरीके के संबंध में अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा। हम स्थिरता से संबंधित परिवर्तनों का समावेशी और न्यायसंगत होना सुनिश्चित करने पर बल देते हुए औद्योगिक नीति, नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम और सामुदायिक स्तर की पहलों में लाइफ सिद्धांतों के एकीकरण की संभावनाएं तलाश करेंगे।

असमानता, आर्थिक विकास और समावेशन से संबंधित कार्यक्रम में प्रोफेसर थॉमस पिकेटी, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

आरआईएस द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

- 9 मई 2024 को काम के भविष्य की खोज पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 3 जून 2024 को सीईओ स्पीक्स सत्र : वैश्विक गतिशीलता का अन्वेषण।
- 29 जुलाई 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर स्पिलओवर हरित वित्त : सतत विकास की ओर विषय पर संगोष्ठी।
- 12 अगस्त 2024 को सहयोग को बढ़ावा देना: जी–20, एसडीजी और सार्वजनिक नीति पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला।
- 13 दिसंबर 2024 को असमानता, आर्थिक विकास और समावेश पर पैनल चर्चा।
- 14 दिसंबर 2024 को मीडिया और विकास अर्थव्यवस्था पर संगोष्ठी।
- 30 जनवरी 2025 को वैकल्पिक विकास परिप्रेक्ष्य पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 24 जुलाई 2024 को सीईओ स्पीक्स सत्र : स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन: भारत में स्वास्थ्य प्रणाली में बदलाव लाने के लिए रणनीतिक विकल्प।
- 19 फरवरी 2025 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाना: मातृ देखभाल और वैक्सीन डिलिवरी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना विषय पर कार्यशाला।

प्रमुख प्रकाशन

चर्चा पत्र

- #302: बियॉन्ड लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट: लर्निंग्स फ्रॉम द दयालबाग मॉडल पमी दुआ, अर्श धीर, डी. भगवान दास, अशिता अल्लमराजू, प्रेम सेवक सुधीश, अपूर्व नारायण, सब्यसाची साहा एंड वी.बी. गुप्ता द्वारा

नीतिगत सारांश

- #111: इनेक्वालिटीज एंड डेवेलपमेंट – जी–20 एक्शन एंड यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर, डॉ. सब्यसाची साहा द्वारा
- #110: एडॉप्टिंग लाइफ ग्लोबली फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, राजदूत पूजा कपूर द्वारा

3 व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाएं और आर्थिक मजबूती : समावेशी और नवोन्मेषी भारत की ओर

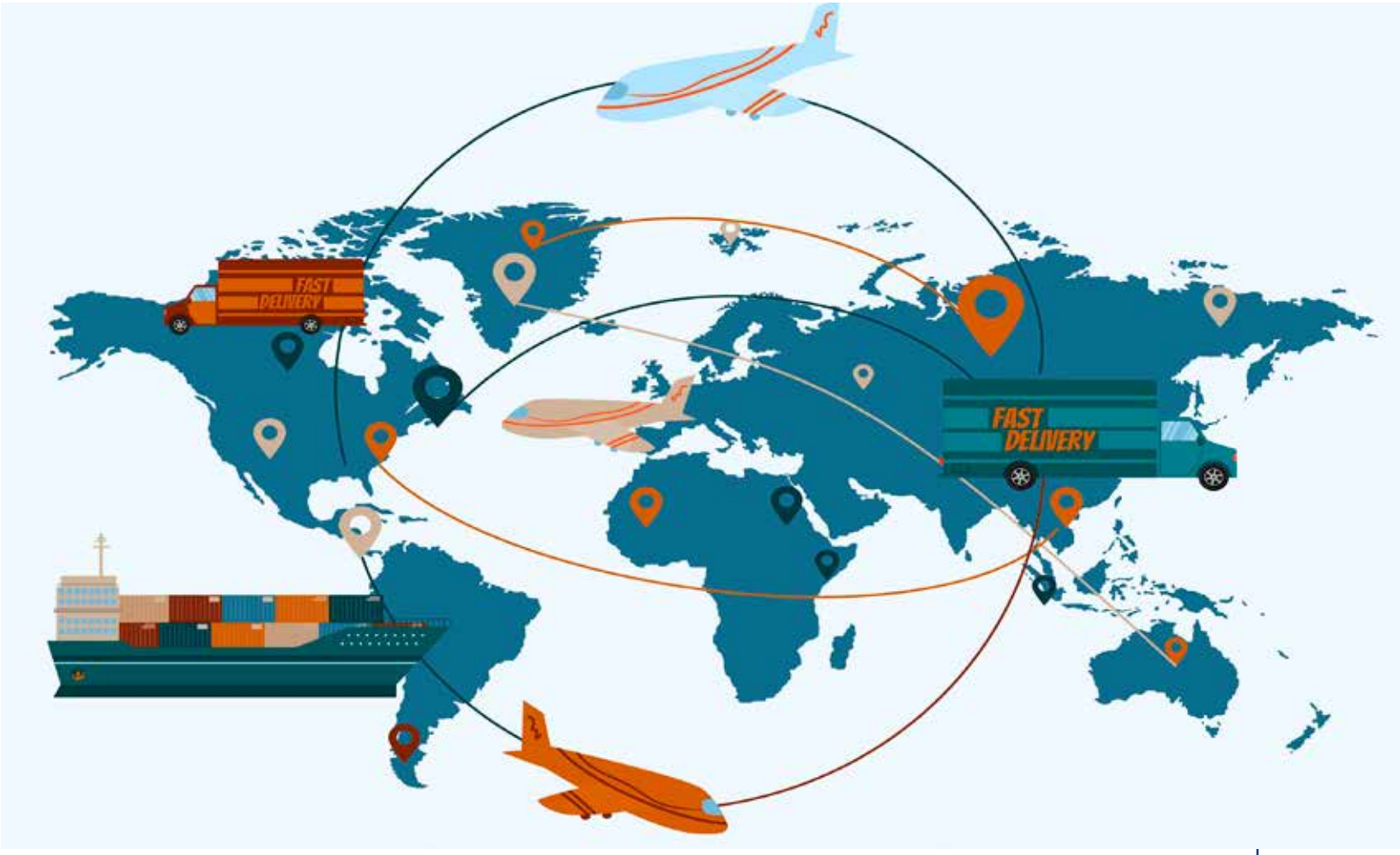

अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विकास का एक प्रमुख चालक है और इस कारण बाहरी बाजार, विशेषकर प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ उत्पन्न होने वाले व्यवधान भारत की व्यापार नीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यवधान व्यापार और निवेश प्रवाह का रुख अन्य देशों की ओर मोड़ देते हैं, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है। टैरिफ में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और सीमा पार तनाव सहित वर्तमान भू–राजनीतिक अस्थिरता–आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, आर्थिक मजबूती और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय व्यापार रणनीति को बेहतर बनाने की आवश्यकता को रेखांकित

करती है। भू–राजनीतिक उथल–पुथल के बीच ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज़ के रूप में भारत की व्यापार रणनीति द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की रूपरेखा को आकार दे रही है। 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को एक ऐसे व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो व्यापार नीति के क्षेत्रीयकरण और स्थानीयकरण को बढ़ावा दे। जैसे कि भारत विकास के अगले चरण के लिए तैयार हो रहा है, ऐसे में गति को बनाए रखने, प्रणालीगत विकास अंतराल को पाटने और आर्थिक, तकनीकी और संस्थागत कारकों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने की चुनौती बनी हुई है।

बदलती वैश्विक व्यवस्था और क्षेत्रवाद के प्रति भारत का नया दृष्टिकोण

वर्ष 2024 से, अमेरिका में नए राष्ट्रपति के सत्तारूढ़ होने के साथ ही संभावित टैरिफ वृद्धि और व्यापार युद्धों की अटकलें लगाई जाने लगीं, जिनसे विश्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक उथल–पुथल क। इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप, भारतीय निर्यात भी अमेरिकी टैरिफ वृद्धि का सामना कर रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था में तेज़ी से हो रहे बदलावों पर गौर करते हुए आरआईएस ने दिसंबर 2024 में 'व्यापार, टैरिफ और ट्रम्प' शीर्षक से एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जहां अमेरिका की व्यापारिक गतिविधियों की गतिशीलता का अन्वेषण किया गया। अमेरिका की ओर से की गई टैरिफ वृद्धि के प्रभावों का आकलन 'ट्रम्प की व्यापार नीतियों का संकटः वैश्विक आर्थिक स्थिरता' रिपोर्ट और 'वैश्विक व्यापार, ट्रम्प और भारत की भूमिका' लेख में किया गया, जिनमें ऐसे कई क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो टैरिफ वृद्धि से प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के दोहरे परिणाम हो सकते हैंः एक ओर, चीन, मेक्सिको और कनाडा जैसे प्रतिस्पर्धियों पर टैरिफ लगाने की स्थिति में वहां भारत के लिए अमेरिकी बाज़ारों से लाभ कमाने का अवसर उत्पन हो सकता है। दूसरी ओर, टैरिफ बढ़ने से भारत को बाज़ार खो देने का भी ख़तरा हो सकता है।

इस बात पर चर्चा हुई कि फार्मास्यूटिकल्स, रत्न एवं आभूषण, और झींगा जैसे क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील हैं तथा चमड़ा, कपड़ा, प्लास्टिक के बर्तन और बेस मेटल उत्पादों जैसे अन्य विनिर्माण क्षेत्रों को अमेरिकी प्रशासन द्व ारा लगाए गए टैरिफ से निपटने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। अमेरिका ने अपनी बाद की घोषणाओं में ऐसे कई क्षेत्रों को लक्षित किया है। हाल ही में, अमेरिका ने रूस से तेल का आयात करने के लिए भारत पर टैरिफ और बढ़ा दिए हैं। हालांकि भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति का बचाव किया है, लेकिन बढ़े हुए टैरिफ अमेरिकी बाजार में वरीयता मार्जिन को कम करने के साथ ही भारत की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को भी कम करेंगे। भारत के साथ संस्थागत ढांचों को सुव्यवस्थित करने के प्रयास बढ़ाते हुए व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और वित्त के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक सर्व–समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को

ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रम्प पर संगोष्ठी में विख्यात वक्ता

बेहतर बनाने के अलावा, निर्यात के लिए वैकल्पिक बाजारों की पहचान किया जाना भी आवश्यक है। ऐसे ही एक प्रयास में, भारत ने 15वें भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ किया है, जहां दोनों देशों ने मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं और अस्थिर वैश्विक शक्तियों पर निर्भरता कम करने पर ज़ोर दिया है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रवाद के प्रति भारत के नए दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यापार के माध्यम से उच्च विकास दर को बढ़ावा देना है। 'एक्सप्लोरिंग ट्रेड, जीवीसी, एंड टेक्नोलॉजी गुड्स इन इंडियाज एफटीए' नामक शोधपत्र क्षेत्रवाद की पहली लहर के दौरान मध्यवर्ती और प्रौद्योगिकी–गहन क्षेत्रों के साथ व्यापार में भारत की प्रगति का प्रयोगात्मक परीक्षण करता है। हालांकि, भारत के समग्र व्यापार घाटे को कम करने के लिए, इसे और बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए कुछ समझौतों जैसे आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए)की समीक्षा आवश्यक है, जो समावेशी विकास के लिए व्यापार सुविधा, प्रभावशीलता और उपयोग सुलभता को बढ़ाएगा, जैसा कि 'टूवर्ड्स फ्री ट्रेड इन गुड्स थ्रू एआईटीआईजीए' आलेख में रेखांकित किया गया है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को गहन बनाने के लिए जानी जाने वाली भारत की क्षेत्रवाद की दूसरी लहर ने क्षेत्रीय कवरेज का विस्तार कुछ डब्ल्यूटीओ–प्लस और डब्ल्यूटीओ एक्स्ट्रा मुद्दों तक कर दिया है। सार्वजनिक खरीद, पर्यावरण संबंधी प्रावधान, श्रम मानक, डेटा संरक्षण आदि जैसे क्षेत्रों को भारत–यूएई सीईपीए, भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, भारत–यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता, भारत–ब्रिटेन एफटीए और हिंद–प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) जैसे व्यापार समझौतों में शामिल किया गया है।

ब्रिटेन के साथ हाल के एफटीए में, दोनों देशों ने व्यापार और जेंडर, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), और सामाजिक सुरक्षा समझौतों जैसे विशेष प्रावधान शामिल किए हैं। आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया, चिली, पेरू और अन्य देशों के साथ मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा/उन्नयन करते समय भारत की द्विपक्षीय व्यापार नीति के इन नए क्षेत्रों पर भी चर्चा की जा सकती है। आरआईएस द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तरों पर क्षेत्रीय इनपुट के साथ–साथ पूर्व–व्यवहार्यता और संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययनों के माध्यम से कई संभावित व्यापार समझौतों के मूल्यांकन में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य सरकारी निकायों के साथ निरंतर कार्य कर रहा है।

घरेलू सुधारों के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं को विकसित करना

वैश्विक कृषि व्यापार में वृद्धि भारत के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को विकसित करने और विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण प्रतिभागी के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करती है। ग्लोबल साउथ में कृषि व्यापार को संचालित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अंतर–उद्योग व्यापार है। प्रसंस्कृत और गैर–प्रसंस्कृत दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के साथ, बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) क्षेत्र कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के विकास और उपभोग के लिए महत्वपूर्ण बाजार प्रस्तुत करता है। हालांकि भारत के पास कृषि क्षेत्र में व्यापार अधिशेष है, जैसा कि 'एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड पॉलिसी रिस्पॉन्सेसः लीवरेजिंग न्यू अपॉर्च्यूनिटीज एंड एड्रेसिंग पर्सिस्टिंग चैलेंज' नामक शोधपत्र में विस्तार से चर्चा की गई है, फिर भी इसमें अप्रयुक्त क्षमता भी है जिसका उपयोग इस क्षेत्र में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं की पहचान और स्थापना के माध्यम से किया जा सकता है। आरआईएस बिम्सटेक ढांचे के भीतर कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं की संभावनाओं का मूल्यांकन करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रारंभिक परिणाम दर्शाते है कि फलों और सब्जियों तथा प्रसंस्कृत खाद्य उप–क्षेत्रों का बिम्सटेक में समग्र कृषि क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक अंतर–क्षेत्रीय व्यापार है।

21वीं सदी के समझौते के प्रति इसकी तैयारी के स्पष्ट प्रमाण हैं। हालांकि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के बारे में, विशेषकर विकासशील देशों पर इसके विकासात्मक प्रभाव को लेकर भारत का दृष्टिकोण अलग है, जैसा कि शोधपत्रों – 'इंटरमिंगलिंग ऑफ ट्रेड एंड एनवायर्नमेंट पॉलिसीः इम्प्लीकेशंस ऑफ ईयू–सीबीएएम ऑन इंडिया एंड एलडीसी' और अखबारों के लेखों – 'कार्बन टैक्सेज डब्ल्यूटीओ टेस्ट एंड अपॉर्च्यूनिटीज फॉर बेटर इंडिया–ईयू ट्रेड टर्म्स' और 'ट्रम्प 2–0ः फेट ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी अमिड शिफ्टिंग ग्लोबल प्रायोरिटीज' में इंगित किया गया है, यह उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के माध्यम से हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सुव्यवस्थित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यापार की लागत कम करने और व्यापार सुविधा उपायों में सुधार लाने के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने की

दिशा में लगातार काम कर रहा है। राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना ने व्यापार सुविधा समझौते के लेखों से संबंधित अधिकांश गतिविधियों को रेखांकित करने में मदद की है, जिसके लाभों पर सीईओ स्पीक्स श्रृंखला में डॉ. जोशुआ एबेनेज़र, प्रधान सलाहकार नुकोव फैसिली–ट्रेड, भारत के साथ भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और ई–संचित जैसी अन्य पहलों ने सीमा पार व्यापार में सुधार किया है, जिससे व्यापार करने में आसानी हुई है और ये देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

खनिज और विनिर्माण क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और व्यापक दोनों स्तरों पर प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत फार्मास्यूटिकल्स, ईवी, सेमीकंडक्टर और वस्त्र पर क्षेत्र–विशिष्ट घरेलू नीतियां भारत को दुनिया में एक विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने हेतु मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए लागू की जाती हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में, सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के माध्यम से खनिज आयात पर भारी निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिसकी चर्चा 'स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ मिनरल सिक्युरिटीः फ्रॉम एफर्ट्स टू एक्शन' और 'सिक्योरिंग सप्लाई ऑफ निश मिनरल्स क्रूशियल' में भी की गई है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के तहत आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसी अन्य पहलें, साथ ही वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय घरेलू सुधार हैं। आरआईएस सीईओ स्पीक्स श्रृंखला का आयोजन करता आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉ. बिबेक देबरॉय, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन और भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव जैसे विशेषज्ञों के साथ कई विकास पहलों और मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इन विमर्शों में विविध प्रकार के मुद्दों पर चर्चा हुई तथा वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण और एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) में भागीदारी के माध्यम से एमएसएमई के लिए नीतिगत दायरे में भी वृद्धि हुई।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार का स्थानीयकरण

घरेलू सुधार व्यापार नीति के स्थानीयकरण से संबद्ध हैं, जो जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देता है। भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के माध्यम से, ओडीओपी दर्शन के साथ उच्च–प्रौद्योगिकी निर्यात, ई–कॉमर्स और विशिष्ट उत्पाद निर्यात संवर्धन के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया है। सरकार की 'निर्यात केंद्र के रूप में जिला' (डीईएच) पहल चिन्हित निर्यात बाज़ारों के लिए लक्षित क्षेत्रों में वस्तुओं के उत्पादन का सूक्ष्म–स्तरीय प्रबंधन प्रदान करती है। वर्तमान में, कुछ राज्यों और ज़िलों में निर्यात अत्यधिक असंतुलित

आरआईएस की सीईओ स्पीक्स श्रृंखला के दौरान डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ

है, जिसकी चर्चा ' डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्सः अ माइक्रो–लेवल ट्रेड स्ट्रेटेजी' और 'माइक्रो–लेवल एक्सपोर्ट मैनेजमेंट इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी : इम्प्लीमेंटिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्स इन इंडिया' में भी की गई है। यह पहल किसानों और एमएसएमई को उत्पादन को विकसित और सवंर्धित करने का अवसर प्रदान करती है, जहां उन्हें स्वाभाविक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हो। यह पहल कृषि उत्पादों, खिलौना समूहों और भौगोलिक संकेतकों वाले उत्पादों पर केंद्रित है। दीर्घकाल तक निरंतर निर्यात बनाए रखने के लिए उत्पादों को एक स्थान पर एकत्र करने, नियमित गुणवत्ता जांच और उत्पाद पैकेजिंग को वैश्विक मानकों अनुरूप बनाए रखा जाना चाहिए।

वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर (1 ट्रिलियन डॉलर वस्तुओं में और 1 ट्रिलियन डॉलर सेवाओं में) का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय और जिला स्तर पर लक्षित तैयारी और सेवा व्यापार के लिए सटीक बातचीत करने की नई रणनीति सहित पारंपरिक और नए क्षेत्रों से निपटने वाले व्यापक व्यापार समझौते का होना आवश्यक है। आर्थिक मजबूती की दिशा में भारत की यात्रा बहुआयामी है। इसमें बाहरी जोखिमों का प्रबंधन करना, डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करना और वित्तीय समावेशन का विस्तार करना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर, श्री एम. राजेश्वर राव आरआईएस में

शामिल है। ये प्रयास अलग–थलग नहीं हैं–वे एक नई आर्थिक संरचना के परस्पर संबद्ध स्तंभ हैं, जो समावेशिता और वैश्विक प्रासंगिकता को प्राथमिकता देते हैं। बाहरी झटकों के प्रति देश की प्रतिक्रिया, निष्पक्ष, समावेशी और सरल व्यापार के लिए इसकी प्रतिबद्धता और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वित्तीय समावेशन के प्रति इसका दृष्टिकोण आर्थिक मजबूती कायम करने की बहुआयामी रणनीति को दर्शाते हैं।

बर्लिन, जर्मनी में आयोजित चौथे भारत–जर्मनी ट्रैक 1.5 रणनीतिक संवाद में आरआईएस और आईसीडब्ल्यूए के प्रतिनिधि

आरआईएस द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

- 31 दिसंबर 2024 को ट्रेड, टैरिफ और ट्रंप पर संगोष्ठी।
- 25 अप्रैल 2024को सीईओ स्पीक्स श्रृंखलाः आर्थिक नीतियों का मार्गनिर्देशन।
- 3 अक्टूबर 2024 को सीईओ स्पीक्स श्रृंखला : आरआईएस में डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन : भारत के आर्थिक समायोजन को समझना।
- 19–20 नवंबर 2024 को जर्मनी में चौथा भारत–जर्मनी ट्रैक 1.5 रणनीतिक संवाद।
- 17 अक्टूबर 2024 को सीईओ स्पीक्स श्रृंखला : डॉ. पूनम गुप्ता (एनएसीईआर) नीतिगत अनुसंधान के रूपांतरण के बारे में चर्चा।
- 1 अक्टूबर 2024 को सीईओ स्पीक्स श्रृंखला : व्यापार सुविधा समझौते के बारे में समझ।
- 22 अगस्त 2024 को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वित्तीय समावेशन पर कार्यशाला।
- 29 नवंबर 2024को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, श्री राजेश्वर राव का आरआईएस का दौरा।

प्रमुख प्रकाशन

रिपोर्ट

- ट्रम्प्स ट्रेड पॉलिसीज पेरिल ग्लोबल इकोनोमिक स्टेबिलिटी, आरआईएस, नई दिल्ली 2025.
- एमएसएमई डिजिटलाइजेशन इन इंडियाः करंट स्टेट्स एंड चैलेंजेस, आरआईएस, नई दिल्ली 2025

चर्चा पत्र

- #294: इंडियाज़ एक्सपीरिएंस इन इंसोलवेंसी लॉज़ः लर्निंग्स फॉर द ग्लोबल साउथ, अनमोल बख्शी द्वारा
- #298: इंसोलवेंसी लॉज एंड इंटरनेशनल ट्रेडः अ पर्सपेक्टिव, अमोल बक्सी द्वारा

नीतिगत सारांश

- #109: डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्सः अ माइक्रो–लेवल ट्रेड स्ट्रेटेजी, पंखुड़ी गौड़ द्वारा
- #113: स्ट्रेंग्थनिंग इंडियाज़ मिनरल सिक्युरिटीः फ्रॉम एफर्ट्स टू एक्शन, पंकज वशिष्ठ द्वारा

लोकप्रिय लेख

- चतुर्वेदी, सचिन. 2025. ग्लोबल ट्रेड, ट्रम्प एंड इंडियाज रोल. इंडियन एक्सप्रेस. 18 फरवरी।
- डे, प्रबीर. 2025. "टूवर्ड्स फ्री ट्रेड थ्रू एआईटीआईजीए", हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 3 जनवरी।
- खेर, राजीव एंड गुप्ता, अंशुमान 2025. कार्बन टैक्सेस डब्ल्यूटीओ टेस्ट एंड अपॉर्च्यूनिटीज फॉर बैटर इंडिया–ईयू ट्रेड टर्म्स। बिजनेस स्टैंडर्ड, 27 मार्च।
- खेर, राजीव एंड गुप्ता, अंशुमान 2025. ट्रम्प 2.0: फेट ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी एमिड शिफ्टिंग ग्लोबल प्रायोरिटीज. बिजनेस स्टैंडर्ड, 13 फरवरी।
- वशिष्ठ, पंकज. 2025. ''सिक्योरिंग सप्लाई ऑफ निश मिनरल्स क्रूशियल''. द हिंदू बिजनेसलाइन. 23 जनवरी।

4 कनेक्टिविटी, गलियारे, बुनियादी ढांचा और वित्त

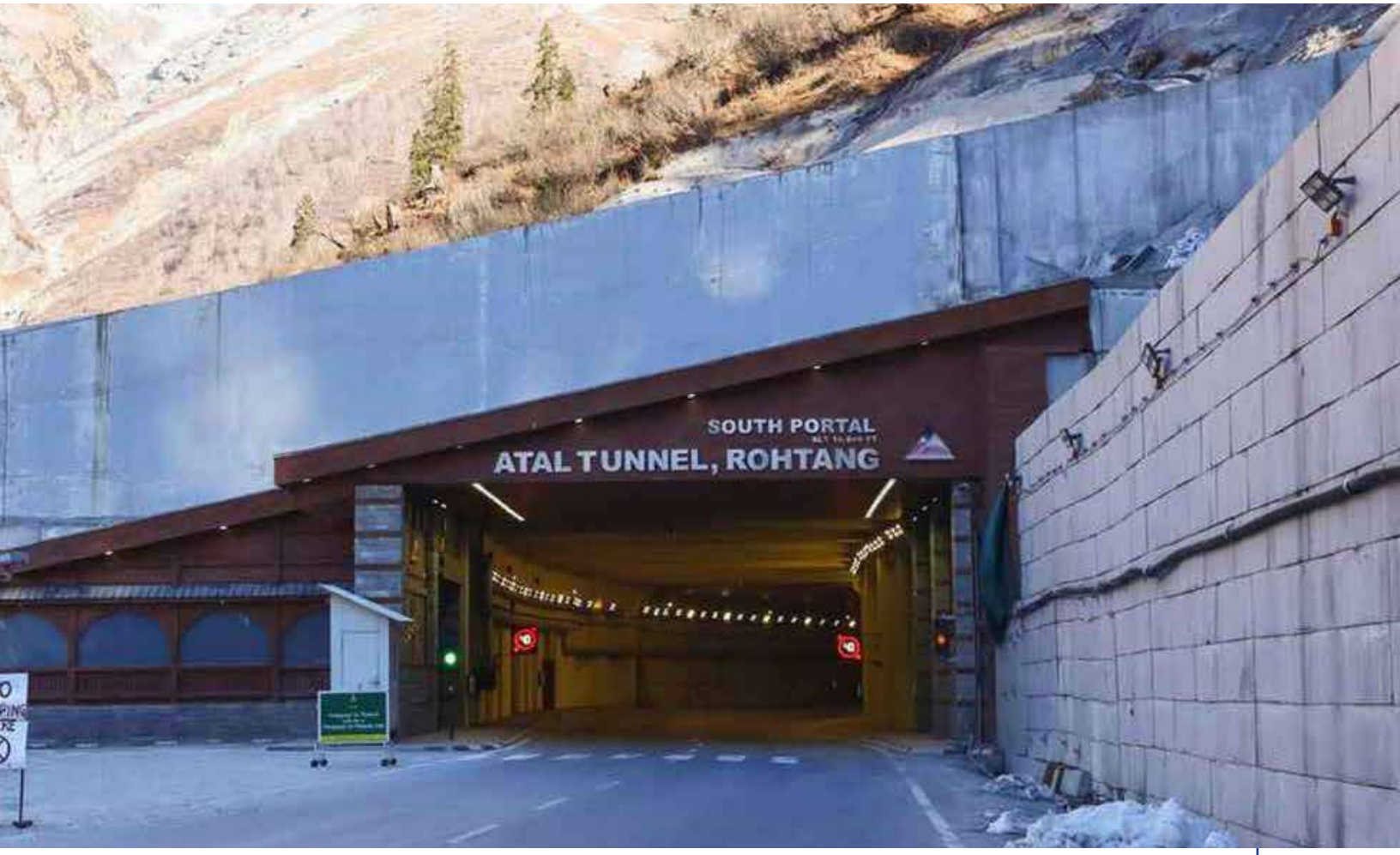

अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में लगातार व्यवधानों से घिरे आज के बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्य में मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचा क्षेत्रीय एकीकरण और सतत विकास के लिए रणनीतिक अनिवार्यता बनकर उभरा है। मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप व्यापार लागत में कमी आई है और गलियारों ने आर्थिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

कनेक्टिविटी पर समकालीन वैश्विक विमर्श में परिवहन के पारंपरिक बुनियादी ढांचे से परे डिजिटल, सांस्कृतिक, सामाजिक और लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों भी शामिल हो चुके हैं, जिससे यह आर्थिक कूटनीति और विकास सहयोग दोनों का आधार बन चुका है। देश और क्षेत्रीय समूह ऐसे कनेक्टिविटी गलियारों और प्लेटफॉर्म में तेज़ी से निवेश कर रहे हैं, जो वस्तुओं, सेवाओं, लोगों और डेटा के सुरक्षित, कुशल और समावेशी आवागमन को प्राथमिकता देते हैं। भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, एशिया–अफ्रीका विकास गलियारा और भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) जैसी पहल कनेक्टिविटी की इसी नई परिकल्पना को दर्शाती है।

व्यापार और कनेक्टिविटी के प्रति समर्पित अनुसंधान स्तंभों के साथ, आरआईएस ने इस विमर्श को आगे बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है और कई उच्च–स्तरीय बहु–हितधारक संवाद आयोजित किए हैं तथा इसी विषय पर केंद्रित अनेक प्रकाशनों को प्रोत्साहन दिया है।

बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

वैश्विक नीतिगत जगत में बुनियादी ढांचे को व्यापार एकीकरण, जलवायु लक्ष्यों, डिजिटल समावेशन और क्षेत्रीय समानता प्राप्त करने के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है। इस अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए भारत ने गति शक्ति, भारतमाला और सागरमाला जैसी पहलों के माध्यम से कनेक्टिविटी से संबंधित अपने बुनियादी ढांचे को संवर्धित के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं; जिनका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस संदर्भ में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयास केवल क्षमता निर्माण ही नहीं करते, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में मजबूती और दक्षता का सृजन भी करते हैं। साथ ही आईएमईसी द्वारा महाद्वीपों के बीच निर्बाध व्यापारिक संबंध बनाकर लॉजिस्टिक्स लागत में 30 प्रतिशत तक और परिवहन समय में 40 प्रतिशत तक की कमी लाए जाने का अनुमान है। मैरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2030 और समुद्री अमृत काल विजन (एमएकेवी) 2047 की शुरुआत के साथ, प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से बंदरगाह दक्षता में वृद्धि भारत की प्राथमिकता रही है।

कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन मूलभूत रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार समुद्र के माध्यम से संचालित होने के कारण समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण की रीढ़ हैं। बंदरगाह का कुशल बुनियादी ढांचा, तटीय नौवहन और ट्रांसशिपमेंट केंद्र बहुविध कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे सीमाओं के पार माल की निर्बाध आवाजाही संभव होती है। 'असेसिंग परफॉर्मेंस एंड

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; श्री संजय कुमार वर्मा, अध्यक्ष, आरआईएस; श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, महानिदेशक, आईआईपीए और सदस्य शासी निकाय, एसआईओएस; राजदूत सुधीर देवरे, पूर्व राजनयिक, नयी दिल्ली में आयोजित आईएमईसी सम्मेलन में।

प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया' शीर्षक वाले आरआईएस चर्चा पत्र में भारतीय बंदरगाहों की प्रचालन दक्षता का विश्लेषण करते हुए और टर्नअराउंड समय, बर्थ ऑक्यूपेंसी और कार्गो हैंडलिंग क्षमता जैसी समस्याओं को रेखांकित करते हुए बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक नीतिगत समाधान प्रस्तावित किए गए, जो भारत के वैश्विक ट्रांस–शिपमेंट हब बनने के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

विश्व बैंक और एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्व ारा 2023 के लिए विकसित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीपीपीआई) के नवीनतम संस्करण के अनुसार, नौ भारतीय बंदरगाहों के शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाने के बावजूद, भारतीय बंदरगाह अभी तक संरचनात्मक कमियों, विशेष रूप से कम उत्पादकता और अकुशलता से ग्रस्त हैं। इस संबंध में, हिंदू बिज़नेसलाइन में आरआईएस संकाय द्वारा लिखे गए एक लोकप्रिय लेख, जिसका शीर्षक था, "नेविगेटिंग थ्रू इंडियाज़ पोर्ट सेक्टर" ने भारत के बंदरगाह उद्योग पर प्रकाश डाला।

अपने चर्चा पत्र 'सीफररज़ वेल–बीइंग एंड मिटिगेशन ऑफ चैलेंजिज इन द इकोसिस्टम" में मानवीय आयामों को प्रमुखता देते हुए आरआईएस ने भारत के समुद्री कार्यबल में व्यावसायिक खतरों, मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों और संरचनात्मक कमजोरियों की पड़ताल की और टिकाऊ बुनियादी ढांचागत प्रणालियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बेहतर सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण और संस्थागत सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सुरक्षित और सुदृढ़ समुद्री कनेक्टिविटी सक्षम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने डेविड ब्रूस्टर की 'द फ्यूचर ऑफ रीजनल मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग इन द इंडियन ओशन' शीर्षक वाली कॉमेंट्री प्रकाशित की, जिसमें हिंद महासागर में समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) की उभरती संरचना का अन्वेषण किया गया है। इस कॉमेंट्री में अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत, अंतर–राष्ट्रीय समुद्री सूचना साझाकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसने सामूहिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को बढ़ाने वाले क्षेत्रीय एमडीए तंत्रों को बढ़ावा देने में भारत की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया है।

भारत का माल ढुलाई बिल लगभग 100 अरब डॉलर का है, जो तेल आयात के बाद दूसरे स्थान पर आता है और भारत का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, ऐसे में विदेशी स्वामित्व वाले जहाजों पर इस निर्भरता पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। भारत के

समुद्री ज्ञान श्रृंखला के प्रथम व्याख्यान में प्रतिष्ठित वक्ता

वर्ष 2025–26 के केंद्रीय बजट में जहाज निर्माण उद्योग को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिए जाने और 25,000 करोड़ रुपये के जहाज निर्माण कोष से जहाज निर्माण उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलने और भारत में जहाज स्वामित्व को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। स्वदेशी जहाज न केवल विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्य में भारत को मजबूत आधार प्रदान करते हुए आघातों से भी बचाएंगे। इस संदर्भ में, आरआईएस ने 'सीईओ स्पीक्स' श्रृंखला के तहत, 24 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड शिपब्रोकर्स, लंदन के श्री कृष्णन सुब्रमण्यम को 'कार्गो माल ढुलाई शुल्क को तर्कसंगत बनाना – भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण' शीर्षक से एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। इस वार्ता में भारत के माल ढुलाई बिल के घटकों का विश्लेषण किया गया और माल ढुलाई शुल्क में योगदान देने वाली 41 लागत श्रेणियों की पहचान की गई और नियामक तर्कसंगतता और एआई–सक्षम माल ढुलाई अनुकूलन के लिए कार्रवाई योग्य क्षेत्रों की पहचान की गई।

रणनीतिक व्यापार मार्गों से परे, आरआईएस ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपर्क पर भी जोर दिया है। भारत की समुद्री विरासत के बारे में ज्ञान का प्रसार करने और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य से इंडिया हैबिटेट सेंटर के सहयोग से आरआईएस के समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी) ने 14 जनवरी 2025 को समुद्री ज्ञान व्याख्यान श्रृंखला का शुभारंभ किया। 'जहाज निर्माण में भारत की प्रेरणादायक विरासत' शीर्षक वाले प्रथम व्याख्यान में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉ. संजीव रंजन, मैरीटाइम हिस्ट्री सोसाइटी के कमोडोर अजय अग्रवाल (सेवानिवृत्त) और भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के पूर्व प्रधान निदेशक कमोडोर विनीत तिवारी (सेवानिवृत्त) जैसे प्रतिष्ठित वक्ताओं ने सिंधु–सरस्वती सभ्यता से लेकर आईएनएस विक्रांत तक भारत की जहाज निर्माण विरासत के पदचिन्हों का उल्लेख करते हुए इस बात को रेखांकित किया कि किस प्रकार समुद्री नवाचार ने लंबे अर्से से भारत के वैश्विक संपर्कों और शुरुआती वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति को मजबूती प्रदान की है।

अभूतपूर्व प्रतिक्रिया और दर्शकों की उपस्थिति (व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों) के बाद, इस श्रृंखला का दूसरा व्याख्यान 18 फरवरी 2025 को प्रोफेसर जॉय सेन, आईआईटी खड़गपुर द्वारा 'भारत में समुद्री प्रतिभा का इतिहास, पुरातत्व और भविष्य' पर आयोजित किया गया, जिसमें यह प्रदर्शित करते हुए कि कैसे कनेक्टिविटी में मानव पूंजी, ज्ञान प्रणाली और समावेशी योजना भी शामिल है, समुद्री क्षेत्रीय नियोजन, क्षमता निर्माण और स्थिरता में भविष्य की जरूरतों के साथ प्राचीन नौवहन परंपराओं के सम्मिलिन को रेखांकित किया गया।

अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर विकसित करने में मदद करने के अलावा, बुनियादी ढांचा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समान रूप से विकास को भी सक्षम बनाता है। भारत

श्री कृष्णन सुब्रमण्यम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड शिपब्रोकर्स (आईसीएस), लंदन के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आरआईएस संकाय सदस्यों के साथ

में व्यापक पहुंच, समानता और समावेशिता को सुगम बनाने के लिए तकनीकी क्रांतियों का उपयोग करते हुए, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के विकास ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ, जन–केंद्रित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में, रु293 'इक्विटेबल डेवेलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजीः रिलेवेंस ऑफ द इंडियन एक्सपीरिएंस फॉर ग्लोबल साउथ' शीर्षक से आरआईएस का चर्चा पत्र, समतामूलक और समावेशी विकास में तकनीकी अवसंरचना की संभावित भूमिका की पड़ताल करता है।

आर्थिक गलियारे

हाल के वर्षों में, आर्थिक गलियारे केवल परिवहन मार्ग न रहकर रणनीतिक आर्थिक क्षेत्रों में परिणत हो गए हैं जो सीमा पार सहयोग को मज़बूती देते हैं, मूल्य श्रृंखलाओं को एकीकृत करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। ये गलियारे अब रेखीय अवसंरचना तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उनमें ऊर्जा पाइपलाइनों, फाइबर–ऑप्टिक केबलों, वित्तीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी प्रणालियों और लोगों की आवाजाही के ढांचों को भी शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार, ये तेज़ी से अनिश्चित होते वैश्विक परिदृश्य में व्यापार को बढ़ावा देने वाले और राजनीतिक विश्वास के आधार के रूप में कार्य करते हैं।

नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित जी–20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया आईएमईसी, भारत को पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह गलियारा रेल, सड़क, समुद्री, डिजिटल और ऊर्जा संपर्कों को एक एकल, बहु–मॉडल ढांचे में एकीकृत करता है। अनुमान है कि इसके पूरा होने पर लॉजिस्टिक्स लागत में 30 प्रतिशत तक और परिवहन समय में लगभग 40 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है, जिससे मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला मार्गों का तीव्र और अधिक मजबूत विकल्प तैयार हो सकता है।

सार्वजनिक–निजी भागीदारी की भावना में गहराई से निहित विकास के वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता के साथ आईएमईसी का महत्व और भी बढ़ गया है और इस विषय पर नीतिगत चिंतन को आकार देने में आरआईएस अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगस्त 2024 में, इसने बेलाजियो, इटली में बेलाजियो सेंटर और डालबर्ग कंसल्टिंग के साथ एक उच्च–स्तरीय कार्यशाला का सह–आयोजन किया, जिसमें वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाकर इस बात का आकलन किया गया कि आईएमईसी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे मजबूत कर सकता है, बुनियादी ढांचे की कमियों को कैसे पाट सकता है और स्थायी निवेश प्रवाह को कैसे बढ़ावा दे सकता है। आईआरएस की रिपोर्ट 'इंडिया–मिडिल ईस्ट–यूरोप इकोनोमिक कॉरिडोर : स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड वे फॉरवर्ड' में संकलित निष्कर्षों ने शासन मॉडल, वित्त पोषण तंत्रों और संस्थागत समन्वय पर कार्रवाई योग्य सुझाव दिए गए।

इस गति को आगे बढ़ाते हुए, आरआईएस और सोसाइटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज ने 19 मार्च 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें आईएमईसी को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का जोखिम कम करने की व्यापक धारणा के अंतर्गत स्थापित किया गया। चर्चा के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह के आधुनिकीकरण, जलवायु–स्मार्ट ऊर्जा साझेदारी और मैत्री जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल व्यापार सुविधा को शामिल किया गया। नीति पर ध्यान केंद्रित करने वाला थिंकटैंक होने के नाते, आईडीई–जेट्रो के श्री इकुमो इसोनो ने 20 मार्च 2025 को आरआईएस संकाय के समक्ष आईएमईसी के एक भौगोलिक सिमुलेशन मॉडल (जीएसएम) का विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो सबूतों के आधार पर निर्णय लेने का समर्थन करते और आईएमईसी के ठोस आर्थिक सामर्थ्य को दर्शाते हुए 2030 तक भारत के लिए 1.98 प्रतिशत, यूएई के लिए 2.76 प्रतिशत और सऊदी अरब के लिए 0.70 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान व्यक्त करता है।

उभरती गलियारा पहलों में शामिल होकर और क्षेत्रीय संवादों को स्थिरता प्रदान कर आरआईएस ने हिंद–प्रशांत और उससे परे कनेक्टिविटी की रणनीतिक रूपरेखा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है। काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग और डालबर्ग कंसल्टिंग के साथ साझेदारी में 16 अप्रैल 2025 को आईटीसी मौर्या, नई दिल्ली में आरआईएस द्वारा 'आईएमईसी सम्मेलन 2025 महाद्वीपों में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ाना'का आयोजन किया। जिसने आईएमईसी के लाभ और इसकी महत्ता किसी भी अन्य आर्थिक गलियारे से कहीं अधिक होने के बारे में सार्थक चर्चा और गहन समझ प्रदान की। आईएमईसी को समृद्धि के विजन के रूप में सराहा गया, एक ऐसा विजन, जो भारत को दुनिया से जोड़ता है, जिससे भारत को बहुध्रुवीय दुनिया में अपने मूल्य, अपने उद्यम और अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

पश्चिम एशिया में जारी भू–राजनीतिक अस्थिरता के कारण सितंबर 2023 में हस्ताक्षरित होने के बावजूद,

आईएमईसी की प्रगति बार–बार बाधित हुई है। ऐसी घटनाओं की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, आरआईएस ने नई दिल्ली में 10 दिसंबर, 2024 को ग्रीस के पूर्व राजदूत महामहिम राजदूत यानिस अलेक्सी ज़ेपोस को आमंत्रित किया। ग्रीस की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, राजदूत ज़ेपोस ने यूरोपीय क्षेत्र में प्रवेश बिंदु के रूप में आईएमईसी ढांचे को सुगम बनाने में ग्रीस की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। राजदूत ज़ेपोस द्वारा आईएमईसी को एक 'शांति परियोजना' के रूप में प्रस्तुत किया जाना, भू–राजनीतिक अस्थिरता के बीच आरआईएस द्वारा कनेक्टिविटी को सहयोग के एक तंत्र के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण से मेल खाता है।

वित्त

विकासशील देशों द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व, सुलभ जलवायु वित्त और डिजिटल वित्तीय समावेशन की मांग किए जाने से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पुनर्संतुलन के दौर से गुजर रही है। पिछले वर्ष आरआईएस के योगदान से विभिन्न मंचों और नीतिगत स्तरों पर इन विषयों पर गौर किया गया, जिसमें क्षेत्रीय वित्तीय सहयोग, फिनटेक, वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिदृश्य के मुद्दे व्यापार के प्रमुख स्तंभों के भीतर अनुसंधान के विशिष्ट स्तंभों के रूप में उभरे।

आरआईएस संकाय विभिन्न टी–20 टास्क फोर्स में सह–अध्यक्ष के रूप में शामिल रहे हैं, जिन्होंने पिछली तीन जी–20 अध्यक्षताओं के दौरान प्रस्तुत महत्वपूर्ण सिफारिशों को आकार दिया है। टास्क फोर्स 3 (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार) एसडीजी के वित्त पोषण अंतर को पाटने, जलवायु–अनुकूल निवेश तंत्रों को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय बैंकों के अधिदेशों पर पुनर्विचार करने पर केंद्रित है। आरआईएस ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविकताओं पर आधारित नवीन वित्तीय तंत्रों की वकालत करते हुए दक्षिण–दक्षिण सहयोग की भूमिका पर विशेष ध्यान आकर्षित किया। दुनिया भर के सहयोगियों के साथ आरआईएस संकाय द्वारा लिखित 'ऐन इन्क्लूसिव जी–20 स्ट्रेटेजी टू स्केल' डेट–फॉर–नेचर/क्लाइमेट स्वाप्स' फॉर इफेक्टिव क्लाइमेट एंड बायोडायवर्सिटी एक्शन इन डेवेलपिंग कंट्रीज" शीर्षक से एक टी–20 नीतिगत सारांश को भी ब्राजील की जी–20 अध्यक्षता के तहत प्रकाशित करने के लिए स्वीकृत किया गया था।

आरआईएस ने फिनटेक और फिनटेक–सक्षम सेवाओं में भारत–ब्रिटेन व्यापार के बारे में भी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया, जिसमें इस बात को रेखांकित किया गया कि वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण और स्टार्ट–अप इकोसिस्टम पर गौर करते हुए समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। आरआईएस द्वारा पेश की गई प्रस्तुतियों में द्विपक्षीय सहयोग और नियामक सामंजस्य के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान की गई, साथ ही खंडित फिनटेक विनियमन से होने वाले जोखिमों के प्रति आगाह भी किया गया।

आर्थिक मजबूती, वित्तीय समावेशन और सतत विकास को बढ़ावा देने में दिवालियापन और शोधन अक्षमता प्रणालियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्लोबल साउथ के कई देश कमज़ोर कानूनी ढांचों, ऋण तक सीमित पहुंच और अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह न केवल नीतियों और नियामक तंत्रों की कमी का संकेत है जो संभावित निवेशकों को नकारात्मक बाजार के संकेत भेजते हैं, बल्कि किसी देश द्व ारा किए जा सकने वाले व्यापार की मात्रा को भी प्रभावित करते हैं। वित्तीय संकट के समाधान के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया प्रदान करके इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी दिवालियापन और शोधन अक्षमता कानून आवश्यक हैं। भारत द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और एक प्रभावी समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए 2016 में दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता लागू किए जाने के साथ ही ग्लोबल साउथ की अनेक विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अब इस संबंध में अपनी नीतियां और नियम बना रही हैं। इस संबंध में, आरआईएस ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर दिवालियापन कानूनों के प्रभाव और दिवालियापन कानूनों के बारे में भारत के अनुभवों और ग्लोबल साउथ इनसे क्या सीख ग्रहण कर सकता है, के संबंध में दो चर्चा पत्र जारी किए हैं।

आरआईएस द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

- 24 अप्रैल 2024 को भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को आगे बढ़ाने पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 10 मई 2024 को भू–राजनीति और अवसंरचना विकास पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 10 दिसंबर 2024 को भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के भू–राजनीतिक आयामों पर इंटरैक्टिव सत्रः महामहिम राजदूत यानिस अलेक्सी ज़ेपोस के विचार।
- 19 मार्च 2025 को भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) पर सम्मेलन : नई उम्मीदें और नए अवसर।
- 20 मार्च 2025 को जियोग्राफिकल सिमुलेशन मॉडल (जीएसएम) और भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 14 जनवरी 2025 को समुद्री ज्ञान श्रृंखला का प्रथम व्याख्यान : जहाज निर्माण में भारत की प्रेरणादायक विरासत।
- 18 फरवरी 2025 को समुद्री व्याख्यान श्रृंखला : भारत में समुद्री प्रतिभा का इतिहास, पुरातत्व और भविष्य।
- 24 मार्च 2025 को सीईओ स्पीक्स श्रृंखला : कार्गो माल ढुलाई शुल्क को तर्कसंगत बनाना–भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण।

प्रमुख प्रकाशन

रिपोर्ट

- इंडिया–मिडल ईस्ट–यूरोप इकोनोमिक कोरिडोर (आईएमईसी) : स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड वे फॉरवर्ड, आरआईएस, नई दिल्ली 2025.

चर्चा पत्र

- #300: असेसिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, प्रबीर डे और अर्पित बर्मन द्वारा
- #295: सीफररज़ वेल बीइंग एंड मिटिगेशन ऑफ चैलेंजिज इन द इकोसिस्टम, चंद्र शेखर द्वारा
- एआईसी कॉमेंट्री
- #52: द फ्यूचर ऑफ रीजनल मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग इन द इंडियन ओशन, डेविड ब्रूस्टर द्वारा

लोकप्रिय लेख

- डे, प्रबीर. 2024. ""नेविगेटिंग थ्रू इंडियाज़ पोर्ट सेक्टर", द हिंदू बिजनेसलाइन, 30 नवंबर 2024

5 भारत की विदेश नीति में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग

अंतर्निर्भरता, नेटवर्क कनेक्टिविटी और बहुध्रुवीयता के उदय से चिन्हित तेज़ी से परिवर्तित होते वैश्विक परिदृश्य में भारत का द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है। अपनी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के आधार पर, भारत ने दक्षिण–पूर्व एशिया, बंगाल की खाड़ी और मेकांग क्षेत्र; और हिंद–प्रशांत क्षेत्र के साथ अपनी सहभागिता को व्यापक बनाया है। ये साझेदारियां स्थिरता, कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक एकीकरण और सुरक्षा ढांचों सहित अनेक क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, सिंगापुर में 8वीं एआईएनटीटी बैठक में मुख्य भाषण दे रहे हैं

पिछले एक साल में, आरआईएस के प्रयास क्षेत्रीय संवादों को आगे बढ़ाने, संस्थागत तंत्रों को मज़बूत बनाने और सहयोग के व्यावहारिक अवसर उत्पन्न करने की दिशा में केंद्रित रहे हैं। आसियान, बिम्सटेक और मेकांग–गंगा जैसे सहयोग के ढांचों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहभागिताओं ने उभरते अवसरों और चुनौतियों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रियाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र ने दक्षिण–पूर्व एशिया के लिए सेतु और विकास–आधारित कूटनीति के केंद्र बिंदु के रूप में महत्व प्राप्त किया है। यह अध्याय भविष्य की साझेदारियों को आकार देने वाली विषयगत प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के साथ ही साथ उपलब्धियों और उभरते रुझानों पर बल देते हुए प्रमुख भौगोलिक परिप्रेक्ष्यों से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति आरआईएस का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

दक्षिण–पूर्व एशिया और भारतः गहन आर्थिक एकीकरण

दक्षिण–पूर्व एशिया भारत के हिंद–प्रशांत संबंधों का केंद्र बना हुआ है, और हाल की द्विपक्षीय पहलों ने इस क्षेत्र में रणनीतिक और सांस्कृतिक तालमेल को दर्शाया है। आरबीआई–बैंक इंडोनेशिया मुद्रा समझौते का वित्तीय एकीकरण की दिशा में उपलब्धि के रूप में स्वागत किया गया, जिसे सीधी उड़ानों के माध्यम से पर्यटन के विस्तार और लोगों के बीच बेहतर आदान–प्रदान की प्रतिबद्धताओं द्वारा और भी बल मिला है।

एआईएनटीटी में पैनल चर्चा

सिंगापुर में आयोजित 8वीं एआईएनटीटी बैठक में प्रतिनिधिगण

मलेशिया के साथ, जलवायु–अनुकूल कृषि, कृषि–तकनीक नवाचार और खाद्य प्रसंस्करण में संयुक्त अनुसंधान पर केंद्रित करते हुए खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। मार्च 2025 में आयोजित भारत–वियतनाम ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस में जलवायु कार्रवाई और त्रिकोणीय सहयोग को सतत विकास के महत्वपूर्ण मार्गों के रूप में रेखांकित करते हुए इस प्रतिबद्धता को और बल प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय स्तर पर, सिंगापुर में आयोजित 8वें आसियान–इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक (एआईएनटीटी) ने आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि की और आसियान–भारत

बिम्सटेक क्षेत्र में कृषि व्यापार से संबंधित तालमेल : क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन पर सम्मेलन में विख्यात वक्ता

साझेदारी को आकार देने में साझा सभ्यतागत मूल्यों और कूटनीति के स्थायी महत्व को रेखांकित करते हुए कनेक्टिविटी, शिक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और जलवायु लचीलेपन के क्षेत्र में गहन सहयोग के मार्ग निर्धारित किए। इसके साथ ही, आसियान साझेदारों के साथ अंतर–संचालनीय भुगतान प्रणालियों और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित फिनटेक सहयोग पर भी प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त, इंडो–पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्क्लेव (आईपीईसी) ने मानक सामंजस्य और कुशल मूल्य श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा देते हुए प्रौद्योगिकी को एक व्यापार प्रवर्तक के रूप में प्रदर्शित किया।

सभी आयामों में कनेक्टिविटी मज़बूत करना आरआईएस के क्षेत्रीय एजेंडे का केंद्रबिंदु बना रहा। त्रिपक्षीय राजमार्ग और समुद्री गलियारों के बारे में विचार–विमर्श में भारत, दक्षिण–पूर्व एशिया और उससे परे बुनियादी ढांचे के संबंधों पर गौर किया गया। मलेशिया के नेतृत्व में आसियान के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी संवादों में सीमा पार सुगम आवागमन के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और संस्थागत ढांचों की पड़ताल की गई। दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुगमता बढ़ाने के लिए एआई–आधारित समाधानों और टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देने वाले कम निवेश वाले कनेक्टिविटी मॉडलों की अवधारणा को प्रोत्साहन दिया गया।

आसियान के अलावा, मेकांग–गंगा सहयोग (एमजीसी) भी भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच एक प्राकृतिक सेतु का काम करता है, जिसे साझा विरासत और रणनीतिक भूगोल सुगम बनाते हैं। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक प्रस्तावित विस्तार के साथ विशेषकर भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से एमजीसी को व्यापक संपर्क ढांचों में एकीकृत करने के कार्य को, संवादों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है।

पड़ोसी क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी उपक्षेत्रः भारत की राजनयिक सहभागिताएं

बंगाल की खाड़ी उपक्षेत्र हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए एक

डॉ. बिबेक देबरॉय आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ

तालिकाः1 द्विपक्षीय और क्षेत्रीय ढांचों में रेखांकित विषय, संबंधित समन्वित राष्ट्रीय रणनीतियां और नीतियां तथा प्रमुख फोकस बिंदु

क्र.सं.	विषयगत क्षेत्र	समन्वित राष्ट्रीय नीतियां और रणनीतियां	आरआईएस द्वारा प्रमुख फोकस बिंदु
1	द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से हरित परिवर्तन और स्थिरता को आगे बढ़ाना	राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय जैव–ऊर्जा मिशन	हरित ऊर्जा कूटनीति, जलवायु–स्मार्ट कृषि, सर्कुलर इकोनॉमी, जैव–अर्थव्यवस्था, कृषि–तकनीक सहयोग
2	द्विपक्षीय और क्षेत्रीय ढांचों के माध्यम से समावेशी, तकनीक–संचालित और भविष्य के लिए तैयार मूल्य श्रृंखलाएं	पीएम गति शक्ति, मेक इन इंडिया, स्टार्ट–अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आसियान–भारत एफटीए	टिकाऊ औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाएं, कृषि–व्यवसाय संबंध, व्यापार सुविधा, आरवीसी 4.0, एमएसएमई और युवा समावेशन
3	द्विपक्षीय और क्षेत्रीय ढांचों के माध्यम से भौतिक और डिजिटल संपर्क को मजबूत करना	एक्ट ईस्ट नीति, सागरमाला, भारतमाला, डिजिटल इंडिया, पीएम गति शक्ति	त्रिपक्षीय राजमार्ग, बंदरगाह आधारित विकास, डीपीआई अंतर–संचालनीयता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, सीमा संपर्क
4	द्विपक्षीय और क्षेत्रीय साझेदारियों में सांस्कृतिक कूटनीति और सभ्यतागत संबंधों को बढ़ावा देना	पड़ोस प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति, आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत	साझा महाकाव्य और लिपियां, सभ्यतागत विरासत, पूर्वोत्तर – दक्षिण–पूर्व एशिया सांस्कृतिक सेतु, लोगों में आपसी संबंध
5	द्विपक्षीय और क्षेत्रीय ढांचों में सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना	हिंद–प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई), सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास), मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030	समुद्री सुरक्षा, यूडीए ढांचा, आईयूयू मत्स्य पालन, रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय व्यवस्था की मजबूती
6	संस्थागत तंत्र और वैचारिक नेतृत्व को बढ़ाना	भारत @ 2047 एक्ट ईस्ट/ एआईएनटीटी/ बिम्सटेक चार्टर	बहुपक्षवाद, ज्ञान कूटनीति, नीतिगत सामंजस्य, त्रिपक्षीय प्रारूप, विचार नेतृत्व और समन्वयकारी भूमिका

स्रोतः लेखक द्वारा संकलित एवं डिज़ाइन किया गया

द्वितीय इंडो–पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्क्लेव (आईपीईसी) में भाग लेने वाले प्रतिभागी।

महत्वपूर्ण विकास केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां द्वि पक्षीय और क्षेत्रीय पहलें कनेक्टिविटी, स्थिरता और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। म्यांमार के साथ, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, एमएसएमई, डिजिटल कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है, जो विकास की रीढ़ त्रिपक्षीय राजमार्ग द्वारा समर्थित है। ऊर्जा सहयोग में भी तेज़ी आई है, जिसमें म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह को स्वच्छ समुद्री अवसंरचना और हरित हाइड्रोजन उत्पादन सहित हरित ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिससे पूर्वोत्तर भारत में ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूती मिलेगी। बांग्लादेश के पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा ने जानकारी युक्त मीडिया संवाद को बढ़ावा दिया और द्वि पक्षीय संबंधों के बारे में जनता की समझ को बढ़ाया। सार्क महासचिव की यात्रा के दौरान, आरआईएस ने पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी बंगाल से चिकित्सा और सामान्य पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सीमा पार डिजिटल भुगतान प्रणालियों का प्रस्ताव रखा। राजनयिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नेपाल के साथ भारत की साझेदारी बढ़ी है, जिसने ग्रामीण परिवर्तन के एक मॉडल के रूप में भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से नेपाली राजनयिकों को अवगत कराया। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के साथ सहभागिताओं ने शैक्षिक कूटनीति और विद्वानों के आदान–प्रदान को सुदृढ़ बनाया।

क्षेत्रीय स्तर पर, बिम्सटेक जलवायु–स्मार्ट कृषि, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं और ई–प्रमाणन एवं अंतर–संचालनीय भुगतान प्रणालियों जैसे डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा

बॉक्स 1: द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के ठोस परिणाम

- गहन, डेटा–आधारित अनुसंधान, साक्ष्य–आधारित अनुशंसाओं और सुविचारित नीतिगत सारांशों के माध्यम से जानकारी युक्त नीतिगत ढांचे
- क्षेत्रीय राजनयिकों, अधिकारियों, अनुसंधानकर्ताओं और युवा नेताओं का क्षमता विकास ताकि वे वैश्विक और क्षेत्रीय संवादों में अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से शामिल हो सकें
- विविध क्षेत्रों में शैक्षणिक, विकासात्मक और नीति–स्तरीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए सीमा–पार संस्थागत संबंधों को मजबूत बनाना; और
- प्रमुख उप–क्षेत्रों में भारत की सॉफ्ट पावर और रणनीतिक उपस्थिति, जो साझा विकास और पारस्परिक सम्मान के लिए प्रतिबद्ध साझेदार के रूप में देश की छवि सुदृढ़ करती है।

देने का एक मंच बन गया है। इस बीच, थाईलैंड के बायो–सर्कुलर–ग्रीन (बीसीजी) अर्थव्यवस्था के ढांचे को स्थिरता के मॉडल के रूप में रेखांकित किया गया है। बंगाल की खाड़ी में भारत–जापान सहयोग ने जापानी निवेश, भारत के संपर्क लक्ष्यों और बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति को जोड़ते हुए एक त्रिपक्षीय दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाया है, जिससे औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाएं मज़बूत हुई हैं और व्यापार सुगम हुआ है। ये कदम रणनीतिक कनेक्टर और क्षेत्रीय संयोजक के रूप में हमारे निकटवर्ती पड़ोस की भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो बंगाल की खाड़ी के पार कनेक्टिविटी, आर्थिक समावेशन और सांस्कृतिक कूटनीति को जोड़ते हैं।

(बाएं से) राजदूत श्री मोहम्मद गुलाम सरवर, महासचिव, सार्क; और राजदूत एस.टी. देवरे, अध्यक्ष आरएसी, आरआईएस।

महासागरों की स्थिरता और सुरक्षा तथा हिंद–प्रशांत के लिए पहल

जहां तक महासागरों का प्रश्न है, स्थिरता एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनी हुई है, जिसमें महासागरीय शासन और नीली अर्थव्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। 2024–2025 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अमेरिका द्वारा सह–आयोजित नीली अर्थव्यवस्था संगोष्ठियों ने समुद्री संसाधन प्रबंधन और जलवायु–अनुकूल विकास पर संवाद को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया। महासागरों के

भारत–इंडोनेशिया कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्षों पर नीतिगत संवाद

भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त डॉ. अनिल सूकलाल, आरआईएस में

बदलते सुरक्षा परिदृश्य के लिए सहयोग की आवश्यकता है। आरआईएस ने इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ समुद्री सुरक्षा संवादों में भाग लिया, जिनमें समुद्री क्षेत्र जागरूकता और सहकारी निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया गया। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी स्टडीज (केआईआईपीएस) के साथ साझेदारी में, क्वाड और भारत–अमेरिका संबंधों पर एक पैनल ने हिंद–प्रशांत रणनीतिक संरचना में सामंजस्य का पता लगाया। साथ ही, तटीय लचीलेपन के लिए नवीन नीतिगत विकल्पों पर चर्चा करने और सागर के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाते हुए समुद्री ज्ञान व्याख्यान श्रृंखला ने महासागर अनुसंधान और टिकाऊ समुद्री प्रथाओं को मजबूती प्रदान की। अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस पर विशेषज्ञ कॉमेंट्रीज ने अवैध रूप से मछलियां पकड़ने से निपटने और समुद्री खतरों के पारिस्थितिकीय प्रभावों को दूर करने को रेखांकित किया। दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर, वैश्विक शासन में दक्षिणी दृष्टिकोणों का समर्थन करते हुए, अनुसंधान और नीतिगत वकालत के एक केंद्र के रूप में उभरा है।

सांस्कृतिक सहयोग और विरासत कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करना

सांस्कृतिक सहभागिता नीतिगत सहयोग के लिए सेतु और उत्प्रेरक दोनों का काम करती है। द्विपक्षीय स्तर और क्षेत्रीय ढांचों में देशों के साथ सांस्कृतिक सहयोग संवादों के माध्यम से, सांस्कृतिक समझ को बढ़ाया गया है। नेपाल में युवाओं तक पहुंच ने विरासत के संरक्षण और क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित छात्र–नेतृत्व वाली पहलों को प्रोत्साहित किया। सांस्कृतिक कूटनीति पर संक्षिप्त जानकारी के माध्यम से नीति पर केंद्रित अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया, जिससे विदेश नीति में इसकी भूमिका रेखांकित हुई। विरासत कूटनीति भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही है। सीईओ स्पीक्स श्रृंखला के तहत, नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के प्रमुख लीडर के साथ चर्चा के दौरान, आरआईएस का उद्देश्य समुद्री विरासत के संरक्षण और मेकांग क्षेत्र के साथ पूर्वोत्तर भारत के ऐतिहासिक संबंधों के एकीकरण को बढ़ावा देना था। ये प्रयास सांस्कृतिक धारणाओं को रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जोड़ते हैं। नवंबर 2024 में, भारत–इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भारत–इंडोनेशिया नीतिगत संवाद में, समुद्री विरासत के साथ–साथ रामायण और महाभारत की साझा सांस्कृतिक कथाओं का भी कीर्तिगान किया गया, साथ ही रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक संपर्क में सहयोग को भी बढ़ावा दिया गया।

परिणाम और प्रभाव

आरआईएस ने इन पहलों के माध्यम से, हिंद–प्रशांत और ग्लोबल साउथ में ज़िम्मेदार और दूरदर्शी संयोजक के रूप

में भारत की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है। संस्था के निरंतर प्रयासों ने जानकारी युक्त नीतिगत ढांचे के निर्माण, क्षमता विकास, सीमा पार संस्थागत संबंधों को बढ़ाने और भारत की सांस्कृतिक और रणनीतिक उपस्थिति को मज़बूत बनाने में योगदान दिया है। भविष्य पर गौर करते हुए, आरआईएस हिंद–प्रशांत, आसियान, बिम्सटेक और मेकांग–गंगा सहयोग (एमजीसी) के बारे में अपने भौगोलिक फोकस को मजबूत करना जारी रखेगा, साथ ही अपनी सहभागिताओं के विषयगत दायरे को भी व्यापक बनाएगा। स्थिरता और जलवायु कार्रवाई, डिजिटल परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियां, भौतिक और लोगों के आपसी संपर्क, सांस्कृतिक कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र इसके एजेंडे के केंद्र में बने रहेंगे। साथ ही, आरआईएस कम निवेश, उच्च प्रभाव वाले डिजिटल और स्वास्थ्य–तकनीक समाधानों विशेषकर जमीनी स्तर पर समुदायों को सीधे लाभान्वित करने वाले समाधानों को बढ़ावा देकर अपनी भूमिका को बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है। यह त्रिपक्षीय और लघुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर भी ज़ोर देगा जो समान विचारधारा वाले साझेदारों को साझा चुनौतियों का समाधान करने और नए अवसरों को उजागर करने के लिए एक साथ लाएगा। ऐसा करके, आरआईएस परस्पर विश्वास, साझा समृद्धि और सतत विकास पर आधारित एक मजबूत, समावेशी और परस्पर संबद्ध क्षेत्रीय व्यवस्था को आकार देने में योगदान देने की आकांक्षा रखता है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ के निदेशक डॉ. शैलेश नायक आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ

आरआईएस द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

- 13 मई 2024 को सार्क क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 25 जून 2024 को बिम्सटेक क्षेत्र में कृषि व्यापार से संबंधित तालमेल : क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन पर क्षेत्रीय सम्मेलन।
- 10 अप्रैल 2024 को क्वाड और भारत–अमेरिका संबंध : हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए निहितार्थों पर पैनल चर्चा।
- 7 जून 2024 को सार्क क्षेत्र में उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 7 मई 2024 बांग्लादेश के मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने आरआईएस का दौरा किया।
- 15 अप्रैल 2024 अंतरराष्ट्रीय नदी बेसिन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर व्याख्यान।
- 27 अगस्त 2024 भारत–इंडोनेशिया के बीच कूटनीतिक संबंधों पर नीतिगत संवाद।
- 26–27 सितंबर 2024 को कोलकाता में दूसरा हिंद–प्रशांत आर्थिक सम्मेलन (आईपीईसी)।
- 11 जुलाई 2024 को सीईओ स्पीक्स श्रृंखला: नीली अर्थव्यवस्था का मार्ग निर्देशन : महासागर विज्ञान से लेकर टिकाऊ भविष्य तक।
- 12 सितंबर 2024 को सीईओ स्पीक्स श्रृंखला: भारत की सांस्कृतिक संबद्धता।
- 28 सितंबर 2024 को नेपाल और भारत के बीच भावी सहयोग पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 7 अगस्त 2024 को भारत–न्यूजीलैंड संबंध: सम्भावित व्यापार और संभावनाए विषय पर चर्चा।
- 7–8 नवंबर 2024 को सिंगापुर में भारत–आसियान को पुनः वैश्वीकरण को अंगीकार करना चाहिए: डॉ. जयशंकर : आईएनटीटी का 8वां दौर
- 18 दिसंबर 2024 आरआईएस में प्रोफेसर अनिल सूकलाल: भारत–दक्षिण अफ्रीका साझेदारी।
- 20 नवंबर 2024 को टोक्यो में भारत–जापान आर्थिक संबंधों पर आरआईएस–आईडीई–भारतीय दूतावास की संगोष्ठी।
- 21–29 नवंबर 2024 को नेपाली प्रतिनिधियों के लिए ग्लोबल साउथ और विकास सहयोग के बारे में विशेष पाठ्यक्रम।
- 10 मार्च 2025 को समुद्री व्याख्यान श्रृंखला: सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) तथा विकासात्मक साझेदारियां।
- 14 फरवरी 2025 को भारत में नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाएं और अमेरिका के साथ सहयोग के संभावित अवसर विषय पर संगोष्ठी।
- 19 मार्च 2025 को ग्लोबल साउथ के लिए काम कर रहे हैं भारत–वियतनाम विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।
- 9 जनवरी 2025 को आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर मलेशिया का विजन और प्राथमिकताएं विषय पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 25 फरवरी 2025 को भारत–म्यांमार आर्थिक संबंधों पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 18 फरवरी 2025 को कुवैत, ओमान और सऊदी अरब के राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम।

प्रमुख प्रकाशन

रिपोर्ट

- इंटरनेशनल कॉफ्रेंस ऑन बे ऑफ बंगाल एंड इंडिया–जापान इकोनॉमिक रिलेशन्स (परिणाम दस्तावेज़) आरआईएस, नई दिल्ली, 2024
- इंडिया–इंडोनेशिया पार्टनर्शिपः अ रिन्यूड अंडरस्टेंडिंग, न्यू ऑर्पच्यूनिटीज एंड क्रिटिकल स्टेप्स अहैड आरआईएस, नई दिल्ली, 2024
- बिम्सटेक सिनर्जीज इन एग्रीकल्चरल ट्रेडः प्रमोटिंग रिजनल ग्रोथ (परिणाम दस्तावेज़) आरआईएस, नई दिल्ली, 2024
- नेविगेटिंग अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशनः एजेंडा फॉर आसियान–इंडिया कोऑपरेशन, आरआईएस–एआईसी, नई दिल्ली 2025.

आरआईएस नीतिगत सारांश

- #116: म्यांमार–इंडिया पार्टनरशिप फॉर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सुजीत समद्दर द्वारा
- #114: कल्चर फॉर रीजनल कोहेशन एंड ग्लोबल एंगेजमेंटः द केस ऑफ आसियान सम्पा कुंडू द्वारा

एआईसी कॉमेंट्रीज

- #49: अनरेवलिंग द इंडिया–आसियान कोऑपरेशन पैराडाइम फॉर नॉन ट्रेडिशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रैट्स, जोएफ बी. संतारीटा द्वारा
- #50: एन्हैंसिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू सस्टेनेबल एग्री–फूड सिस्टम्सः लेसन्स फ्रॉम इंडिया एंड आसियान इनिशिएटिव्स, डॉ. कल्पना शास्त्री द्वारा
- #51: आसियान–इंडिया कोऑपरेशन –अ न्यू परस्पेक्टिव बेस्ड ऑन द अंडरवॉटर डोमेन अवेयरनेस (यूडीए) फ्रेमवर्क, डॉ. अर्नब दास द्वारा
- #53: नेविगेटिंग अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशनः एजेंडा फॉर द आसियान–इंडिया पार्टनरशिप, डॉ. एस. जयशंकर द्वारा
- #55: अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ आसियान–इंडिया रीजनल वैल्यू चैन (आरवीसी) 4.0 डॉ. विटाडा अनुकूनवत्ताका द्वारा
- #54: टुवर्ड्स अ रेसिलिएंट पार्टनरशिपः आसियान एंड इंडिया इन अ ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल लैंडस्केप डॉ. काओ किम हॉर्न द्वारा

एआईसी कार्य पत्र

- #12: बिल्डिंग अप अ रेजिलिएंट फूड सिक्योरिटी इकोसिस्टम्सः पोटेंशियल कोलेबरेशन बिट्वीन मलेशिया–इंडिया, फातिमा मोहम्मद अरशद द्वारा
- #13: अनरेवलिंग म्यांमार्ज सिक्युरिटी लैंडस्केपः अंडरस्टेंडिंग इट्स इम्प्लीकेशंस एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स, सम्पा कुंडू द्वारा
- #14: 75 यर्स ऑफ इंडिया–इंडोनेशिया रिलेशनशिपः अ हिस्टॉरिकल पर्सपेक्टिव, राजदूत गुरजीत सिंह द्वारा

लोकप्रिय लेख

- डे, प्रबीर. 2024 "द कमिंग ट्वेंटी फर्स्ट आसियान –इंडिया समिट एंड वे फॉरवर्ड", द इकोनॉमिक टाइम्स, 8 अक्टूबर 2024

6 विज्ञान नीति और प्रौद्योगिकी शासन

आज की परस्पर संबद्ध और तेज़ी से बदलती दुनिया में, जिस तरह हम जलवायु परिवर्तन और जन स्वास्थ्य संकटों से लेकर डिजिटल असमानता और भू–राजनीतिक तनावों तक, जटिल वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में विकास और शासन के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) की भूमिका तेज़ी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। विकास से परे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भू–राजनीतिक रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव के महत्वपूर्ण साधन हैं। तकनीकी–राष्ट्रवाद का उदय, आपूर्ति श्रृंखलाओं का हथियार के रूप में इस्तेमाल और अग्रण ी प्रौद्योगिकियों के संबंध में बढ़ती प्रतिस्पर्धा वैश्विक शासन संरचना और उसकी गतिशीलता को

आकार दे रही है। चौथी औद्योगिक क्रांति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रसार को भी गति दी है। साथ ही, दुनिया जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी खतरों, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता की हानि, डिजिटल असमानता आदि जैसी चुनौतियों का सामना भी कर रही है, जिनके लिए वैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता है। इसी जटिल परिदृश्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) का शासन विकसित हो रहा है। इस प्रकार, न्यायसंगत पहुंच, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी प्रशासन ढांचे के साथ–साथ उत्तरदायी और जिम्मेदार विज्ञान नीति का निर्माण आवश्यक है।

भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता और विकासोन्मुख नीतिगत फोकस, तकनीकी रूप से उन्नत और पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और बहुपक्षीय सहयोग के बीच की खाई को पाटने में विशेष रूप से मदद करने की स्थिति में है। यह वैश्विक एसटीआई विमर्श को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। आरआईएस ने विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए, भविष्य पर केंद्रित और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और विज्ञान कूटनीति पर नीतिगत अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एसटीआईपी और सार्वजनिक पहुंच

पिछले वर्ष के दौरान, एसटीआई नीति और प्रशासन में आरआईएस के कार्य की विशेषता व्यापक सहभागिता रही है, जो नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों और राजनयिकों को एक साथ लायी। क्षमता निर्माण से लेकर विज्ञान कूटनीति में सैद्धांतिक अन्वेषणों तक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष नीति पर नीतिगत सलाह, बायो–सिमिलर्स पर संवाद से लेकर 5जी कनेक्टिविटी पर आउटरीच तक, आरआईएस ने समावेशी, सुलभ और भविष्य के लिए तैयार नीतिगत ढांचे को आकार देने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता मज़बूत की है।

आरआईएस का कार्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और शासन के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए गहन रूप से प्रतिबद्ध है। इस वर्ष एसटीआई शासन के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाओं में आरआईएस के योगदान का विस्तार हुआ, विशेष रूप से जब वे अग्रणी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों से संबंधित हों। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम व्याख्यान ने उल्लेखनीय रूप से, सार्वजनिक पहुंच और तथ्यपरक वैज्ञानिक विमर्श को बढ़ावा देने की दिशा में आरआईएस के निरंतर प्रयासों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। पचास से अधिक व्याख्यानों के साथ, एसटीआईपी फोरम ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और उनकी पहुंच और समानता पर चर्चाओं का आयोजन करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का सिलसिला जारी रखा। अप्रैल, 2024 में, डीएसटी के सचिव, प्रोफेसर अभय करंदीकर ने समावेशी विकास के लिए एसटीआई का लाभ उठाने के बारे में जानकारी प्रदान की। उनके व्याख्यान 'कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड इन 5जी एंड बियॉन्ड' ने लो मोबिलिटी लार्ज सेल (एलएमएलसी) और 5जी मानक जैसे ग्रामीण दूरसंचार नवाचार में भारत के योगदान पर प्रकाश डाला साथ ही यह भी दर्शाया कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) जैसे वैश्विक मंचों के साथ नीतिगत सहभागिता सिक प्रकार दूरगामी विकासात्मक प्रभाव वाले नवाचार उत्पन्न कर सकती है।

प्रोफेसर अभय करंदीकर आरआईएस में

क्षमता निर्माण और युवाओं को संलग्न करना: भविष्य में निवेश करना

आरआईएस इस बात को स्वीकार करता है कि समावेशी और सतत नवोन्मेषी इकोसिस्टम को आकार देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विचारकों और व्यवसायियों की अगली पीढ़ी में निवेश करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान उठाए गए कई कदमों ने युवाओं और करियर के शुरुआती दौर वाले पेशेवरों के बीच क्षमता निर्माण के एक मंच का कार्य किया। इनमें शिव नादर यूनीवर्सिटी के पूर्व स्नातक विद्यार्थियों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र भी शामिल है। विज्ञान कूटनीति को सिद्धांतिक रूप से समझने पर केंद्रित इस संवाद में प्रतिभाशाली युवाओं को कूटनीतिक धारणाओं के बारे में गहराई से विचार करने हेतु प्रेरित किया गया। आरआईएस के संकाय और विशेषज्ञ पैनलिस्टों ने विदेशी मामलों में विज्ञान की और अधिक सिद्धांत–आधारित समझ की आवश्यकता पर बल दिया।

इसी प्रकार, आरआईएस ने केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की मेज़बानी की तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों और ग्लोबल साउथ में भारत की स्थिति पर चर्चा को बढ़ावा दिया। इस सत्र में आरआईएस के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के एजेंडे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आर्थिक कूटनीति, विकास वित्त और व्यापार नीति जैसे मुद्दों से जोड़ने पर इसके द्वारा लंबे अर्से से दिए जा रहे ज़ोर पर गहन चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने परमाणु सहयोग, सैन्य प्रणालियों में एआई और जी–20 के साथ भारत की सहभागिता जैसे विषयों पर आरआईएस के विद्वानों के साथ बातचीत की, जिससे अकादमिक अनुसंधान और रणनीतिक दूरदर्शिता के बीच पुल बनाया जा सका।

ये कार्यक्रम क्षमता निर्माण के प्रति आरआईएस के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। वर्ष के दौरान, आरआईएस ने अपने संकाय सदस्यों के क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया। आरआईएस के संकाय सदस्यों ने यूएनआईटीएआर और जिनेवा साइंस डिप्लोमेसी एंटिसिपेटर द्वारा आयोजित जिनेवा साइंस डिप्लोमेसी वीक में भाग लिया, और विज्ञान कूटनीति पर पाठ्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिन्हें अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस और द वर्ल्ड अकादमी ऑफ साइंस द्वारा क्रमशः जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड और ट्रिएस्टे, इटली में आयोजित किया गया। आरआईएस के संकाय सदस्यों ने ट्रैक 1.5 डायलॉग, ब्रिक्स और प्रोडिजीज़ और प्रीपेयर्ड जैसी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में भी आरआईएस का प्रतिनिधित्व किया।

विज्ञान कूटनीति

विज्ञान कूटनीति, आरआईएस की व्यापक रणनीतिक दृष्टि में प्रमुख आधार के रूप में निरंतर महत्वपूर्ण बनी हुई है। आरआईएस, एसटीआई कूटनीति पर डीएसटी उपग्रह केंद्र की मेजबानी करता है। अंतरराष्ट्रीय संवादों को आकार देने से लेकर भारत और ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण और न्यायसंगत वैश्विक सहयोग में उनकी भूमिका पर केंद्रित ढांचों की संकल्पना करने तक, आरआईएस ने इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य किया है। पीएम कर्मयोगी मिशन के अंतर्गत, भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग के लिए

आरआईएस के प्रतिनिधियों ने इन–स्पेस के अधिकारियों को "एक्सपेंडिंग इंडियाज़ कमर्शियल स्पेस सेक्टर फुटप्रिंट इंटरनेशनली" रिपोर्ट सौंपी

41

आरआईएस द्वारा विज्ञान कूटनीति पर ए लेवल 1 पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। इस पाठ्यक्रम को आईगॉट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विज्ञान कूटनीति में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, महानिदेशक ने जुलाई, 2024 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) द्वारा आयोजित लीड्स कार्यक्रम के दौरान 'विज्ञान कूटनीति के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व' विषय पर मुख्य भाषण दिया।

साल भर की गतिविधियां विद्यार्थियों के साथ सैद्धांतिक अन्वेषणों से लेकर शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और व्यवसायियों द्वारा चर्चाओं और योगदानों तक, साथ ही आरआईएस द्व ारा प्रकाशित ओपन एक्सेस जर्नल, साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू के प्रकाशन तक व्याप्त रहीं। विज्ञान नीति और कूटनीति पर पाक्षिक अपडेट प्रकाशित किए गए और 8000 से अधिक हितधारकों के साथ साझा किए गए।

वर्ष के दौरान, आरआईएस की नई आरंभ की गई सीईओ स्पीक्स श्रृंखला, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, कूटनीति और शासन के शोधकर्ताओं और व्यवसायियों पर केंद्रित रही। प्रोफेसर सुमा अथ्रे (आईआईटी दिल्ली) और डॉ. रुद्र चौधरी (कार्नेगी इंडिया) के साथ बातचीत ने इस बारे में अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किए कि वैश्विक प्रौद्योगिकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए कूटनीति, उद्योग और शिक्षा जगत किस प्रकार एकजुट हो सकते हैं। इसने प्रौद्योगिकी के भू–राजनीतिक आयामों के बारे में गहन चर्चा की और डेटा शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वैज्ञानिक साझा साधनों के वैश्विक स्वामित्व के बीच परस्पर क्रिया को प्रदर्शित किया। इन संवादों ने तकनीकी नीति और कूटनीति के बढ़ते क्षेत्र को रेखांकित किया, जिनमें आरआईएस विशेष रूप से दक्षिण–दक्षिण सहभागिता को प्राथमिकता देने वाले सहयोगपूर्ण ढांचों के माध्यम से अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

उभरते क्षेत्रों में नीतिगत अनुसंधानः जैव प्रौद्योगिकी, एआई, और अंतरिक्ष शासन एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग

जैव प्रौद्योगिकी और जैव–अर्थव्यवस्था पर आरआईएस का अनुसंधान उभरते वैश्विक विकास घटनाक्रमों और राष्ट्रीय नीतिगत प्राथमिकताओं, दोनों को दर्शाता है। इस कार्यक्रम ने जैव–अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के ढांचों, बायो–सिमिलर्स के लिए नियामक दृष्टिकोणों, और सिंथेटिक बायोलॉजी, जीनोम एडिटिंग और डिजिटल अनुक्रम सूचना के शासन का परीक्षण किया है। ये अध्ययन जैव विविधता ढांचों और सतत एवं नवाचार–आधारित विकास पर उनके प्रभावों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में संलग्नता का उद्देश्य तकनीकी प्रगति को नैतिक उत्तरदायित्व और न्यायसंगत पहुंच के साथ जोड़ना है। आरआईएस ने बायो–सिमिलर विनियमन ढांचों का मूल्यांकन करते हुए नीतिगत संवाद आयोजित किए। इस संदर्भ में, अक्टूबर, 2024 में बायो–सिमिलर्स पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। चर्चाएं सिंथेटिक बायोलॉजी, डिजिटल अनुक्रम सूचना, जैव–अर्थव्यवस्था, जीन ड्राइव और जीनोम एडिटिंग, जैव विविधता, और सीबीडी/सीपीबी पर केंद्रित रहीं। आरआईएस उभरती और अग्रणी प्रौद्योगिकियों की एक श्रृंखला में शैक्षणिक और नीतिगत नेतृत्व प्रदान करना जारी रखे हुए है। इस दिशा में, आरआईएस स्कोपस–इंडेक्स्ड और समकक्ष–समीक्षित एशियन बायोटेक्नोलॉजी डेवेलपमेंट रिव्यू प्रकाशित करना जारी रखे हुए है। इन पहलों का उद्देश्य जैव–नैतिकता, नियामक सामंजस्य और जैव–चिकित्सा नवाचार में ग्लोबल साउथ नेतृत्व पर बातचीत को बढ़ावा देना है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आरआईएस का कार्य उभरती प्रौद्योगिकियों के संचालन, नैतिक ढांचों, ज़िम्मेदारीपूर्ण उपयोग और एआई अपनाने से रोज़गार पर पड़ने वाले प्रभाव सहित इसके सामाजिक–आर्थिक आयामों पर केंद्रित है। यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमर्श में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है और एआई विनियमन, नैतिकता और सहयोगपूर्ण एआई के अवसरों के बारे में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करता रहा है। यह संलग्नता न केवल उच्च–स्तरीय विषयगत चर्चाओं में आरआईएस की उपस्थिति, बल्कि इसके नीतिगत अनुसंधान की मान्यता में भी परिलक्षित हुई है। आरआईएस के महानिदेशक ने जुलाई, 2024 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित 2024 ग्लोबल इंडिया एआई मिड–ईयर समिट के दौरान 'सहयोगपूर्ण एआई वैश्विक साझेदारी' पर एक सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने अगस्त, 2024 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित एआई और ज्ञान प्रबंधनः अकादमिक–उद्योग शिखर सम्मेलन के दौरान 'ज़िम्मेदार एआई विकास सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत और नियामक उपाय' विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता भी की। जुलाई, 2024 में मॉस्को, रूस में आयोजित ब्रिक्स सिविल फ़ोरम के दौरान आरआईएस के संकाय सदस्य ने 'नई प्रौद्योगिकियों का नैतिक पक्ष' विषय पर एक सत्र में एआई शासन और नैतिकता पर चर्चा की। आर्थिक समीक्षा 2023–24 में एआई और रोज़गार पर आरआईएस के नीतिगत सारांश

का उपयोग किया गया, जो भारत की नीतिगत मुख्यधारा के लिए इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

एआई गवर्नेंस और जिम्मेदार नवाचार पर आरआईएस संकाय की कॉमेंट्रीज और विश्लेषण राष्ट्रीय विचार मंचों पर भी प्रदर्शित हुए, जिससे विशेषज्ञ और सार्वजनिक दोनों प्रकार की चर्चा को आकार देने में संस्थान की भूमिका पुष्ट हुई है। इसके अतिरिक्त, एआई गवर्नेंस के क्षेत्र में, कार्यशालाओं, प्रकाशन और परियोजनाओं में आरआईएस की भागीदारी ने नैतिकता और पहुंच की बारीकियों की पड़ताल की। उदाहरण के लिए, एआई एथिक्स फॉर द ग्लोबल साउथ पर आरआईएस संकाय के प्रकाशन ने इस जागरूकता को प्रतिबिंबित किया कि तकनीकी शासन को वैश्विक रूप से समन्वित होने के साथ–साथ स्थानीय संदर्भ के अनुकूल भी होना चाहिए। आरआईएस ने संस्थागत निरीक्षण में विभिन्न क्षमताओं और एआई नीतिगत उपकरणों में मानवाधिकार ढांचों को केंद्र में रखने के महत्व को रेखांकित किया। 19–20 फरवरी, 2025 के दौरान आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ, आरआईएस एआई के संबंध में अपना काम जारी रखने तथा अधिक से अधिक सार्वजनिक पहुंच और हितधारक सहभागिता में योगदान देने के लिए प्रयासरत है।

वर्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत परिणामों में से एक, 'एक्सपेंडिगि इंडियाज़ कमर्शियल स्पेस सेक्टर फुटप्रिंट इंटरनेशनली' शीर्षक वाली रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और प्रस्तुत करना रहा। इन–स्पेस द्वारा संचालित इस अध्ययन ने वैश्विक स्तर पर अपनी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार करने की भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए बाज़ार के अवसरों और नीतिगत रणनीतियों का गहन विश्लेषण प्रदान किया। इस प्रयास ने तकनीकी–आर्थिक कूटनीति के प्रति आरआईएस की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया और भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नीति में यह एक अग्रणी योगदान के रूप में चिन्हित हुआ।

आरआईएस ने एसटीआई प्रशासन पर अंतरराष्ट्रीय सहयोगपूर्ण अनुसंधान में भी अपनी सहभागिता बढ़ाई है। यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित प्रोडिजीज़ परियोजना के अंतर्गत, आरआईएस डिजिटलीकरण और सतत विकास पर अनुसंधान में योगदान दे रहा है। होराइज़न यूरोप के अंतर्गत प्रीपेयर्ड परियोजना के अंतर्गत, आरआईएस अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान मंचों में सक्रिय भागीदारी के साथ, अनुसंधान के लिए नैतिक ढांचे विकसित करने में लगा हुआ है।

न्यायसंगतता, पहुंच और समावेशन

आरआईएस के मिशन का मूल आधार यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि विज्ञान, अपने सभी रूपों में, जनहित में कार्य करे। चाहे भारत की जी–20 अध्यक्षता को विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए या सामाजिक रूप से प्रासंगिक और सतत नवाचार के दृष्टिकोण से, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आरआईएस पहुंच, न्यायसंगतता और नैतिकता के आधार पर निर्मित शासन के ढांचों की वकालत करता है।

इसके अलावा, पहुंच, न्यायसंगतता और समावेशन के ढांचे में आरआईएस का योगदान विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर इसकी कार्ययोजना के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इसी के आधार पर, आरआईएस ने ज़िम्मेदार नवाचार और अग्रणी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया। आरआईएस संकाय ने 'रिस्पॉसिबल एआई ग्रोथ विद् सेफ्टी' जैसे प्रकाशनों और राष्ट्रीय जैव–नैतिकता सम्मेलन में भागीदारी के माध्यम से इस विमर्श में और योगदान दिया है। आरआईएस ने नैतिक रूप से सुदृढ़ और खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में व्यावहारिक रूप से कार्यान्वयन योग्य समावेशी और पूर्वानुमानित शासन के ढांचों की आवश्यकता पर बल देते हुए स्वास्थ्य सेवा में एआई पर चर्चा में योगदान दिया। पूर्वाग्रह कम करना, डेटा गोपनीयता, तथा एआई प्रणालियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य दायित्वों के बीच उभरते सामाजिक अनुबंध के मुद्दों पर ज़ोर दिया जाना भी अनिवार्य है।

वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व, ज्ञान तक पहुंच और मुक्त विज्ञान शासन पर आरआईएस में अनुभवजन्य और सैद्धांतिक कार्य इस बात को दोहराते हैं। आरआईएसएसटीआईपी फोरम व्याख्यान श्रृंखला, समकक्ष–समीक्षित पत्रिकाओं और कार्यक्रमों जैसे मंचों के माध्यम से समावेशन के प्रश्नों को मुख्यधारा के नीतिगत विमर्श में लगातार लाता रहता है।

नए तकनीकी युग के लिए नीति का पुनर्निर्माण

पिछले वर्ष आरआईएस द्वारा संचालित गतिविधियां विज्ञान, नीति, कूटनीति और शासन की गतिशीलता के साथ गहन सहभागिता का संकेत देती हैं। क्षमता निर्माण, सैद्धांतिक योगदान से लेकर वाणिज्यिक अंतरिक्ष नीति में भारत के प्रभाव के विस्तार तक, आरआईएस एक अद्वितीय नीतिगत अनुसंधान एजेंडे को आकार दे रहा है जो स्थानीय और वैश्विक, दोनों ही स्तरों पर प्रासंगिक है।

सरकारों, शिक्षा जगत, सिविल सोसायटी और उद्योग जगत के साथ साझेदारी में, आरआईएस एसटीआई शासन के एक ऐसे दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है, जो पूर्वानुमानात्मक, समावेशी और परिवर्तनकारी है। ऐसा करके, यह न केवल वैश्विक विकास एजेंडा निर्धारित करने में भारत के नेतृत्व की पुष्टि करता है, बल्कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के लिए भी गुंजायश बनाता है।

भविष्य में, आरआईएस समावेशन और स्थिरता के प्रवर्तक के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में काम करना जारी रखेगा। आरआईएस दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर, साक्ष्य–आधारित संवाद को सक्षम बनाकर और नैतिक ढांचों को बढ़ावा देकर समावेशी और भविष्य के लिए तैयार विज्ञान नीति और प्रौद्योगिकी शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अनुसंधान, कूटनीति और विकास के संगम पर, आरआईएस भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण की सेवा करना जारी रखेगा और तेजी से जटिल होती वैश्विक व्यवस्था में अपने अनुसंधान के माध्यम से नवाचार और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन कायम करने के लिए नीतिगत ढांचों में योगदान देता रहेगा।

आरआईएस द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

- 9 अप्रैल 2024 को 52वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान : कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड इन 5जी एंड बियॉन्ड।
- 23 अप्रैल 2024को विज्ञान कूटनीति के बारे में सिद्धांत बनाना विषय पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 17 मई 2024 को सीईओ स्पीक्स : प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति को आगे बढ़ाना।
- 9 मई 2024 को अंतरराष्ट्रीय संबंधों और प्रौद्योगिकी का अन्वेषण विषय पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 20 नवंबर 2024 को भारत के वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष पदचिह्नों का इन–स्पेस तक विस्तार पर इंटरैक्टिव सत्र।
- 5 दिसंबर 2024 को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला।
- 28–29 जनवरी 2025 को स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : जिम्मेदार एआई की दिशा में मिलकर सीखना विषय पर कार्यशाला।
- 24 अक्टूबर 2024 को बायोसिमिलर विनियमन पर गोलमेज चर्चा।

प्रमुख प्रकाशन

if=dk;

- साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू, खंड 6 अंक 2
- एशियन बायोटेक्नोलॉजी रिव्यू खंड 29 अंक 1, मार्च 2024
- एशियन बायोटेक्नोलॉजी डेवेलपमेंट रिव्यू (जुलाई और अक्टूबर 2024)

आरआईएस नीतिगत सारांश

- #112: साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी: रिविजिटिंग पॉलिसी ऑप्शन्स फॉर ग्लोबल साउथ, डॉ. सब्यसाची साहा द्वारा

पत्रिका में लेख

- चतुर्वेदी, सचिन, कुमार, अमित. 2024. 'रिस्पॉन्सिबल एआई ग्रोथ विद् सेफ्टी: एक्सप्लोरिंग ग्लोबल एंड नेशनल पॉलिसी डिस्कोर्स'', जर्नल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, 61 (5), पृ. 231–237

7 पारंपरिक चिकित्सा और आरोग्य

भारत का पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र, जिसे आयुष क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, अब केवल सांस्कृतिक परम्परा और उपचार एवं आरोग्य के पारंपरिक संसाधन के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसे राष्ट्रीय विकास के प्रगतिशील प्रेरक के रूप में भी स्वीकार किया जाने लगा है। इस क्षेत्र का योगदान सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्रों में व्याप्त है। निवारक और समग्र देखभाल के अपने सिद्धांत के माध्यम से, यह हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं से सीध

ो जुड़ता है। यह क्षेत्र औषधीय पौधों और जड़ी–बूटियों पर आधारित दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्युटिकल्स के निर्यात में अभूतपूर्व विस्तार का साक्षी बना है; इसने सेवा प्रदान करने वाली अपनी श्रृंखलाओं को मजबूत किया है; देश में वेलनेस टूरिज्म को नए सिरे से परिभाषित किया है, जिससे ग्रामीण आजीविका, कुशल रोजगार के अवसर, व्यापार का विविधीकरण और जीडीपी को बढ़ाने में योगदान मिला है। वैश्विक स्तर पर टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों और सांस्कृतिक कूटनीति से संबंधित चर्चाओं में खुद के लिए अविभाज्य स्थान बनाते हुए तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग में भारत का दर्जा बढ़ाते हुए आयुष, देश की सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन गया है।

इस व्यापक पृष्ठभूमि में, फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडीसिन (एफआईटीएम), आयुष प्रणालियों के व्यापार, उद्योग और नीतिगत आयामों पर केंद्रित आरआईएस की एक इकाई है। यह आयुष के भीतर ज्ञान के एक मज़बूत इकोसिस्टम में योगदान देता है, स्वास्थ्य और आरोग्य के उभरते मानकों को प्रभावित करता है, और पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने के भारत के प्रयासों और भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में इसके विकास पथ में सहायता करता है। वित्त वर्ष 2024–25 में एफआईटीएम द्वारा किए गए प्रयासों की निरंतरता को निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य से देखा जा सकता है:

ज्ञान का सृजन

भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था में आयुष क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसने आरोग्य की समग्र अवधारण ाओं को राष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित विमर्श में गहराई से समाहित किया है। इसने उभरते वैश्विक मानकों और आधुनिक साक्ष्य–आधारित ढांचों के प्रति भी अनुकूलनशीलता प्रदर्शित की है, इस प्रकार वैश्विक सहयोग, अनुसंधान–संचालित नवाचारों और स्वास्थ्य सुरक्षा की नींव रखी गई है।

आयुष में नीति और बाज़ार को आकार देने के महत्वपूण र्ा साधन विचार, आंकड़े और साक्ष्य हैं। एफआईटीएम का फोकस सार्थक ज्ञान सृजन को समर्थन देने की प्रतिबद्ध ता पर केंद्रित रहा है, जो इस क्षेत्र में नीतिगत सहभागिता, अकादमिक विमर्शों और रणनीतिक प्रसार में सहायक होगा। यह कार्य आयुष प्रणालियों के मौजूदा और उभरते ढांचों और वैश्विक धारणाओं से संबंधित बौद्धिक अकादमिक योगदान और विश्लेषण का उपयोग करते हुए किया जाता है और यह बात इसके प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशन – ट्रेडिशनल मेडिसिन रिव्यू (टीएमआर) के दो खंडों में भी जारी रही।

दोनों खंडों में प्रकाशित सामग्री के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है, यथा:

- समकालीन स्वास्थ्य ढांचे में पारंपरिक उपचार पद्धतियों को समाहित करने पर जारी विमर्श को सुदृढ़ करना
- सुरक्षा मानकों के साथ ही साथ औषधीय पौधों के निर्यात की व्यवहार्यता के निर्धारकों जैसे कि जैवसक्रिय अखंडता के संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना
- अश्वगंधा पर अर्थमितीय अध्ययन के माध्यम से हर्बल दवाओं के बाजार मूल्य निर्धारण में उतार–चढ़ाव के शासन–संबंधी निर्धारक (नीति और खरीद)।
- आयुष योगों को 'सुपरफूड्स' या निवारक आरोग्य उपकरणों के रूप में पुनः स्थापित करने के माध्यम से रणनीतिक बाजार अनुकूलन पर चर्चाएं प्रदर्शित करना
- आध्यात्मिक परंपराओं और एकीकृत विज्ञान और सिस्टम बायोलॉजी के बीच संबंधों पर दृष्टिकोण प्रदर्शित करके बहु–विषयक दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि।

उपचार और आरोग्य पर राष्ट्रीय और वैश्विक विमर्श को आकार देने में विज्ञान, नीति, व्यापार और नवाचार की भूमिका और प्रभाव को स्वीकार और प्रदर्शित करने वाले कथात्मक माध्यम की उपयुक्त आवश्यकता को समझते हुए एफआईटीएम ने नवंबर, 2024 में मासिक न्यूजलेटर 'आयुष वैभव' शुरू किया। इस प्रकाशन का उद्देश्य संचार का समय–संवेदी और गतिशील माध्यम बनाना है जो कई उप–क्षेत्रों में फैला हुआ है और उन्हें जोड़ता है तथा आयुष क्षेत्र की आवाज़ को मजबूत और प्रखर बनाता है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहभागिताओं, नवीन सफलताओं को उजागर करना, तुलनात्मक शिक्षाओं और क्षेत्र–व्यापी जागरूकता को बढ़ावा देना और जानकारी को सार्थक समझ में बदलने में मदद करना है।

आयुष वैभव को आयुष कूटनीति, हितधारक जुड़ाव, तकनीकी नवाचारों और सार्वजनिक एवं निजी दृष्टिकोणों और धारणाओं पर नज़र रखने वाले महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। यह नीति निर्माताओं, घरेलू नियामकों, अकादमिक और शोध विद्वानों, और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित विविध दर्शकों को लक्षित करता है। इसके पांच अंक (नवंबर, 2024– मार्च, 2025) प्रकाशित हुए, जिनमें विविध वर्गों के समूह के माध्यम से, विविध विषयों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें विशेषकर निम्नलिखित विषय शामिल

आयुष वैभव का विमोचन

रहे, लेकिन वे केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- .आयुष के अंतर्गत संस्थागत और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना
- आयुष अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार
- औषधीय पौधों का संरक्षण और स्थायित्व
- आयुष के लिए नियामक ढांचे और वित्तीय समावेशन का व्यापक दायरा
- नीति के लिए केंद्रित एजेंडा
- निर्यात विश्लेषण और बाज़ार के रुझान

सामूहिक रूप से, ये दोनों प्रकाशन आयुष क्षेत्र में विचार नेतृत्व तक ज्ञान पहुंचाने तथा नीति एवं उद्योग जगत की प्रगति और नवाचारों को वास्तविक समय में फैलाने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार इसकी वैश्विक सहभागिता बढ़ाते हुए भारत की आरोग्य अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसके मजबूत योगदान को प्रदर्शित करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एफआईटीएम द्वारा किया जा रहा अखिल भारतीय आयुष सेवा क्षेत्र अध्ययन, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और आरोग्य सुविधाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों का एक संरचित मानचित्रण करता है। यह अध्ययन आयुष सेवा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के प्रतिष्ठानों की संख्या, आकार और भौगोलिक वितरण; राजस्व के स्वरूप और रोजगार; घरेलू–विदेशी ग्राहक मिश्रण; और उनके द्वारा सबसे अधिक प्रदान की जाने वाली चिकित्सा पद्धतियों पर केंद्रित है। इस कार्य का उद्देश्य एमएसएमई को सहायता, मान्यता और गुणवत्ता के मार्ग, वेलनेस टूरिज्म रणनीति और आयुष सेवाओं के बीमा समावेशन हेतु आवश्यक साक्ष्यों को मानकीकृत सुविधा प्रोफ़ाइल के साथ जोड़कर सूचित करना है।

भारत की पारंपरिक चिकित्सा कूटनीति को आगे बढ़ाना

आयुष, दुनिया भर में स्वास्थ्य साझेदारी स्थापित करने की दिशा में भारत की सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण तत्व बनकर उभरा है। यह तथ्य कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के दर्शन और पद्धतियां ग्लोबल साउथ के कई देशों में प्रतिध्वनित होती हैं, इन देशों के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के मार्ग प्रशस्त करती हैं। औषधीय आदान–प्रदान के साथ–साथ वेलनेस टूरिज्म का बढ़ता क्षेत्र उपरोक्त बातों का प्रमाण है। द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों और डब्ल्यूएचओ की पहलों में आयुष की बढ़ती उपस्थिति के साथ, भारत महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और वैश्विक आरोग्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एफआईटीएम की पहलों ने आयुष को व्यापार, उद्योग और सतत विकास से जोड़कर भारत की पारंपरिक चिकित्सा कूटनीति की रणनीतिक ताकत को बढ़ाया है।

एफआईटीएम ने आरआईएस की दूसरी इकाइयों जैसे डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव (दक्षिण) और आसियान इंडिया सेंटर (एआईसी) के साथ मिलकर 23 जनवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में 'आयुष

और जामू पर भारत–इंडोनेशिया सहयोगः सतत जैव संसाधन प्रबंधन की प्रासंगिकता' शीर्षक से एक महत्वपूर्ण गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और यूनिवर्सिटी ऑफ पदजाजारन और यूनिवर्सिटी ऑफ उदयना बाली के सहयोग से आयोजित किया गया था।

23 जनवरी, 2025 को आयोजित किए गए इस कार्यक्रम ने इंडोनेशियाई स्वदेशी उपचार (जामू) और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आयुष) के क्षेत्रों में अनुभव साझा करने और अवसरों की पहचान करने का एक मंच प्रदान किया। इस आयोजन में दोनों देशों के अधिकारी, उद्योग जगत के हितधारक और विद्वान शामिल हुए। इसमें एकीकृत सेवा मॉडल, वेलनेस टूरिज्म और हर्बल संसाधन प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इसमें फार्माकोपिया रिकग्निशन और सुव्यवस्थित बाजारों तक पहुंच के लिए एमओयू की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए विनियामक ढांचों में अनियमितताओं पर भी चर्चा की गई। इंडोनेशियाई संस्थानों द्वारा भारतीय जीएसीपी प्रोटोकॉल और आपूर्ति श्रृंखला की ट्रेसेबिलिटी के ढांचों में दिलचस्पी दिखाए जाने सहित इस दौरान अनुसंधान में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

एफआईटीएम ने भारत की पारंपरिक चिकित्सा कूटनीति को मज़बूती प्रदान करने और अनुसंधान के निष्कर्षों को अमल में लाने के लिए विख्यात आयुष वैज्ञानिक पीठों, आयुष मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव, और साउथ सेंटर (जिनेवा) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ उच्च स्तरीय चर्चा आयोजित की।

इसके अलावा, दिसंबर 2024 में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस (डब्ल्यूएसी) मंच पर एफआईटीएम ने स्वास्थ्य प्रणाली के दृष्टिकोण से आयुर्वेद में शासन पर अपनी प्रस्तुति के ज़रिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेदिक हितधारकों के एक बड़े नेटवर्क के साथ चर्चा की।

उपरोक्त के अलावा, एफआईटीएम का अफ्रीका में पारंपरिक चिकित्सा पर अध्ययन, जो एक बहु–राष्ट्रीय नीति और बाजार के परिदृश्य के अध्ययन का अभ्यास है, भारत और अफ्रीका के बीच पारंपरिक चिकित्सा के ज़रूरी बाजार, विनियामक ढांचे और सहयोग के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अध्ययन द्वारा व्यापार/नवाचार के रास्ते, फार्माकोपिया के मानकों का संदर्भ लेने के अवसरों और प्राथमिक विनियामक व्यवस्थाओं की पहचान करके अफ्रीकी महाद्वीप में आयुष की मौजूदगी बढ़ाने में मदद करेगा।

नीति और बहु–हितधारक सहभागिता

भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की रोग–निवारक, स्वास्थ्य–प्रवर्धक और समग्र स्वास्थ्य सेवा के विजन में आयुष की केंद्रीय भूमिका को सभी हितधारकों द्वारा तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। यद्यपि नीतिगत स्तर पर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और बीमा कवरेज के संदर्भ में आयुष की सहभागिता के दायरे को व्यापक बनाने की संभावनाओं पर केंद्र स्तर पर निरंतर विचार–विमर्श जारी है। वहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और संस्थागत ढांचों में आयुष को समाहित करने की राज्य–स्तरीय रणनीतियां नीतिगत नवाचारों को प्रदर्शित करती हैं। इस दिशा में मंत्रालय के फोकस को सशक्त बनाने के लिए एफआईटीएम का कार्य एक मूल्यवान योगदान है, जो साक्ष्य–आधारित सिफारिशें और रणनीतिक अंतर्दृष्टियां तैयार करने में सहायक है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) में आयुर्वेद को औपचारिक रूप से शामिल करने की आयुष मंत्रालय की पहल को एफआईटीएम ने महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। एफआईटीएम ने मंत्रालय की रणनीतिक क्रय समिति के साथ मिलकर आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं की एक विस्तृत सूची के लिए प्रति इकाई दरें निर्धारित करने हेतु एक व्यापक लागत निर्धारण प्रक्रिया का नेतृत्व किया। आर्थिक रूप से कमज़ोर 120 मिलियन भारतीयों की सहायता के उद्देश्य सहित केंद्र द्वारा प्रायोजित इस स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रम में इन मानकीकृत दरों को शामिल किया जाना था।

इस साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोण ने उन पैकेज दरों के विकास में सहयोग किया, जिनका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के ढांचे के भीतर आयुर्वेदिक सेवाओं के प्रावधान को संस्थागत रूप देना था। इसके अलावा, एफआईटीएम ने हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों में सारगर्भित और जानकारी–आधारित सुझाव प्रदान किए, जिससे अंतिम सिफारिशों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता को बढ़ावा दिया जा सके।

एफआईटीएम की भरोसेमंद नीतिगत परामर्शदाता की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने जून 2024 में नई दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए उससे महत्वपूर्ण भागीदारी और रणनीतिक सुझाव मांगे। यह संगोष्ठी डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा की अनुसंधान प्राथमिकताएं निर्धारित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। एफआईटीएम

आयुष और जामू में भारत–इंडोनेशिया सहयोग पर गोलमेज चर्चा में प्रतिष्ठित पैनलिस्ट

के सदस्यों ने बौद्धिक विमर्शों की प्रमुख धारणाएं तय करने में योगदान दिया, ताकि पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित व्यावहारिक और क्रियान्वित किए जा सकने वाले उद्देश्य तैयार किए जा सके।

एफआईटीएम के हाल के नीतिगत सारांश 'ट्रेडिशनल मेडिसिन इन साउथ अफ्रीका : प्रॉस्पेक्ट्स फॉर आयुष' ने महाद्वीप में मानकों द्वारा संचालित आयुष की उपस्थिति स्थापित करने के लिए प्रमाण–आधारित और लागू करने योग्य कार्ययोजना प्रस्तुत की। यह सारांश बाजार में प्रवेश से जुड़े जोखिमों को कम करता है तथा मांग और नियमों को एसएएचपीआरए की उत्पाद आवश्यकताओं और एएचपीसीएसए की व्यावसायिक निगरानी रेखांकित करते हुए प्रस्तावों को उपभोक्ता संरक्षण और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्देशित करता है। यह सारांश मानकों के समन्वय की दिशा में कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में मदद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि एमएपी की आपूर्ति श्रृंखलाएं पता लगाने योग्य और अनुपालन योग्य हैं, और प्रशिक्षण और अनुसंधान पर सहयोग कर रही हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए और भरोसेमंद, उच्च–मूल्य वाले आयुष व्यापार को बढ़ावा देते हुए भारत की पारंपरिक चिकित्सा कूटनीति को सशक्त बनाने के लिए यह सारांश प्रवासियों तक पहुंच, ज़िम्मेदार वेलनेस–टूरिज्म के संबंध, और नियामक और वैज्ञानिक आदान–प्रदान जैसे बड़े पैमाने पर किए जा सकने वाले कार्यों को प्राथमिकता देता है। यह दक्षिण अफ्रीका को एक आदर्श बाजार के तौर पर पेश करता है।

निष्कर्ष

आयुष, अर्थव्यवस्था और रोज़गार सृजन, वैश्विक व्यापार में विविधता लाने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को सुदृढ़ करने के तरीकों से भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत के व्यापक विकास सहयोग और विकास अर्थव्यवस्था के ढांचों की पृष्ठभूमि में, एफआईटीएम पारंपरिक चिकित्सा को एक रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। ज्ञान, नीति और व्यवहार को जोड़ने के अपने प्रयासों के माध्यम से, एफआईटीएम कूटनीतिक पहुंच, सतत व्यापार और स्वास्थ्य शासन के क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है। साथ ही भारत को एक ऐसी 'ज्ञान अर्थव्यवस्था' के रूप में आगे बढ़ाता है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देती है।

आरआईएस द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

- 23 जनवरी 2025 को सतत जैव संसाधन प्रबंधन की प्रासंगिकता" विषय पर गोलमेज चर्चा।
- 24 अक्टूबर, 2024 को आयुष वैभव का विमोचन।

प्रमुख प्रकाशन

पत्रिकाएं

- ट्रेडीशनल मेडिसिन रिव्यू
- खंड 4 अंक 1 अप्रैल 2024
- खंड 4 अंक 2 अक्टूबर 2024
-

नीतिगत सारांश

- रु115: ट्रेडीशनल मेडिसिन इन साउथ अफ्रीका: प्रोस्पेक्ट्स फॉर आयुष नम्रता पाठक और संकेत चव्हाण द्वारा

आयुष वैभव

- खंड 1 अंक 1 नवंबर 2024
- खंड 1 अंक 2 दिसंबर 2024
- खंड 2 अंक 1 जनवरी 2025
- खंड 2 अंक 2 फरवरी 2025
- खंड 2 अंक 3 मार्च 2025

8 अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- नीति आयोग द्वारा 9 अप्रैल 2024 को "विकसित भारत / 2047 के लिए प्रेरक के रूप में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार" विषय पर आयोजित विचार–विमर्श बैठक में संबोधन
- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा 15 अप्रैल 2024 को आयोजित मध्य–कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के चरण–ट में 'अंतर्विभाजक क्षेत्रः वैश्वीकृत दुनिया में भू–अर्थशास्त्र और भू–राजनीति को नेविगेट करना' पर प्रस्तुति दी।
- दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल सेंटर फॉर एप्लाइड सिस्टम्स साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईसीएएसएसएसडी) द्वारा 20 अप्रैल 2024 को आयोजित आईसीएएसएसएसडी के दूसरे रिसर्च स्कूल में 'लाइफ़ के साथ जीडीपी से आगे बढ़नाः प्रणालीगत मानकों और तौर–तरीकों पर फिर से विचार करना' पर मुख्य भाषण दिया।

- सीआईआई ग्लोबल इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समिट में सीआईआई द्वारा 23 अप्रैल को 'भविष्य के विकास के लिए नवोन्मेष, आईपी और निरंतर विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) के बीच तालमेल बनाना' में 'विकसित भारत /2047 : नवाचार, आईपी और एसडीजी के बीच अंतर्संबंध' विषय पर सत्र में पैनलिस्ट।
- बर्लिन में 5 मई 2024 को ग्लोबल सॉल्यूशंस समिट 2024 में चाइना–वेस्ट डायलॉग द्वारा आयोजित 'एक्सेलरेटिंग रिफॉर्म्स टू द इंटरनेशनल डेट ट्रीटमेंट सिस्टम : रेकंमेडेशन्स टू द जी–20' पर सत्र में पैनलिस्ट।
- बर्लिन में 6 मई 2024 को ग्लोबल सॉल्यूशंस समिट 2024 में 'सामाजिक–पारिस्थितिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए मार्ग तलाशना' विषय पर सत्र में वक्ता।
- बर्लिन में 6 मई 2024 को ग्लोबल सॉल्यूशंस समिट 2024 में टी–20 टास्क फोर्स 4: सतत विकास के लिए व्यापार और निवेश – डब्ल्यूटीओ और जी–20 की भूमिका पर सत्र में वक्ता।
- बर्लिन में 6 मई 2024 को काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा आयोजित जीएसआई समिट में 'जी–20–टी–20 जलवायु कार्रवाई और सतत विकास निरंतरता सुनिश्चित करना' विषय पर गोलमेज चर्चा में भाग लिया।
- बर्लिन में 7 मई 2024 को काउंसिल फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम–सॉल्विंग (सीजीपी) की वार्षिक बैठक में भाग लिया।
- रोम में 14 मई को एलयूआईएसएस यूनिवर्सिटी के सहयोग से इस्टिटुटो अफ़ारी इंटरनेशनल (आईएआई) और इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पोलिटिकल स्टडीज (आईएसपीआई) के साथ संयुक्त रूप से आयोजित टी–7 इटली समिट ऑन जी–7 एंड द वर्ल्ड: रिबिल्डिंग ब्रिजिज के दौरान 'टास्क फोर्स 4 मीटिंग ऑन साइंस एंड डिजिटलाइजेशन फॉर अ बैटर फ्यूचर डिजिटलाइजेशन' में भाग लिया।
- रोम में 14 मई को एलयूआईएसएस यूनिवर्सिटी के सहयोग से इस्टिटुटो अफ़ारी इंटरनेशनल (आईएआई) और इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पोलिटिकल स्टडीज (आईएसपीआई) के साथ संयुक्त रूप से आयोजित 'टी–7 इटली समिट : ऑन जी–7 एंड द वर्ल्ड: रिबिल्डिंग ब्रिजिज के दौरान 'टी–7 इटली समिट : चैलेंजिस ऑफ डिजिटलाइजेशन' पर सत्र में प्रस्तुति दी।
- आईआईटी दिल्ली में 16 मई 2024 को 'आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाना : घरेलू उद्योग और प्रौद्योगिकी को सुरक्षित करना' विषय पर संगोष्ठी में 'व्यापार के माध्यम से उपनिवेशीकरण' में पैनलिस्ट और 'सीमा पार रुपये में नामित वस्तु विनिमय व्यापार को सक्षम बनाना' पर पैनल चर्चा का संचालन किया।
- ओईसीडी डेवेलपमेंट सेंटर द्वारा 21 मई 2024 को पेरिस में 'चुनौतीपूर्ण समय में एलडीसी स्नातक पर पुनर्विचार की आवश्यकता' विषय पर आयोजित सेमिनार में चर्चा की।
- सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट (सीजीडी) और एजेंस फ्रांसेइस डु डेवलपमेंट (एएफडी) द्वारा संयुक्त रूप से 23 मई 2024 को पेरिस में आयोजित ऐट द फ्यूचर ऑफ द ओडीए वर्कशॉप में 'टूवर्ड अ पोस्ट–ओडीए वर्ल्ड : व्हॉट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट मैटर?' विषय पर सत्र में संबोधन।
- इंडोनेशिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा 6 जून 2024 को इंडोनेशिया में आयोजित रोड टू प्लेटिनम जुबली ऑफ एशियन– अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस' में 'एशिया अफ्रीका वी वॉन्ट : एम्पॉवरिंग द ग्लोबल साउथ बाइ लीवरेजिंग द बंडंग स्पिरिट' में पैनलिस्ट।
- बेन गुएरिर, मोरक्को में 9–10 जून को मोहम्मद टप पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी (यूएम6पी) के साथ सह–आयोजित पेरिस पीस फोरम (पीपीएफ) की स्प्रिंग मीटिंग 2024 में ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 एंड इम्प्लीकेशन्स ऑन 'फेयर ट्रांजिशन्स : अ व्यू फ्रॉम पार्लियामेंट्स' सत्र में पैनलिस्ट।
- काहिरा, मिस्र में 11–12 जून 2024 को न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) द्वारा आयोजित नेविगेटिंग न्यू

होराइजन्स पर एनडीबी सेमिनार में दक्षिण–दक्षिण सहयोग के माध्यम से वैश्विक विकास को बढ़ाना' विषय पर पैनल का संचालन किया।

- काहिरा, मिस्र में 12 जून 2024 को 'विविध संकटों के दौर में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बदलती गतिशीलता' विषय पर आयोजित विशेषज्ञ पैनल चर्चा में पैनलिस्ट
- मैंगलोर में 15 जून 2024 को मैंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 42वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में "सतत विकास के लिए जीवनशैलीः विश्वविद्यालय, थिंक–टैंक कनेक्ट की संभावना" विषय पर दीक्षांत भाषण दिया।
- यूनेस्को द्वारा 17 जून 2024 को पेरिस में आयोजित एनुअल मैनेजमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन्स (एमओएसटी) फोरम 2024 में आरंभिक भाषण दिया
- यूनेस्को द्वारा 17 जून 2024 को पेरिस में 'जलवायु, डिजिटल और आर्थिक परिदृश्य में वांछनीय भविष्य की परिकल्पना करना' विषय पर आयोजित पैनल में पैनलिस्ट
- यूनेस्को द्वारा 18 जून 2024 को पेरिस में आयोजित एमओएसटी कार्यक्रम की अंतर–सरकारी परिषद (आईजीसी) के असाधारण सत्र में मुख्य भाषण दिया
- बिम्सटेक सचिवालय की ओर से नियुक्त प्रख्यात व्यक्तियों के समूह (ईपीजी) के साथ बिम्सटेक सचिवालय द्वारा 25 जून 2024 को भविष्य की दिशा पर आयोजित बिम्सटेक बैठक (ऑनलाइन) में भाग लिया
- एनडीसी द्वारा 2 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय/वैश्विक वित्तीय विकास में नए वित्तीय संस्थानों के प्रभाव पर व्याख्यान दिया।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा 3 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इंडिया एआई समिट में वैश्विक साझेदारी के लिए सहयोगपूर्ण एआई पर एक सत्र का संचालन किया।
- स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 4 जुलाई 2024 को आईआईसी, नई दिल्ली में आयोजित स्वदेशी संगम – कल आज और कल' में वक्ता।
- 10 जुलाई 2024 को आयोजित बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक (बीएनपीटीटी) तकनीकी सत्र– प्प (खाद्य श्रृंखला) की छठी बैठक में वक्ता(ऑनलाइन) ।
- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) द्वारा आईएनएसए, नई दिल्ली में 11 जुलाई 2024 को आयोजित आईएनएसए–एनसीजीजी लीड्स–जुलाई 2024 कार्यक्रम के दौरान 'ग्लोबल लीडरशिप थॉट साइंस डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन' विषय पर व्याख्यान दिया।
- एसकेओसीएच द्वारा 13 जुलाई 2024 को आईएचसी, नई दिल्ली में आयोजित 98वें एसकेओसीएच शिखर सम्मेलन में विकासशील भारत के लिए सूचकांकः वैश्विक उपयोग के लिए भारतीय सूचकांक पर प्रस्तुति दी।
- रियो डी जेनेरियो में जी–20 ब्राज़ील के विकास कार्य समूह (डीडब□ल्यूजी) की चौथी बैठक के अवसर पर 17 जुलाई 2024 को जीएएलईआरआई साइड इवेंट में 'लाइफ अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तनः असमानता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान' के दौरान स्वागत भाषण और संदर्भ स्थापित किया।
- आईआईसी, नई दिल्ली में सीआईईयू द्वारा 26 जुलाई 2024 को आयोजित 'एजेंडा फॉर मोदी 3.0 ऑन डिकोडिंग यूनियन बजट 2024' पर गोलमेज चर्चा में पैनलिस्ट।
- ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग द्वारा 5 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग नई दिल्ली में आयोजित 'एसीआईएआर दक्षिण एशियाः अवसर और चुनौतियां' विषय पर गोलमेज चर्चा में वक्ता।
- नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा 6–8 अगस्त 2024 को आयोजित बिम्सटेक बिजनेस समिट में 'ब्लू इकोनॉमी और माउंटेन इकोनॉमी के बीच तालमेल तलाशना' विषय पर सत्र में पैनलिस्ट।
- आईसीएई द्वारा 07 अगस्त 2024 को एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित 'विकास को प्रोत्साहनः सार्वजनिक व्यय से संबंधित निर्णय भारत और अफ्रीका में कृषि परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार आकार दे रहे हैं' विषय पर चर्चा में पैनलिस्ट।

- औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान द्वारा 9 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 'औद्योगिक नीति, हरित परिवर्तन और 21वीं सदी में ग्लोबल साउथ का उदय' विषय पर व्याख्यान दिया।
- मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हब में 12 अगस्त 2024 को भारत में जी–20, एसडीजी और सार्वजनिक नीति पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित (ऑनलाइन) किया।
- इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय और सारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस द्व ारा 14 अगस्त 2024 को आईआईसी, नई दिल्ली में एआई और ज्ञान प्रबंधन पर संयुक्त रूप से आयोजित शिखर सम्मेलन में 'सुरक्षा, संरक्षा और विषय सामग्री शुद्धता के साथ जिम्मेदार एआई विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति और नियामक उपाय' विषय पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता की।
- सीईबीआरआई द्वारा 10 सितंबर 2024 को आयोजित ब्राजील जी–20 साइड इवेंट में 'जलवायु और विकास के बीच तालमेल' विषय पर वक्ता (ऑनलाइन) ।
- आरएन काओ अकादमी, गुरुग्राम में 11 सितंबर 2024 को इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी स्टडीज बैंगलोर द्वारा आयोजित चाइना लेक्चर सीरीज में 'एक्सटेंट ऑफ चाइनाज़ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स इन्क्लूडिंग ग्रांट्स, लोन्स, करेंसी स्वाप्स, ट्रेडिंग आईएन रेनमिनबी' पर व्याख्यान दिया।
- साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल अफेयर्स (एसएआईआईए) और नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस (एनएमएसजी) के साथ साझेदारी में ओडीआई द्वारा 12 सितंबर 2024 (ऑनलाइन) को आयोजित 'शेपिंग साउथ अफ्रीकाज़ जी–20 प्रेसीडेंसी' कार्यशाला में पैनलिस्ट।
- एक्सेंचर इंडिया द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में 27 सितंबर 2024 को आयोजित बेल्जियम के सबसे बड़े बैंक बेल्फ़ियस के बोर्ड सदस्यों को संबोधित किया।
- बैंकॉक में 1 अक्टूबर 2024 को रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा आयोजित बहु–हितधारक सम्मेलन– "द रॉकफेलर फाउंडेशन एशिया एक्सचेंज 2024" में बैक टू क्लासरूम? स्ट्रेंग्थनिंग द कैपेसिटी ऑफ स्टेट एक्टर्स ऑन अप्रोच फॉर क्लाइमेट चेंज' पर सत्र में पैनलिस्ट।
- पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय के तहत लिस्बन में 7 अक्टूबर 2024 को आयोजित कैमोस – इंस्टीट्यूट दा कोऑपरेशन ई दा लिंगुआ, आई.पी. और ओईसीडी विकास सहयोग निदेशालय (डीसीडी) के सहयोग से ब्राजीलियन कोऑपरेशन एजेंसी (एबीसी) द्वारा आयोजित त्रिपक्षीय सहयोग पर जी–20 तकनीकी बैठक में भाग लिया।
- पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय और ओईसीडी विकास सहयोग निदेशालय (डीसीडी) द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को लिस्बन में त्रिकोणीय सहयोग पर आयोजित 8वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक में 'एशियाई भागीदारों के साथ त्रिकोणीय सहयोग' पर पैनल का संचालन किया।
- नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द्व ारा 4 अक्टूबर 2024 को आयोजित तीसरे कौटिल्य आर्थिक कॉन्फ्रेंस "द इंडियन एरा" के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।
- मास्को में 9 अक्टूबर 2024 को रूस के वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क फॉर फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में 'कोऑपरेशन इन टैक्स मैटर्स विद् स्पेसिफिक फोकस ऑन टू– पिलर सोल्यूशन' पर प्रस्तुति दी।
- मास्को में 9 अक्टूबर 2024 को रूस के वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क फॉर फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में 'सुदृढ़ और भविष्यवादी बुनियादी ढांचे के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण' पर प्रस्तुति दी।
- आरबआई द्वारा नई दिल्ली में 13–14 अक्टूबर 2024 को आयोजित "सेंट्रल बैंकिंग ऑन क्रॉस रोड्स" पर आरबआई/90हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।
- विदेश मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में मध्य एशियाई देशों के लिए आयोजित तीसरे विशेष पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों के समक्ष ''ग्लोबल ट्रेड एंड कनेक्टिविटीः इनोवेशन एप्रोचेज विद् आईएमईसी'' पर व्याख्यान दिया।

- मानव विकास संस्थान द्वारा रांची में 26 अक्टूबर 2024 को आयोजित 23वें आईएएसएसआई वार्षिक सम्मेलन में इन्क्लूसिव इंडिया/100: पीपुल–पॉलिसीज–इकोनॉमी पर पैनल की अध्यक्षता की।
- मानव विकास संस्थान द्वारा रांची में 25 अक्टूबर 2024 को आयोजित 23वें आईएएसएसआई वार्षिक सम्मेलन में ''इंटरसेक्टिंग पाथ्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, एंड वीमन्स एम्पावरमेंट'' पर आईएएसएसआई– सीईएसएस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर विशेष भाषण दिया।
- विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में 28 अक्टूबर 2024 को आयोजित "जी–20 ब्राजील शिखर सम्मेलन से अपेक्षाएं" विषय पर गोलमेज चर्चा में भाग लिया।
- आईडीओएस, आईपीईए, टी–20 ब्राज़ील, एमजीजी और प्रॉडोजीज द्वारा 13 नवंबर 2024 को आयोजित '2024 के चुनाव वर्ष के बाद सतत विकास पर वैश्विक सहयोग' विषय पर टी–20 शिखर सम्मेलन के साइड इवेंट में विशेषज्ञ इनपुट प्रदान किए।
- फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जनेरो के ब्राजीलियन हाई स्टडीज इंस्टीट्यूट, आईपीईए, ईआरआईए, एमआईजीए–जीएसआरसी, सीएसआईएस, आरआईएस, एसआईआईए और एनईपीएडी द्वारा रियो में 13 नवंबर 2024 को सह–आयोजित 'इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिजास्टर रेसिलिएंस: फोर्टिफाइंग ग्लोबल साउथ इकोनोमीज थ्रू डायनामिक गवर्नेंस सोल्यूशन्स' पर जी–20 ब्राजील के समर्थन में एक उच्च स्तरीय कार्यशाला में 'बियोंड ऐड: अ जी–20 रोडमैप फॉर क्लाइमेट एंड डिजास्टर फाइनेंस' पर पैनल में पैनलिस्ट।
- आईपीईए द्वारा रियो में 13 नवंबर 2024 को जर्नल जी–20 चैलेंजिज एंड द प्रो–टेम्पोर ब्राजीलियन प्रेसीडेंसी' के विशेष जी–20 संस्करण के शुभारंभ पर आयोजित टी–20 साइड–इवेंट में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 18 नवंबर 2024 को ओआरएफ और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्व ारा संयुक्त रूप से आयोजित सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग में ग्लोबल थिंक टैंक कम्युनिटी के साथ मंत्रिस्तरीय रात्रिभोज गोलमेज चर्चा में संक्षिप्त आरंभिक संबोधन।
- इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज, नई दिल्ली और एमएएचई, मणिपाल द्वारा मणिपाल में 23 नवंबर 2024 को अंडरस्टेंडिंग चाइना इन अ टरबुलेंट वर्ल्ड: जियोपोलिटिकल कंटेस्टेशन एंड कोऑपरेशन विषय पर आयोजित 17वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना स्टडीज में ''मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीफेसिटेड पार्टनरशिप्स: न्यू डायनामिक्स ऑफ कंटेस्टेशंस एंड कोऑपरेशन' विषय पर समापन भाषण दिया।
- सीपीडी द्वारा 1 दिसंबर 2024 को आयोजित (ऑनलाइन) सीपीडी जर्नी: सीपीडीज थर्टीएथ एनिवर्सिरी में 'क्षेत्रीय और वैश्विक विमर्श को प्रभावित करना' सत्र में प्रतिष्ठित चर्चाकार।
- इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा 05 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली आयोजित जल–ऊर्जा–पर्यावरण संबंध की ट्रांसवर्सलिटी को समझना विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 4 दिसंबर 2024 को फाइनेंशियल टाइम्स के प्रमुख वर्चुअल इवेंट ग्लोबल बोर्डरूम के 8वें संस्करण में "उभरते बाजार: अंतरराष्ट्रीय मामलों को नया रूप देने में ग्लोबल साउथ की भूमिका" पर पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2024 को प्रभासाक्षी की 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'भारत की भू–राजनीतिक चुनौतियां और अवसर' पर प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 5 दिसंबर 2024 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण और स्कैन पोर्टल 'अन्न चक्र', के लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया।
- काठमांडू में एसएडब्ल्यूटीईई द्वारा 12 दिसंबर 2024 को "अनलीशिंग ऐन इक्विटेबल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन इन साउथ एशिया" शीर्षक से आयोजित पंद्रहवें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस

एक्सवी) में 'ट्रेड एंड इंडस्ट्रीयल पॉलिसिज इन अ टाइम ऑफ क्लाइमेट एक्शन'' शीर्षक से आयोजित पूर्ण सत्र में 'इंडिया डेमोन्स्ट्रेट्स हॉउ इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस शुड वर्कः द रोल ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग'' पर प्रस्तुति दी।

- ईईएससी द्वारा यूरोपीय संघ–भारत रणनीतिक साझेदारी, विदेश संबंध खंड के बारे में 12 दिसंबर 2024 को आयोजित यूरोपियन इकॉनोमिक एंड सोशल कमिटी ओपिनियन के फ्रेमवर्क में सुनवाई के दौरान 'भारतीय परिप्रेक्ष्य' के बारे में जानकारी प्रदान की। (ऑनलाइन)।
- हरियाणा के अंबाला में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा 21 दिसंबर 2024 को आयोजित भारतीय आर्थिक संघ (आईईए) के 107वें वार्षिक सम्मेलन में 'विकसित भारत के लिए रोडमैपः कई स्तरों पर लक्ष्य और चुनौतियां' विषय पर प्रस्तुति दी।
- हरियाणा के अंबाला में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित भारतीय आर्थिक संघ (आईईए) के 107वें वार्षिक सम्मेलन में 'व्यापार नीति, एफटीए और मूल्य श्रृंखला' पर एक विशेष सत्र की अध्यक्षता की।
- गुड़गांव में आईसीएफएआई बिजनेस स्कूल द्वारा 7 जनवरी 2025 को आयोजित आईबीएस एमिनेंट लीडरशिप सीरीज में 'नई आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में भारत की भूमिका' पर व्याख्यान दिया।
- नई दिल्ली में सीआईईयू, डालबर्ग और भारत क्लाइमेट फोरम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'नेट–जीरो एवं आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा देना' विषय पर भारत क्लाइमेट फोरम 2025 के अवसर पर 'हरित महत्वाकांक्षाओं के लिए वैश्विक भागीदारीः प्रौद्योगिकी, व्यापार और संसाधन' पर पैनल चर्चा का संचालन किया।
- नई दिल्ली में 14 जनवरी 2025 को सीएसआईआर–एनआईएससीपीआर के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभावी जीएंडडी गवर्नेंस के लिए विज्ञान–प्रौद्योगिकी–नवाचार संकेतकों को संरेखित करना विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (एसटीआईआईजी–2025) में 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संकेतकों की पुनर्कल्पनाः 2047 में विकसित भारत के लिए विकास एजेंडे की ओर' पर स्थापना दिवस व्याख्यान दिया।
- मुंबई में 18 जनवरी 2025 को ब्लिट्ज द्वारा आयोजित "विकसित भारत / 2047" विषय पर आयोजित ब्लिट्ज इंडिया कॉन्क्लेव में 'विकसित भारत' पर प्रस्तुति दी और ब्लिट्ज इंडिया बिजनेस वीकली का शुभारंभ किया गया।
- यूएनडीपी और इंटीग्रेटेड पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स नेटवर्क (आईपीपीएन) द्वारा 22 जनवरी 2025 को 'आईपीपीएन नॉलेज कैफेः हाउ कैन इंटीग्रेटेड पॉलिसीज डिलिवर द यूएन कॉमन अप्रोचेज टू बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन' विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रतिभागियों को संबोधित किया।
- कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर द्वारा सिकंदराबाद में 24 जनवरी 2025 को आयोजित 48वें हायर एयर कमांड कोर्स (एचएसीसी) में 'राष्ट्रीय सुरक्षा के एक तत्व के रूप में आर्थिक सुरक्षाः भारत के लिए चुनौतियां और अवसर' विषय पर प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 3 फरवरी 2025 को नीति आयोग द्व ारा आयोजित ब्रूगल स्कॉलर्स के साथ गोलमेज चर्चा में 'बहुपक्षवाद और भूराजनीति', तथा 'प्रौद्योगिकी और डिजिटल गवर्नेंस' विषय पर सत्रों में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 6 फरवरी 2025 को नीति आयोग द्व ारा "विकसित भारत/2047 की ओरः अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारियां और कानून को मजबूत बनाना" विषय पर आयोजित सम्मेलन में 'प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत की वैश्विक साझेदारियों और संसाधन संबंधी मांगों को प्राप्त करने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करना' विषय पर पैनल का संचालन किया।
- युन्नान, चीन में चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा 10 फरवरी 2025 को आयोजित ग्लोबल साउथ एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम के दौरान 'विकास सहयोग में ग्लोबल साउथ की भूमिका' पर थीम आधारित चर्चाओं में भाग लिया।

- युन्नान, चीन में 11 फरवरी 2025 को ग्लोबल साउथ एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम के दौरान आयोजित 'विकास सहयोग में जी–20/टी–20 की भूमिका' पर एनईएसटी और आईडीओएस चर्चाओं में भाग लिया।
- विज्ञान भारती द्वारा आईआईटी, गांधी नगर के साथ मिलकर आयोजित भारत केंद्रित विजन पर आधारित "देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम में आवश्यक भारत केंद्रित दृष्टिकोण" पर दो दिवसीय विचार–मंथन सत्र में मुख्य वक्ता।
- प्रयागराज में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 16 फरवरी, 2025 को आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलनः कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन में 'मिशन लाइफ–सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना' पर प्रस्तुति दी।
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग, असम सरकार द्वारा गुवाहाटी में 25 फरवरी, 2025 को आयोजित 'एडवांटेज असम 2.0 – इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट' में 'एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट एक्ट फर्स्ट' सत्र में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 4 मार्च 2025 को एसएयू थॉट कैफे–ए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी लेक्चर सिरीज में 'आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और ग्लोबल साउथ का विचार' विषय पर आरंभिक व्याख्यान दिया।
- नई दिल्ली में द इंडिया फाउंडेशन द्वारा 17 मार्च 2025 को आयोजित 'प्रौद्योगिकी, व्यापार और टैरिफ की भूराजनीति' पर पैनल चर्चा में 'संक्रमण काल में व्यापार नीति' विषय पर प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार द्वारा 20 मार्च 2025 को 'भारत की उभरती सॉफ्ट पावरः रणनीतिक आयाम और वैश्विक पहुंच' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में 'विकास साझेदारी और भारत की सॉफ्ट पावर' पर प्रस्तुति दी।

प्रोफेसर एस के मोहंती

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित भारत चिली संयुक्त अध्ययन समूह की चर्चा बैठक में भाग लिया।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के साथ 17 जून 2024 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित भारत में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार पर चर्चा बैठक में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई, पीआरसीआई और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ नई दिल्ली में 25 जून 2024 को 'कृषि व्यापार में बिम्सटेक तालमेल पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन : क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना' का आयोजन किया और उसमें भाग लिया।
- नई दिल्ली में 25 जून 2024 को 'कृषि व्यापार में बिम्सटेक तालमेल पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन : क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना' में भाग लिया और 'बिम्सटेक क्षेत्र में कृषि की स्थितिः विकास के अवसर' पर सत्र में प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 28 जून 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा सचिव की अध्यक्षता में व्यापार सांख्यिकी में सुधार के लिए कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया और एफटीए वार्ता और ट्रेड डेटा गैप्स पर प्रस्तुति दी।
- 28 जून 2024 को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) अमेरिका के हैड ऑफ कैपिसिटी स्ट्रेंग्थनिंग को 'कृषि व्यापार में बिम्सटेक तालमेल पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन : क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना' पर रिपोर्ट सौंपी गई।
- इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) अमेरिका के हैड ऑफ कैपिसिटी स्ट्रेंग्थनिंग को 30 जून 2024 को बिम्सटेक क्षेत्र के

साथ भारत के कृषि व्यापार संबंधों पर मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 'भारत और उरुग्वे के बीच व्यापार पूरकताएं तलाशने के लिए संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन और भारत–मर्कोसुर पीटीए के विस्तार' पर व्यापक अध्ययन पर बैठक में भाग लिया।
- बांग्लादेश के ढाका में बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल (बिम्सटेक) सचिवालय द्वारा 9 जुलाई 2024 को आयोजित बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक (बीएनपीटीटी) की छठी बैठक में वेबएक्स के माध्यम से भाग लिया और बिम्सटेक क्षेत्र में कृषि व्यापार पर प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 26 जुलाई 2024 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ब्लू इकोनॉमी और आरआईएस के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा बैठक आयोजित की गई।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 1 अगस्त 2024 को वाणिज्य विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में भारत–अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के 19वें संस्करण में भारत–अफ्रीका व्यापार रणनीति पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।
- ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स द्व ारा 26 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक आयोजित समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) कार्यशाला में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए ब्लू इकोनॉमी पर कार्यशाला चर्चाओं का नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।
- सीजीआईएआर, वाशिंगटन डीसी के साथ अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कृषि–खाद्य व्यापार प्रसार कार्यक्रम में भाग लिया और 3 अक्टूबर, 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में बिम्सटेक क्षेत्र में कृषि व्यापार और निवेश पर प्रस्तुति दी।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा नई दिल्ली में 7 अक्टूबर 2024 को आयोजित व्यापार सांख्यिकी में सुधार के लिए की गई कार्रवाई/प्रगति पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक में भाग लिया और ट्रेड डेटा गैप्स पर चर्चा की।
- आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र और आईएसईएएस–यूसुफ इशाक इंस्टीट्यूट, सिंगापुर द्वारा सिंगापुर में 7 नवंबर 2024 को संयुक्त रूप से आयोजित आसियान–इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स (एआईएनटीटी) की 8वीं गोलमेज चर्चा में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया तथा कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं पर प्रस्तुति दी।
- चाइना स्टडी सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोपोलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेन्स), द्वारा मणिपाल, कर्नाटक में 23 नवंबर 2024 को अंडरस्टेंडिंग चाइना इन अ टरबुलेंट वर्ल्डः जियोपोलिटिकल कंटेस्टेशन एंड कोऑपरेशन विषय पर आयोजित 17वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना स्टडीज (एआईसीसीएस) में 'इम्पैक्ट ऑफ जियोपोलिटिकल फैक्टर्स ऑन इकोनॉमी एंड ट्रेड' विषय पर प्रस्तुति दी।
- अंबाला (हरियाणा) के महर्षि मार्कंडेश्वर (डीम्ड–टू–बी–यूनिवर्सिटी), मुलाना, द्वारा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित भारतीय आर्थिक संघ (आईईए) के 107वें वार्षिक सम्मेलन के व्यापार नीति, एफटीए और मूल्य श्रृंखलाओं पर विशेष सत्र में भाग लिया।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) नई दिल्ली द्वारा में 2 जनवरी 2025 को व्यापार सांख्यिकी के बारे में चर्चा के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया और ट्रेड डेटा गेप्स विषय पर प्रस्तुति दी।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 6 जनवरी 2025 को भारत की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए चिन्हित किए गए 20 महत्वपूर्ण देशों में भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक प्रकोष्ठ के अधिकारियों की चर्चा बैठक–रिट्रीट में भाग लिया।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 10 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में व्यापार सांख्यिकी पर चर्चा के लिए आयोजित की गई समीक्षा बैठक में भाग लिया।

- यूजीसी सेंटर फॉर मैरीटाइम स्टडीज, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी द्वारा भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से 'अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहः बहुआयामी परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और अंडमान एवं निकोबार द्व ीप समूह में अप्रयुक्त आर्थिक अवसरों के मानचित्रण पर प्रस्तुति दी। 29–30 जनवरी 2025 को पुड्डुचेरी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भारत के व्यापार केंद्र के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता पर एक शोध पत्र भी प्रस्तुत किया।
- आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 25 फरवरी 2025 को आयोजित पहली व्यापक आयुष डेटाबेस समिति की बैठक में भाग लिया और चर्चा की।
- कुरुक्षेत्र, हरियाणा में 27 फरवरी 2025 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडो–पैसिफिक (आईसीआईपीएस) द्वारा आईसीडब्ल्यूए के सहयोग से 'भारत और आईओआरएः आगे की राह' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया और आईओआरए में नीली अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तुति दी।
- भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए), नई दिल्ली द्वारा 25 मार्च 2025 को 'हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को उजागर करनाः आईओआरए के लिए आगे की राह' विषय पर आयोजित गोलमेज चर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और आईओआरए में नीली अर्थव्यवस्था का दोहनः विकास और स्थिरता विषय पर प्रस्तुति दी।

डॉ. सब्यसाची साहा

एसोसिएट प्रोफेसर

- पेरिस में 17–18 जून 2024 को यूनेस्को के मैनेजमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन्स (एमओएसटी) फोरम में भाग लिया।
- मॉस्को में 3–4 जुलाई 2024 को ब्रिक्स सिविल फोरम में समापन सत्र को संबोधित किया।
- भारतीय संसद के संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) द्वारा 9 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित "जीवनशैली और कल्याण के नए विकास प्रतिमानः सतत विकास के लिए जीवनशैली" पर एक कार्यशाला का संचालन।
- संसद टीवी पर 23 जुलाई 2024 को बजट–पूर्व चर्चा में शामिल हुए।
- 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा विज्ञान शिखर सम्मेलन के दौरान 13 सितंबर 2024 को आयोजित साइड इवेंट में –"आर्थिक विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार" विषय पर आयोजित वेबिनार में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में सेज पब्लिशर्स द्वारा 13 सितंबर 2024 को आयोजित "शोध पद्धति" पर चर्चा की।
- भुवनेश्वर में 20–21 सितंबर, 2024 को आईएनडीआईएएलआईसीएस और केआईआईटी द्व ारा आयोजित आईएनडीआईएएलआईसीएस वार्षिक सम्मेलन में पूर्ण सत्र में वक्ता के रूप में भाग लिया।

डॉ प्रियदर्शी दाश

एसोसिएट प्रोफेसर

- मॉस्को में 22–24 मई 2024 को आयोजित ब्रिक्स एकेडमिक फोरम में "ब्रिक्स में वित्तीय सहयोग" विषय पर प्रस्तुति दी।
- ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में टी–20 द्वारा 1–3 जुलाई, 2024 को आयोजित टास्क फोर्स–3 (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार) चर्चा में सह–अध्यक्ष के रूप में योगदान दिया।
- बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक (बीएनपीटीटी) की 9–10 जुलाई 2024 को आयोजित छठी बैठक में आभासी रूप से भाग लिया।
- मणिपुर यूनीवर्सिटी, इंफाल में 17 जुलाई 2024 को 'महिला नेतृत्व में विकासः एक गेम चेंजर' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में " भारत की जी –20 की अध्यक्षता में प्राथमिकता के

रूप में महिला नेतृत्व में विकास" पर आभासी रूप से चर्चा की।

- ब्रिटेन के कोलचेस्टर में यूनीवर्सिटी ऑफ एसेक्स द्वारा 22–23 जुलाई 2024 को आयोजित 'वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम और फिनटेक–सक्षम सेवाओं में व्यापार' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसएफएसआई), नई दिल्ली में 12 अगस्त 2024 को श्रीलंकाई राजनयिकों और अधिकारियों को "ब्लू इकोनॉमी" पर व्याख्यान दिया।
- "एशिया–अफ्रीका विकास गलियारा–हिंद–प्रशांत में विकास सहयोग के लिए रोडमैप" विषय पर 10 सितंबर 2024 को वॉक्सन यूनीवर्सिटी, हैदराबाद के छात्रों को ऑनलाइन व्याख्यान दिया।
- मास्को, रूस में 18–19 सितंबर 2024 को आयोजित ब्रिक्स ग्रीन सिटीज़ फ़ोरम में 'ग्रीन ट्रांसपोर्टः स्ट्रैटेजीज़ एंड द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ़ सिटीज़' और ' ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन ब्रिक्स सिटीज़' पर सत्रों में पैनलिस्ट और चर्चाकार के रूप में भाग लिया।
- कोलकाता में 26 सितंबर 2024 को आयोजित हिंद–प्रशांत आर्थिक सम्मेलन 2024 में "ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड फिनटेकः एप्लीकेशन्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज़" पर पैनलिस्ट के रूप में आभासी रूप से प्रस्तुति दी।
- आरआईएस में 28 सितंबर 2024 को नेपाल युवा नेताओं के कार्यक्रम के तहत नेपाल से आए सांसदों और नेताओं के समक्ष डिजिटल भुगतान पर प्रस्तुति दी।
- सेंट जोसेफ यूनीवर्सिटी, नागालैंड द्वारा 30 सितंबर 2024 को "नारी शक्तिः महिला विकास से महिला–नेतृत्व में विकास तक" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में आभासी रूप से विशेष वक्तव्य दिया।
- नई दिल्ली में 1 अक्टूबर, 2024 को आयोजित कोरिया–इंडिया फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवेलपमेंट में 'डिजिटलीकरण और फिनटेक समाधानों की भूमिकाः पूर्वोत्तर क्षेत्र के समावेशी विकास का एक तरीका' विषय पर विशेष टिप्पणी।
- मॉस्को में 9 अक्टूबर 2024 को आयोजित ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क फॉर फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में 'कोऑपरेशन इन टैक्स मैटर्स विद् स्पेसिफिक फोकस ऑन टू–पिलर सोल्यूशन'' पर प्रस्तुति दी।
- सिंगापुर में 7–8 नवंबर 2024 को आयोजित 8वें आसियान–इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक (एआईएनटीटी) सम्मेलन में "फिनटेक और सीमा पार भुगतान निपटान" पर प्रस्तुति दी।
- नीति आयोग में 12 नवंबर 2024 को पूर्वोदय राज्यों पर आयोजित विचार–मंथन सत्र में योगदान दिया।
- बर्लिन में 19–20 नवंबर 2024 को आयोजित चौथे भारत–जर्मनी संवाद में "भारत–जर्मनी वित्तीय सहयोग के लिए फिनटेक और नई संभावनाएं" पर प्रस्तुति दी।
- बैंकॉक में 27 नवंबर 2024 को आयोजित आरआईइन वार्षिक बैठक में "डिजिटल वित्त" पर प्रस्तुति दी।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक द्वारा 3 फरवरी 2025 को आयोजित 'शिक्षक प्रभावशीलता और व्यावसायिक विकास' विषय पर अल्पावधि कार्यक्रम के प्रतिभागियों को "उभरते सामाजिक–आर्थिक विकास की समस्याएं और प्राथमिकताएं : डेटाबेस और कार्यपद्धतियां" विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया।
- इस्तांबुल, तुर्की में मिडिल ईस्ट काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स और गल्फ इंटरनेशनल फोरम द्व ारा 6–7 फरवरी 2025 को आयोजित '(वैश्विक संपर्क के नए विमर्श की ओरः रणनीतिक गलियारों और साझेदारियों में खाड़ी क्षेत्र के नए क्षितिज' शीर्षक वाली कार्यशाला में "क्षेत्रीय आर्थिक गलियारेः भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारा" और "समावेशी विकास को बढ़ावा देने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका" विषय पर प्रस्तुति दी।
- आरआईएस में 17 फरवरी 2025 को आईएफएस प्रोबेशनर्स को "रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण और डिजिटल भुगतान की संरचना" विषय पर व्याख्यान दिया।

- आरआईएस और एसआईओएस द्वारा नई दिल्ली में 19 मार्च 2025 को आयोजित 'भारत–पश्चिम एशिया –यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी): नई उम्मीदें और नए अवसर' विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में "आर्थिक गलियारों का वित्त पोषण" विषय पर प्रस्तुति दी।
- असम विश्वविद्यालय, सिलचर द्वारा 29 मार्च 2025 को आयोजित 'युवा उत्सव 2025: युवा सहभागिता और नागरिक उत्तरदायित्व' में "विकास के लिए नीतिगत परिदृश्य : हाल के आकलन और भविष्य के बारे में दृष्टिकोण" विषय पर आभासी प्रस्तुति दी।

डॉ. पंकज वशिष्ठ

एसोसिएट प्रोफेसर

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक विज्ञान में पीएचडी/पीडीएफ विद्वानों के लिए शोध पद्धति और डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम के दौरान 03 अप्रैल 2024 को आयोजित एक सप्ताह के 'डिजिटलीकरण और नौकरियों का भविष्य: चुनौतियां, मुद्दे और शोध कार्यपद्धतियां' पर व्याख्यान दिया।
- महर्षि यूनिवर्सिटी, रोहतक के अर्थशास्त्र विभाग में 19 जून 2024 को 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार के वितरण संबंधी निहितार्थ: सैद्धांतिक समझ और अनुभवजन्य साक्ष्य' विषय पर व्याख्यान दिया
- केआईपीआरए द्वारा 26 जून 2024 को 'केन्या में औद्योगीकरण का भविष्य: बॉटम–अप आर्थिक परिवर्तन एजेंडा में औद्योगीकरण का मार्ग' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में "औद्योगीकरण के लिए आधार के रूप में एमएसई की स्थिति: भारत से सबक' पर प्रस्तुति दी।
- महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक में अर्थशास्त्र में अध्ययन बोर्ड में विशेष नामित के रूप में नियुक्त किया गया
- बर्लिन, जर्मनी में 20 नवंबर 2024 को आयोजित चौथी भारत–जर्मनी 1.5 ट्रैक रणनीतिक वार्ता में 'हिंद प्रशांत में भारत–जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना' विषय पर प्रस्तुति दी।
- मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित भारत–मलेशिया व्यापार सम्मेलन 2024 में 'भारत–मलेशिया संबंध: आर्थिक उपलब्धियां और चिंताएं' विषय पर प्रस्तुति दी।
- मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित भारत–मलेशिया व्यापार सम्मेलन 2024 में 'वैश्विक विकास और संबंधों को आकार देने में भारत की भूमिका' विषय पर प्रस्तुति दी।
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में 17 दिसंबर 2024 को 'भारत नेपाल व्यापार संधि की व्यापक समीक्षा' विषय पर प्रस्तुति दी।
- इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्ट्डीज, कोलकाता द्वारा 11 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति परबोवो सुबियांटो की भारत यात्रा पर आयोजित वेबिनार : 'भारत–इंडोनेशिया संबंधों में नया अध्याय', में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया ।
- नालंदा विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीस स्टडीज के विजिटिंग फैकल्टी नियुक्त किए गए।
- आरआईएस और एनईएनएपी द्वारा 10 मार्च 2025 को संयुक्त रूप से भारत–नेपाल संबंध: आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य पर आयोजित क्लोज डोर गोलमेज चर्चा में भारत–नेपाल आर्थिक संबंधों पर प्रस्तुति दी।

डॉ पी के आनंद

विजिटिंग फेलो

- भुवनेश्वर, ओडिशा में 20 फरवरी 2025 को नीति आयोग की राज्य सहायता मिशन पहल के तहत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति के संबंध में फास्ट–ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहरी प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन. 2024. "कोविड–19 पेंडेमिक एंड इमर्जेंस ऑफ इंटीग्रेटेड इनोवेशन सिस्टम'' रिइमेजनिंग इनोवेशन सिस्टम्स इन द कोविड एंड पोस्ट–कोविड वर्ल्ड में लखविंदर सिंह और के. जे. जोसेफ, (संपा), रूटलेज। पृष्ठ 104–120

चतुर्वेदी, सचिन. 2024. लाइफस्टाइल चेंज इज़ नीड ऑफ द ऑवर टू रिड्यूज कार्बन फुटप्रिंट, द हिंदू, 16 जून

चतुर्वेदी, सचिन. 2024. न्यू डेवेलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ लाइफ एंड वेलबीइंग : लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन्स परिवर्तन में, दूसरा अंक, ऐन हेबिटेट सेंटर पब्लिकेशन, अप्रैल 2024

चतुर्वेदी, सचिन. 2024. वैल्यू एंड एथिक्स इन ह्यूमन वेलबीइंग : टाइम टू गो बियोंड जीडीपी, जर्नल ऑफ गवर्नेंस, जनवरी 2023

चतुर्वेदी, सचिन. 2024. "इंडिया ऑफर्स ऐन ऑल्टरनेट डेवेलपमेंट पाथ फॉर ग्लोबल साउथ नेशंस" इंडियन एक्सप्रेस, 6 सितंबर 2024।

चतुर्वेदी, सचिन. 2024. डेवेलपमेंट कॉम्पैक्टः "अ ह्यूमन–सेंट्रिक अप्रोच विद् बैलेंस्ड अपॉर्च्यूनिटीज," ब्लिट्ज, 9–15 सितंबर 2024।

चतुर्वेदी, सचिन. 2024. "कोविड–19 पैंडेमिक एंड द इमर्जेंस ऑफ इंटीग्रेटिड इनोवेशन सिस्टम" इन रेइमेजिनिंग इनोवेशन्स सिस्टम्स इन द कोविड एंड पोस्ट–कोविड वर्ल्ड " लखविंदर सिंह और केजे जोसेफ (संपा)

चतुर्वेदी, सचिन. 2024. "मुचकुंद दुबेः वॉरियर ऑफ द ग्लोबल साउथ" इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59, अंक 30, 27 जुलाई 2024

चतुर्वेदी, सचिन, कुमार, अमित. 2024. 'रिस्पॉन्सिबल एआई ग्रोथ विद् सेफ्टीः एक्सप्लोरिंग ग्लोबल एंड नेशनल पॉलिसी डिस्कोर्स'', जर्नल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, खंड 61 (5), अक्टूबर 2024, पृ. 231–237

चतुर्वेदी, सचिन. 2024. स्पेशल इश्यू ऑन ट्रेड पॉलिसी, एफटीए, एंड वैल्यू चेन्स – ऐन ओवरव्यू इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59, अंक 46 नवंबर 16, पृ. 31–32

चतुर्वेदी, सचिन. 2024 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड पॉलिसी रिस्पॉन्सेस लीवरेजिंग न्यू अपॉर्च्यूनिटीज एंड एड्रेसिंग पर्सिस्टिंग चैलेंजिज इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59, अंक 46 नवंबर 16, पृ. 42–49

चतुर्वेदी, सचिन. 2024 (सह–लेखक)। क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑक्शंसः इंक्रीजिंग द इफैक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस। मॉन्ट्रियलः इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन पब्लिक पॉलिसी। आईआरपीपी इनसाइट नंबर 58.

चतुर्वेदी, सचिन. 2025. 'विकसित भारत एंड ग्लोबल साउथ'. ब्लिट्ज इंडिया बिजनेस. 18 जनवरी।

चतुर्वेदी, सचिन. 2025. ''हॉव इंडिया कैन डू बिजनेस विद ट्रंप्स अमेरिका'. इंडियन एक्सप्रेस. 23 जनवरी।

चतुर्वेदी, सचिन. 2025. ''बूस्ट फॉर ट्रेड इन टाइम्स ऑफ ट्रम्प'. ब्लिट्ज इंडिया बिजनेस. 3 फरवरी।

चतुर्वेदी, सचिन. 2025. ''ग्लोबल ट्रेड, ट्रंप एंड इंडियाज रोल' इंडियन एक्सप्रेस. 18 फरवरी।

दाश, पी. 2024. "ऐन इन्क्लूसिव जी–20 स्ट्रेटेजी टू स्केल 'डेट–फॉर–नेचर/क्लाइमेट स्वैप' फॉर इफेक्टिव क्लाइमेट एंड बायोडायवर्सिटी एक्शन इन डेवेलपिंग कंट्रीज"। टी–20 ब्राजील पॉलिसी ब्रीफ, 2024

डे, प्रबीर 2024 "ग्रीनिंग ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन इन साउथ एशियाः व्यूज फ्रॉम इनसाइड", ट्रेड इनसाइट,. खंड 20, अंक 1–2

डे, प्रबीर 2024 "चेंगिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियाज इकॉनोमिक डिप्लोमेसीः नेहरू टू मोदी", जर्नल ऑफ इंडियन एंड एशियन स्टडीज, खंड 5, अंक 2

डे, प्रबीर. 2024. "बैरियर्स टू गुड्स ट्रेड इन साउथ एशियाः चैलेंजिज एंड प्रोस्पेक्ट्स", आनंद कुमार (संपादक) अचीविंग रीजनल इकोनोमिक इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया, एमपी–आईडीएसए, नई दिल्ली

डे, प्रबीर और अन्य. 2024. "सिक्योरिंग रीजनल सोलार सप्लाई चेन्सः डिटरमिनेंट्स एंड प्रीपेयर्डनेस ऑफ द नॉर्थईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड आसियान", कार्य पत्र संख्या 537, ईआरआईए, जकार्ता

डे, प्रबीर और अन्य. 2024 (संपा.) इंडो–पैसिफिक एंड आसियानः न्यू बैलेंसिज एंड न्यू चैलेंजिज फॉर एशियन इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी, रूटलेज इंडिया, नई दिल्ली

डे, प्रबीर ."टूवर्ड्स बांग्लादेश–इंडिया–जापान (बीआईजे) ट्राइलेटरल ट्रेड पार्टनरशिप." आईडीई नीतिगत सारांश संख्या 226, आईडीई–जेईटीआरओ, जापान मार्च 2025.

डे, प्रबीर. "मातरबारी पोर्ट एंड ओपनिंग ऑफ न्यू मल्टी–मॉडल कनेक्टिविटी कोरिडोर्स" आईडीई नीतिगत सारांश संख्या 225, आईडीई–जेईटीआरओ, जापान मार्च 2025.

डे, प्रबीर. "रीजनल वैल्यू चेन्स एंड कनेक्टिविटी इन बिम्सटेक", नीतिगत सारांश एसएएनईएम, ढाका। फरवरी 2025.

डे, प्रबीर. 2025. "द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिम्सटेक समिट" द संडे गार्जियन, नई दिल्ली. 30 मार्च।

दे, प्रबीर. 2025. "बिम्सटेकः बंगोपोसगोरे एकटी स्थायि अंगशिदारतोवो", बांग्ला ट्रिब्यून, ढाका, बांग्ला में. 28 मार्च।

डे, प्रबीर. 2025. "टूवर्ड्स फ्री ट्रेड थ्रू एआईटीआईजीए", हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 3 जनवरी।

मोहंती, एस. के. 2024. "एक्सप्लोरिंग ट्रेड, जीवीसी, एंड टेक्नोलॉजी गुड्स इन इंडियाज़ एफटीए" इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59, अंक संख्या 46

9 सुखमय चक्रवर्ती पुस्तकालय एवं आंकड़ा सूचना केन्द्र

परिचय

इस डॉक्यूमेंटशन सेंटर में नवीनतम विशेष प्रकाशनों, रिपोर्टों, डेटाबेस, ई–पत्रिकाओं और लेखों का व्यापक संग्रह है, जो आरआईएस के संकाय सदस्यों और अतिथि विद्वानों हेतु अद्यतन जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यह संस्थान अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मजबूत आदान–प्रदान कार्यक्रम जारी रखे हुए है और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर नए प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री को शामिल करते हुए अपने संसाधन आधार को लगातार समृद्ध कर रहा है।

आरआईएस के एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, यूएन, यूएनसीटीएडी, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे

प्रमुख वैश्विक संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित हैं। यहां आदान–प्रदान कार्यक्रमों के जरिए कार्य पत्र, चर्चा पत्र, पुनर्मुद्रण और सामयिक पत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों स्वरूपों में प्राप्त किए जाते हैं या संस्थागत वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाते हैं। इस डॉक्यूमेंटशन सेंटर में वर्तमान में 23,547 से अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें सरकारी प्रकाशन और अन्य शोध संस्थानों के दस्तावेज़ शामिल हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों स्वरूपों में हैं। इसमें पत्रिकाओं के 1,850 सजिल्द खंड भी हैं। इस सेंटर के पास 429 से अधिक प्रिंट और ऑनलाइन पत्रिकाओं की सदस्यता है, जिनमें जेएसटीओआर, एल्सेवियर–साइंस डायरेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, टेलर एंड फ्रांसिस और विले जैसे प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं, और प्रतिष्ठित स्रोतों से लगभग 25 पत्रिकाएं निःशुल्क प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, संग्रह में 350 से अधिक सीडी–रोम और डेटाबेस शामिल हैं। डेलनेट के सदस्य के रूप में, सेंटर सक्रिय रूप से संसाधनों को साझा करने को बढ़ावा देता है। संकाय सदस्यों को एक नियमित करंट अवेयरनेस सर्विस प्रदान की जाती है।

सुगम संदर्भ के लिए यह समग्र संग्रह इंट्रानेट के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

इस संग्रह में शामिल हैं:पुस्तकें

- किताबें
- सांख्यिकीय वार्षिकी
- दस्तावेज–डब्ल्यूपी–ओपी–डीपी
- जर्नल/पत्र–पत्रिकाएं (प्रिंट+ऑनलाइन+सीडी–रॉम)
- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के समाचार पत्र
- पिछला संस्करण (बैक वॉल्यूम)
- सीडी–रॉम
- सीडी–रॉम में डेटाबेस

आरआईएस डेटाबैंक

व्यापार, टैरिफ एवं गैर–टैरिफ उपायों, भुगतान संतुलन, वित्तीय सांख्यिकी, विकास सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, बौद्धिक संपदा सेवाओं और कॉरपोरेट डेटा एवं सूचना पर आरआईएस का वैश्विक डेटाबेस। भारतीय आंकड़े 8–अंकीय स्तर पर व्यापार संबंधी टाइम सीरीज डेटाबेस, भारतीय कंपनियों एवं उनके वित्तीय प्रदर्शन के डेटाब. `स, सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस और सीमा शुल्क टैरिफ आंकड़ों को कवर करता है।

आरआईएस डेटाबेस

आरआईएस ने देवकूपइंडिया नामक एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया है, जिसका उद्देश्य 1947 से 2021 तक भारत की ओर से भागीदार देशों को प्रदान की गई विकास संबंध ी सहायता का ब्यौरा को दर्ज करना है। इस डेटाबेस में डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की पांच कार्यपद्धतियां अर्थात्– क्षमता निर्माण, अनुदान, रियायती वित्त, व्यापार और बाजार तक पहुंच, और तकनीकी हस्तांतरण शामिल हैं। प्रमुख वर्गीकरण को उप–कार्यपद्धतियों, क्षेत्रों और गतिविधियों में विभाजित किया गया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अतिरिक्त कई अन्य मंत्रालय शामिल किए गए हैं, जो अनेक कार्यपद्धतियों और उप–कार्यपद्धतियों के माध्यम से विकास संबंधी सहायता देने में सम्मिलित हैं। डेटाबेस में भारत के अनुदान शामिल हैं, जिनमें द्विपक्षीय विकास के लिए सहायता के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दिया गया योगदान भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025–2026 में विकास सहायता के लिए आवंटन 2024–25 के संशोधित अनुमानों द्वारा निर्धारित है, जैसा कि 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

एक अन्य डेटाबेस में जीडीपी, व्यापार, निवेश, शुल्क और अन्य संबद्ध कारकों जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर डेटा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। व्यापार और शुल्क डेटाबेस के संदर्भ में, आरआईएस डेटा को अधिकतम पृथक स्तर पर प्रभावी ढंग से पुनर्गठित करता है। उदाहरण के लिए, भारत के लिए द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों का आवंटन 8–अंकों वाले हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) उत्पाद वर्गीकरण पर आधारित है, जबकि शेष विश्व के लिए यह 6–अंकों वाले एचएस वर्गीकरण पर आधारित है। डेटा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण में मौजूद सभी शब्दावलियों में दर्ज किया गया है। पृथक्करण का स्तर और समय श्रृंखलाओं का स्तर अलग–अलग डेटा स्रोतों के साथ भिन्न–भिन्न होता है। इस डेटाबेस को नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है।

आरआईएस का डेटा सर्वर

आरआईएस ने त्वरित संदर्भ के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टाइम सीरीज आंकड़ा हासिल किया है। इसने टैरिफ आंकड़ा कोष, भारतीय कंपनियों के डेटाबेस, व्यापार आंकड़ों की दिशा (डॉट्स), विश्व विकास संकेतकों (डब्ल्यूडीआई), इत्यादि के साथ इस पर महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ा (एचएस एंड एसआईटीसी) अपलोड किए हैं। सर्वर पर आंकड़ा कोष

आरआईएस मुख्य वेबसाइट
www.ris.org.in

आरआईएस में मुख्य केंद्र

आसियान भारत केंद्र
http://aic.ris.org.in

दक्षिण– ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
https://dakshin.org.in/

समुद्री अर्थव्यवस्था संयोजन केन्द्र
https://ris.org.in/cmec/

विशेष पहल

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम
https://ris.org.in/science-technology-and-innovation-policy-stip-forum-and-monthly-lecture-series

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम)
http://fitm.ris.org.in

भारतीय विकास सहयोग के लिए फोरम
http://fidc.ris.org.in

एफआईएसडी
http://fisd.in

दिल्ली प्रोसेस
http://ris.org.in/delhi-process

वैश्विक/क्षेत्रीय नेटवर्क

दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस)
http://saceps.org.in

बिम्सटेक नीतिगत विचारकों का नेटवर्क (बीएनपीटीटी)
https://ris.org.in/bimstec

थिंक 20 (टी20)
https://ris.org.in/think-20

ब्रिक्स सिविल फोरम
http://bricscivil.ris.org.in/index.html

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट)
https://southernthinktanks.org/

इब्सा अकादमिक मंच
https://ris.org.in/bimstec

को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। यह संकाय के सदस्यों को तत्काल अद्यतन डेटा उपलब्ध कराता है जो उनके साक्ष्य–आधारित शोध अध्ययनों में गहराई से मदद करता है। यही नहीं, ऐसे में व्यक्तिगत आरआईएस संकाय सदस्यों के लिए महंगी बहु–वैश्विक डेटा प्रणालियों को खरीदने की जरूरत नहीं रह जाती है।

आरआईएस की वेबसाइट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर

(www.ris.org.in)

आरआईएस की वेबसाइट को प्रतिदिन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली एवं यूजर (उपयोगकर्ता) अनुकूल सामग्री के साथ नवीनीकरण किया जाता है और यह नवीनतम सुविधाओं एवं कार्यों से सुसज्जित या लैस है। इसे आरआईएस की

आंतरिक टीम द्वारा वास्तविक समय पर अपडेट किया जाता है, ताकि उसके आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वैश्विक सार्वजनिक डोमेन में गहन अनुसंधान अध्ययनों और संबंधित घटनाक्रमों को उपलब्ध कराया जा सके। यह स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, निवेश, विकास सहयोग, वैश्विक आर्थिक मुद्दों, क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिणीय सहयोग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित आरआईएस के कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों के बारे में व्यापक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। यह अनुसंधान रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, सूचना–पत्र (न्यूजलेटर) और मीडिया लेखों के रूप में आरआईएस द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकाशनों की विस्तृत श्रृंखला की मुफ्त डाउनलोड सुविधा प्रदान करती है। इसमें आरआईएस द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का विवरण भी है। चालू वित्त वर्ष (2023–24) के दौरान तीन नए उप–कार्य क्षेत्रों (सब–डोमेन) को आंतरिक तौर पर विकसित किया गया है और फिर उन्हें आरआईएस की वेबसाइट से लिंक कर दिया गया है, ताकि उनकी स्पष्ट और व्यापक पहुंच संभव हो सके। अब आरआईएस की मुख्य वेबसाइट के अंतर्गत ग्यारह उप–कार्य क्षेत्र (सब–डोमेन) हैं। इनमें ये शामिल हैं:

परिणामों में से एक का दर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है जो इसकी निरंतर बढ़ती दृश्यता को रेखांकित करता है। आरआईएस नियमित रूप से अपने त्रैमासिक ई–न्यूजलेटर और मासिक ई–पत्रिका को भी प्रकाशित करता है जिन्हें प्रमुख नीति–निर्माताओं एवं आकृतिकारों, थिंक टैंकों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्रमुख शिक्षाविदों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रख्यात हस्तियों के बीच दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है, ताकि उन्हें विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दों पर आरआईएस द्वारा किए जा रहे विश्वसनीय शोध कार्यों की विस्तृत विविधता से अवगत कराया जा सके।

सोशल मीडिया आउटरीच

बीते वर्षों में इस संस्थान ने ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी पहुंच को व्यापक बनाया है। आरआईएस के यूट्यूब चैनल को लगातार अद्यतन रखा जाता है। ट्विटर पर लगभग 14 हजार हैं। कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग सुगम पहुंच के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाती है। यूट्यूब चैनल पर दर्शकों की संख्या और ग्राहक आधार में लगातार वृद्धि हुई है। आरआईएस यूट्यूब चैनल पर लगभग 1.69 हजार सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या 5.3 हजार से ज्यादा है और पब्लिक ओपिनियन पोल्स के आधार पर इसके पेजों को 5 में से 4.6 रेटिंग दी गई है। आरआईएस के प्रत्येक प्रमुख आयोजन को वास्तविक समय के आधार पर त्वरित सार्वजनिक पहुंच के लिए इन दोनों प्लेटफार्मों पर तत्काल फ्लैश किया जाता है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन आदि पर दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहवर्धक रही है।

आंकड़ा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक

पिछले सातः वर्षों में आरआईएस के हिट्स

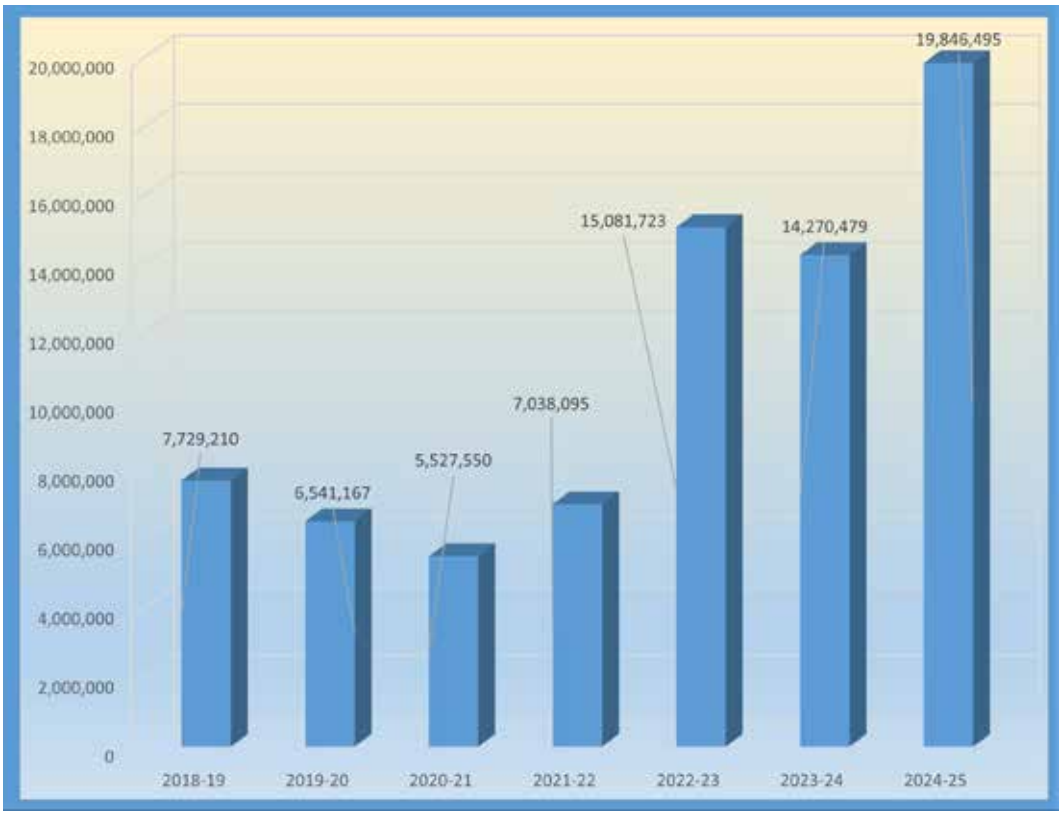

पिछले वर्षों की तरह, हम तै के सम्मानित संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनकी अटूट प्रतिबद्धता ने परिवर्तनकारी अनुसंधान को गति दी है और संस्थान के वैश्विक प्रभाव को व्यापक बनाया है। यह आरआईएस वार्षिक रिपोर्ट उनकी विशेषज्ञता का प्रमाण है, जो पिछले वर्ष संस्थान की प्रभावशाली यात्रा और उपलब्धियों पर गहन परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। हम आगे भी अपना आभार व्यक्त करते हैं

हम आरआईएस के संकाय सदस्यों के अत्यधिक आभारी हैं, जिनके अटूट समर्पण ने नवोन्मेषी अनुसंधान को बढ़ावा दिया है, जिसकी बदौलत संस्थान की वैश्विक पहुंच में वृद्धि हुई है। हमारे सम्मानित संकाय सदस्यों द्वारा तैयार की गई आरआईएस की वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट संस्थान की प्रभावशाली यात्रा का विस्तृत अन्वेषण प्रदान करती है।

अभिस्वीकृति

पिछले वर्षों की तरह, हम आरआईएस के सम्मानित संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनकी अटूट प्रतिबद्धता ने परिवर्तनकारी अनुसंधान को गति दी है और संस्थान के वैश्विक प्रभाव को व्यापक बनाया है। यह आरआईएस वार्षिक रिपोर्ट उनकी विशेषज्ञता का प्रमाण है, जो पिछले वर्ष संस्थान की प्रभावशाली यात्रा और उपलब्धियों का गहन परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। हम प्रोफेसर एस. के. मोहंती के नेतृत्व में डॉ. पंखुड़ी गौर; डॉ. प्रियदर्शी दाश के नेतृत्व में श्री वासु अग्रवाल; डॉ. सब्यसाची साहा के नेतृत्व में डॉ. प्रत्युष शर्मा और श्री सैयद अरसलान अली; डॉ. पंकज वशिष्ठ के नेतृत्व में डॉ. शम्पा कुंडू; डॉ. एस. के. वार्ष्णेय के नेतृत्व में डॉ. स्नेहा सिन्हा; और प्रोफेसर टी. सी. जेम्स के नेतृत्व में डॉ. सारिन एन. एस. को आरआईएस वार्षिक रिपोर्ट (2024–25) के इस संस्करण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए और आरआईएस की प्रकाशन टीम, जिसमें श्री तीश मल्होत्रा, श्री सचिन सिंघल और श्री संजीव कर्ण शामिल हैं, को इस वार्षिक रिपोर्ट के निर्माण की व्यवस्था करने के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

मानव संसाधन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तत तथा विकास सहयोग

(7 सितंबर 2025 तक)

प्रो. सचिन कुमार शर्मा

महानिदेशक

विशेषज्ञता :

(8 सितंबर 2025 से)

संकाय

डॉ एस के मोहंती

विशिष्ट फैलो

विशेषज्ञता : वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

डॉ. प्रबीर डे

प्रोफेसर, (सीएमईसी)

विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

डॉ सब्यासाची साहा

सह प्रोफेसर

विशेषज्ञता : प्रोद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ प्रियदर्शी दाश

सह प्रोफेसर

विशेषज्ञता : अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

डॉ पंकज वशिष्ठ

सह प्रोफेसर/समन्वयक, एआईसी

विशेषज्ञता: व्यापार, प्रौद्योगिकी और श्रम बाजार

डॉ. सुशील कुमार

सहायक प्रोफेसर

विशेषज्ञता: अतंर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

डॉ. अमित कुमार

सहायक प्रोफेसर

विशेषज्ञता: नवप्रवर्तन, दूरदर्शिता एवं नियंत्रण

डॉ. पंखुड़ी गौर

सहायक प्रोफेसर

विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नीली अर्थव्यवस्था, एफटीए और मेगा क्षेत्रीय

विशिष्ट फेलो

श्री राजीव खेर
विशिष्ठ फेलो
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य

डॉ जे आर भट्ट
विशिष्ठ फेलो
(जनवरी 2023 से मानद फैलो)

प्रोफेसर पम्मी दुआ
विशिष्ठ फेलो
(1 जनवरी 2025 से)

श्री अनिल जोहरी
विशिष्ठ फेलो
(5 मार्च 2025 से)

विजिटिंग फेलो

प्रो. टी सी जेम्स
विजिटिंग फेलो
विशेषज्ञताः बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर)

डॉ. के रवि श्रीनिवास
विजिटिंग फेलो
विशेषज्ञताः बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

डॉ. पी के आनन्द
विजिटिंग फेलो
विशेषज्ञताः आर्थिक विकास और विकास

कमोडोर सुजीत समादार
विजिटिंग फैलो
(1 जून 2024 से)

डॉ बीना पाण्डेय
विजिटिंग फेलो
विशेषज्ञता : सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले
(29 दिसंबर 2024 से)

श्री अमोल बक्सी
विजिटिंग फेलो
विशेषज्ञताः वित्त और दिवालियापन कानून

श्री जी के अरोड़ा
फेलो
(31 अगस्त 2024 तक)

फेलो/सलाहकार

डॉ नम्रता पाठक
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता: पारंपरिक ज्ञान

डॉ अंशुमन गुप्ता
सलाहकार
विशेषज्ञता: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

डॉ चैतन्य गिरी
सलाहकार
विशेषज्ञता: अंतरिक्ष डोमेन रणनीतियाँ, ग्रह विज्ञान
(30 नवम्बर 2024 तक)

डॉ स्नेहा सिन्हा
सलाहकार
विशेषज्ञता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन

श्री सायंतन घोषाल
सलाहकार
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक सुरक्षा कल्याण प्रणाली

डॉ अनुज द्विवेदी
विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञ
विशेषज्ञता: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी और मूल्यांकन

डॉ पुष्पक कुमार राय
सलाहकार

डॉ सरीन एन एस
सलाहकार
विशेषज्ञता: परंपरागत चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रणाली और नीति अनुसंधान

प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती
सलाहकार
(23 फरवरी 2023 से)
विशेषज्ञता: सूक्ष्म–अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सहयोग और मूल्यांकन

डॉ पी. श्रीनिवास राव
फैलो
विशेषज्ञता: कृषि, सतत विकास लक्ष्य और जी20

डॉ आईवी रॉय सरकार
फैलो

डॉ रोहित सैनी
फैलो
(3 सितंबर 2024 तक)

श्री संकेत चवान
सलाहकार

डा अनुपमा विजयकुमार
सलाहकार

श्री सैयद मोहम्मद अली
सलाहकार
(27 मार्च 2025 तक)

श्री अली हैदर रिजवी
सलाहकार
(4 मार्च 2025 से)

आसियन–भारत केंद्र

डॉ पंकज वशिष्ठ
सह प्रोफेसर/समन्वयक, एआईसी
विशेषज्ञता: व्यापार, प्रौद्योगिकी और श्रम बाजार

डॉ शम्पा कुन्डू
सहायक
आसियान की भू–राजनीति, म्यांमार, क्षेत्रीय सहयोग

श्री वासू अग्रवाल
अनुसंधान सहायक
(9 दिसंबर 2024 से)

समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी)

डॉ शिशिर श्रोत्रिय
समन्वयक, सीएमईसी
(2 मई 2024 से)

डॉ. प्रबीर डे
प्रोफेसर, (सीएमईसी)
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

सुश्री अनुष्का त्रिपाठी
अनुसंधान सहायक

सुश्री शगुन वर्मा
अनुसंधान सहायक
(29 जुलाई 2024 से)

सुश्री शगुन वर्मा
अनुसंधान सहायक
(22 नवम्बर 2024 से)

दक्षिण

डॉ गुलशन सचदेवा
समन्वयक दक्षिण
(26 नवंबर 2024 से)

डॉ मोनिका कोचर
सलाहकार (हेल्थ)
(1 फरवरी 2024 से)

श्री वेंकटेश कृष्णमूर्ति
सलाहकार (डिजिटल)
(27 जून 2024 से)

श्री अमित अरोड़ा
मैनेजर

सुश्री चांदनी शर्मा
अनुसंधान सहायक
(31 अगस्त 2024 तक)

सुश्री तानया सिंह
अनुसंधान सहायक
(22 अक्टूर 2024 से)

श्री अतुल कौशिक
जीडीसी फैलो

डॉ अरायपल्ली शिवसेनरेड्डी
सलाहकार (कृषि)

डा प्रत्युष शर्मा
सलाहकार

श्री ओमेगेरे जॉन पैट्रिक
अफ्रीका के लिए संसाधन व्यक्ति

श्री आकाश सिंह
अनुसंधान सहायक
(1 जुलाई 2024 से)

अनुसंधान सहायक

श्री सैयद अर्सलान अली

श्री अर्पित बर्मन

श्री सुक्रित जोशी
(2 सितंबर 2024 तक)

सुश्री राणा अमानत सिंह
(19 अक्टूबर 2024 तक)

श्री कनिष्क रोहिल्ला
(24 अप्रैल 2024 से)

श्री अमल के साजी
(27 मई 2024 से)

सुश्री ओम स्तुति
(28 मई 2024 से)

श्री आयुष तिवारी
(3 जून 2024 से)

सुश्री देबाजंना
(29 दिसंबर 2024 तक)

श्री कार्तिक किशोर
(4 नवंबर 2024 तक)

सुश्री वैशाली चौधरी

श्री विमलेन्दु चौहान

श्री अविनाश
(22 अक्टूबर 2024 से)

सुश्री वंशिका गोयल
(17 जनवरी 2025 से)

सुश्री रिद्धि लखियानी
(3 फरवरी 2025 से)

श्री टिनू कुरियन
(3 फरवरी 2025 से)

सुश्री श्रीलक्ष्मी पी

(3 फरवरी 2025 से)

सुश्री अनन्या रस्तोगी

(1 अगस्त 2024 से)

श्री शरद कौशल

(4 नवंबर 2024 से)

तनुश्री शर्मा

(2 दिसंबर 2024 से)

श्री लक्ष्य शंकर गौड़

(29 जुलाई 2024 से)

सहायक वरिष्ठ अध्येता

प्रोफेसर अनिल सुकलाल
उप महानिदेशक, एशिया और मध्य पूर्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग, दक्षिण अफ्रीका

प्रोफेसर हरिबाबू ईजनवरजला
पूर्व कुलपति प्रभारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय

डॉ. बेनू श्नाइडर
पूर्व में संयुक्त राष्ट्र एवं अंकटाड के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक में सलाहकार

प्रोफेसर मुकुल जी. अशर
प्रोफेसरियल फेलो, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. बालाकृष्ण पिसुपति
चेयरपर्सन, फ्लेज और पूर्व अध्यक्ष, एनबीए, चेन्नई

डॉ. सतीश चंद्र मिश्रा
कार्यकारी निदेशक,
अर्थशास्त्र संस्थान, इंडोनेशिया

डॉ. सुमा अत्रे
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और रणनीति, ब्रुनेल बिजनेस स्कूल, यूके

राजदूत अमर सिन्हा
पूर्व सचिव (ईआर) विदेश मंत्रालय

प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल
आरबीआई के पूर्व चेयर प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम

प्रोफेसर श्रीविद्या राघवन
कानून के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ लॉ, नॉर्मन, अमेरिका

डॉ. निकोलस जे.ए. बुचौड
अध्यक्ष, ग्रैंड पेरिस महानगरीय विकास गठबंधन

डॉ. टी. पी. राजेंद्रन
पूर्व सहायक महानिदेशक, आईसीएआर तथा विजिटिंग फेलो, आरआईएस

प्रोफेसर केविन पी. गालाघेर
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, बोस्टन यूनिवर्सिटी; सीनियर एसोसिएट, जीडीएई, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी

डॉ गणेशन विग्नराज
एडजंक्ट सीनियर फेलो
सीनियर रिसर्च एसोसिएट, ओवरसीज इंस्टीट्यूट (ODI), लंदन; अनिवासी सीनियर फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (ISAS)

स्टाफ के अन्य सदस्य

श्री अनिल कांत शर्मा
निदेशक, (वित्त एवं प्रशासन)

श्री अरिंजित बैनर्जी
सलाहकार (प्रशासनिक)
(14 अगस्त 2024 से)

महानिदेशक कार्यालय

श्रीमती रितु परनामी
निजी सचिव

सुश्री गोहर नाज
सचिवीय सहायक

श्री बलजीत
सपेशल सहायक

प्रकाशन विभाग

श्री तीश कुमार मल्होत्रा
प्रकाशन अधिकारी

श्री सचिन सिंघल
प्रकाशन सहायक (वेब और डिजाइन)

श्री संजीव कर्ण
संपादकीय सहायक

श्री महेश सी अरोड़ा
सलाहकार, (वित्त एवं प्रशासन)

आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र

श्रीमती ज्योति
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

श्रीमती सुशीला
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक

श्रीमती सुषमा भट्ट
उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन

श्री सत्यपाल सिंह रावत
जूनियर सहायक

सुश्री निशा सैनी
वेबसाईट डेवलपर

वित्त एवं प्रशासन

श्री अनिल कुमार
अनुभाग अधिकारी

श्री सुरजीत
लेखाकार (*डेपूटेशन पर*)

श्री अमरेंद्र पटनायक
सलाहकार (लेखा)
(9 अप्रैल 2024 से)

श्री योगेश
सलाहकार (लेखा)

श्रीमती शालिनी शर्मा
स्वागती

श्री भास्कर तिवारी
सहायक लेखाकार

श्री पियूष माथुर
लेखाकार लिपिक

अनुसंधान सहयोग

सुश्री किरन वाघ
सचिवीय सहायक

श्री संजीव शर्मा
निजी सचिव (*डेपूटेशन पर*)

श्री सुरेन्द्र कुमार
निजी सहायक

श्रीमती बिन्दु गंभीर
आशुलिपिक

श्री बैदनाथ पाण्डेय
कार्यालय सहायक

सहायक स्टाफ

श्री जे बी ठाकुरी, स्टाफ कार चालक

श्री राज कुमार (एमटीएस)

श्री सत्यवीर सिंह, स्टाफ कार चालक

श्री प्रदीप (एमटीएस)

श्री राजू (एमटीएस)

श्री मनीष कुमार (एमटीएस)

श्री राज कुमार (एमटीएस)

श्री सुधीर राणा (एमटीएस)

श्री बिरजू (एमटीएस)

श्री प्रदीप नेगी (एमटीएस)

श्री अविनाश कपूर (एमटीएस)

श्री रमेश सिंह चौधरी (एमटीएस)

वित्तीय विवरण

जीएसए एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स

16, डीडीए फलैट्स, ग्राउंड फलोर, पंचशील शिवालिक मोड़,
मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली–110017 टेलीफोन : 41811888, 7862099205, ई–मेलः admin@gsa.net.in

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली की आमसभा के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

मत

हमने 'विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली' (इकाई) के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च, 2025 तक का तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारे मतानुसार और हमारी जानकारी में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में 31 मार्च, 2025 को इकाई की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय तथा प्राप्ति एवं भुगतान के बारे में सही और निष्पक्ष छवि प्रदान करते हैं।

मत का आधार

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों (एसए) के अनुरूप लेखा परीक्षण किया है। इन एसए मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के खण्ड 'वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में वर्णित हैं। हम अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के लिए उपयुक्त नैतिक आवश्यकताओं के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार इस इकाई से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और अपने अन्य आचार उत्तरदायित्वों का निर्वहन आचार संहिता के अनुसार किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन और शासी प्रभारियों के उत्तरदायित्व

भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, इकाई की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन की सही व निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का होता है। इस उत्तरदायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण का स्वरूप निर्धारित करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो सही एवं निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त होते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान प्रबंधन सुनाम प्रतिष्ठान बने रहने में इकाई की क्षमता का आकलन करने, सुनाम प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण और लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तदायी है, जब तक कि प्रबंधन या तो इकाई को समाप्त करने अथवा संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा ऐसा करने के अलावा कोई ठोस विकल्प न हो।

इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए शासी प्रभारी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन होने के बावजूद यह गारंटी नहीं देता कि 'एसए' के अनुसार किए गए लेखा परीक्षण तथ्य संबंधी गलतबयानी होने पर सदैव उसका पता लगा ही लेंगे। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उसे ठोस तभी माना जाता है, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों की व्यक्तिगत या समग्र रूप से इनसे प्रभावित होने की संभावना हो।

'एसए' के अनुसार की जाने वाली लेखा परीक्षा के तहत हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान व्यवसायिक तौर पर संशय से युक्त दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी करते हैं:

- हम धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण की तथ्य संबंधी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, इन जोखिमों को कम करने में सक्षम लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं को निर्मित एवं निष्पादित करते हैं, और ऐसा लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे मत को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं बिल्कुल उपयुक्त होता है। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी का पता नहीं लगा पाने का जोखिम दरअसल त्रुटि से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी से जुड़े जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि ध ोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।
- हम परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षण से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं।
- हम प्रयुक्त की जा चुकी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का आकलन करते हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार की उपयुक्तता और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर इस बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ऐसी कोई ठोस अनिश्चितता है, जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में अपना संचालन जारी रखने संबंधी इस इकाई की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने मत में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां इकाई के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में संचालन जारी न रखने का कारण बन सकती हैं।
- हम प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सारांश, का आकलन करते हैं, तथा ज्ञात करते हैं कि क्या अंतर्निहित लेन–देन के व्यवहार और स्थितियों का विवरण उचित स्वरूप में वित्तीय विवरणों में दिया गया है या नहीं।
- हम अन्य मामलों के अलावा शासन व्यवस्था के प्रभारी लोगों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र एवं लेखा परीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में चिन्हित की गई किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण खामियों के बारे में जानकारी देते हैं।

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/N500339

ह./–
तनुज चुघ
साझेदार
एम संख्या : 529619

स्थान : नई दिल्ली :
दिनांक : 29.09.2025

यूडीआईएनः 25529619BMIVLG7982

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी)

31 मार्च, 2024 तक का तुलन पत्र

धनराशि रु.में

विवरण	अनुसूची #	31मार्च, 2024 को	31मार्च, 2023 को
देनदारियां			
अनुसंधान एवं विकास कोष	1	182,958,394.08	158,979,552.22
अचल परिसंपत्ति कोष (गैर एफसीआरए)	2	136,308,128.00	116,827,535.00
अचल परिसंपत्ति कोष (एफसीआरए)		37,767.00	46,037.00
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित रा"ि (गैर एफसीआरए)	3	52,691,435.14	8,218,008.14
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित रा"ि (एफसीआरए)		103,885,408.39	80,919,187.15
विदे"ा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित सहायता अनुदान	4a	-	-
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान(गैर एफसीआरए)	4	38,849,637.12	53,975,073.60
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (एफसीआरए)		828,273.00	10,087,720.00
कुल		515,559,042.73	429,053,113.11
परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (गैर एफसीआरए)	5	136,308,128.00	116,827,535.00
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (एफसीआरए)		439,063.00	447,333.00
निवे"ा (गैर एफसीआरए)	6	48,637,819.00	34,156,930.00
निवे"ा (एफसीआरए)		207,485,254.95	189,849,406.95
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य रा"ि (गैर एफसीआरए)	3	53,657,088.47	11,478,167.20
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य रा"ि (एफसीआरए)		27,791.72	2,618,735.62
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (गैर एफसीआरए)	7	32,757,529.66	53,666,026.67
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (एफसीआरए)		36,246,367.93	20,008,978.67
कुल		515,559,042.73	429,053,113.11

खातों पर महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण नीतियां एवं टिप्पणियां 16

अनुसूची 1 से 16 खातों का अत्याव"यक भाग है
हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एंडएसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/N500339

कृते विकास"ाील दे"ाों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(सीए सुनील अग्रवाल)
साझेदार
एम संख्या : 083899

अरिजीत बनर्जी
कार्यवाहक निदेशक (वित्त एवं प्र"ाासन)

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदे"ाक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :26.9.2024

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था)
31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता राशि में

राशि रु. में

विवरण	अनुसूची #	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
आय			
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान	4(a)	14,15,11,574	14,66,55,672
कार्यक्रम से संबंधित व्यय पूरे करने के लिए हस्तांतरित प्रायोजित परियोजना अनुदान (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	3	11,11,91,003	14,99,30,593
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर हस्तांतरित अधिशेष राशि (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	3	3,47,940	31,39,579
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय (गैर–एफसीआरए)			3,54,827
अर्जित ब्याजः			
सावधि जमा पर (एफसीआरए)		92,26,689	66,81,945
सावधि जमा पर (गैर–एफसीआरए)		70,950	21,21,416
बचत खाता/ऑटो स्वीप खाता(एफसीआरए) पर		34,950	5,31,005
बचत खाता/ऑटो स्वीप खाता (गैर एफसीआरए) पर		6,41,396	20,94,882
कर्मचारियों को दिए ऋण पर (गैर–एफसीआरए)		12,000	27,000
आयकर रिफंड पर (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		1,64,469	8,450
अन्य विविध आय (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		3,64,618	
प्रायोजित परियोजनाओं से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उपरिव्ययों के लिए वसूली(गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		63,82,857	99,86,318
देय बट्टे खाते में डाला			1,18,987
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कोष से हस्तांतरित राशि – बेची गई/बट्टे खाते में डाल दी गई संपत्तियों का डब्ल्यू.डी.वी. (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	2		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कोष से हस्तांतरित राशि – भारत सरकार/प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त सहायता अनुदान से अधिगृहीत परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	2	1,71,79,275	1,60,59,892
कुल (ए)		28,71,27,722	33,77,10,566
व्यय			
कार्यक्रम व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	8	11,11,91,003	14,99,30,593
स्थापना व्यय (गैर–एफसीआरए)	9	10,03,64,986	10,60,21,518
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (गैर–एफसीआरए)	10	4,64,32,651	4,08,03,011
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (एफसीआरए)	11	5,648	5,078
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	5	1,71,79,275	1,60,59,892
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर अंतरित की गई घाटा राशि (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)			
	3	48,86,195	9,11,632
कुल (बी)		28,00,59,758	31,37,31,724
अनुसंधान और विकास कोष में हस्तांतरित अधिशेष/ घाटा (ए–बी)		70,67,964	2,39,78,842

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16
अनुसूची 1 से 16 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं
आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/N500339

ह./–	ह./–	ह./–
सीए तनुज चुघ	अनिल कांत शर्मा	प्रो. सचिन चतुर्वेदी
साझेदार	निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)	महानिदेशक
एम सं. :529619		
स्थानः नई दिल्ली		
दिनांकः 29/09/2025		

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(1860 के सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी)

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रसीद और भुगतान

धनराशि रुपये में

	प्राप्तियां	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
ए	प्रारंभिक जमा :				
	हाथ में नकदी (गैर–एफसीआरए)	19,301		11,981	
	हाथ में नकदी (एफसीआरए)			4,608	
	बैंक में जमा राशि :				
ii)	बचत खाते में– आंध्रा बैंक				
	बचत खाता/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	39,140		39,140	
	बचत खाता/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	2,56,27,011		4,55,14,306	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	4,12,393		3,97,661	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर –एफसीआरए)	9,37,50,705		8,98,49,407	
	बचत खाते में– भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	4,86,37,819		3,41,56,930	
	बचत खाते में– भारतीय स्टेट बैंक (गैर–एफसीआरए)				
	सावधि जमा में . भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	2,70,34,864		1,27,19,253	
iii)	डाक टिकट– फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)	2,18,150			
		11,37,34,550		10,00,00,000	
	कुल ए	92,539		3,74,337	
बी	प्राप्त अनुदान				
			30,95,66,472		28,30,67,622
ii)	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से				
iii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से (गैर–एफसीआरए)	17,99,90,275		15,80,21,518	
	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से(एफसीआरए)	7,56,72,332		11,83,98,787	
	कुल बी				
		96,98,771		9,37,21,122	
सी	अर्जित ब्याज		26,53,61,378		37,01,41,427
i)	ऋण, अग्रिम आदि पर ब्याज, (गैर–एफसीआरए)				
	बचत बैंक खाता/ऑटो स्वीप पर ब्याज(एफसीआरए)	12,000		26,000	
ii)		30,090		5,04,627	
iii)	सावधि जमा खातों पर ब्याज(गैर–एफसीआरए)	9,49,305		13,61,793	
iv)	सावधि जमा खातों पर ब्याज(एफसीआरए)	65,05,255		50,64,251	
v)	बचत बैंक खाता/ऑटो स्वीप पर ब्याज(गैर–एफसीआरए)	80,804		20,94,882	
	आय कर रिफंड पर ब्याज				
vi)		1,64,469		8,450	
	कुल अग्रेनीत				
			77,41,923		90,60,003
			58,26,69,773		66,22,69,052

	भुगतान	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
ए	व्यय				
i)	स्थापना व्यय – अनुसूची – 12 (गैर – एफसीआरए)	10,72,07,845		10,81,57,740	
ii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय – अनुसूची – 13 (गैर–एफसीआरए)	4,22,57,944		4,44,91,438	
iii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय – अनुसूची – 14 (एफसीआरए)	5,648		5,078	
iv)	यय – प्रायोजित परियोजनाएं – अनुसूची – 15 (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	11,03,29,867		15,55,79,697	
	कुल ए		25,98,01,304		30,82,33,953
बी	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान				
i)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (गैर–एफसीआरए)	69,45,877		3,55,73,661	
ii)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (एफसीआरए)				
	कुल बी		69,45,877		3,55,73,661
सी	अग्रिम और जमा				
i)	अग्रिम (गैर–एफसीआरए)	4,94,941		9,05,340	
ii)	अग्रिम (एफसीआरए)			3,39,852	
iii)	एफटीसी0ऑन स्वीप ट्रांसफर (गैर–एफसीआरए)	1,02,615		1,03,429	
.) IV	स्वीप ट्रांसफर पर टीडीएस (एफसीआरए)	546		1,331	
v)	गतावधि या पुराने चेक				
	कुल सी		5,98,102		13,49,952
डी	अन्य				
i)	लौटाए गए अनुदान	3,75,69,026		78,66,611	
ii)	एलआईसी से प्राप्त राशि और कर्मचारियों को किया गया भुगतान	23,83,566		34,97,629	
iii)	आरआईएस भविष्य निधि में भुगतान की गई राशि				
iv)	मूर्त आस्तियों और विविध मदों का निपटान (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया)	1,31,453		1,38,425	
	कुल डी		4,00,84,045		1,15,02,665
	कुल अग्रेनीत		30,74,29,328		35,66,60,231

	प्राप्तियां	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष			भुगतान	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
	कुल अग्रानीत		58,26,69,773		66,22,69,052		कुल अग्रानीत		30,74,29,328		35,66,60,231
डी	अन्य आय					ई					
i)	रॉयल्टी	4,61,753		67,799		i)	अंतिम शेष (क्लोजिंग बैलेंस	17,685		19,301	
ii)	विविध आय						हाथ में नकदी (गैर–एफसीआरए)				
	कुल डी		4,61,753		67,799	ii)	हाथ में नकदी (एफसीआरए))			39,140	
ई	अग्रिम और जमा						बैंक में जमा राशि				
i)	ऋण/अग्रिम की वसूली (गैर –एफसीआरए)	4,31,501					बचत खाते में– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (गैर–एफसीआरए)	43,87,268		2,56,27,011	
ii)	कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली (गैर–एफसीआरए)			35,000			बचत खाते/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	8,928		2,18,150	
iii)	गतावधि या पुराने चेक (गैर–एफसीआरए एवं–एफसीआरए))						बचत खाते में– भारतीय स्टेट बैंक (गैर–एफसीआरए)	66,72,883		4,12,393	
iv)	एलआईसी से प्राप्त राशि और कर्मचारियों को देय	23,89,561		38,01,938			बचत खाता/ऑटो स्वीप – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	10,08,68,659		9,37,50,705	
v)	अग्रिम में प्राप्त राशि (गैर–एफसीआरए)						सावधि जमा– बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	7,57,12,383		4,86,37,819	
vi)	ऋण/अग्रिम की वसूली (एफसीआरए)	12,35,001		3,389			सावधि जमा– बैंक ऑफ इंडिया/भारतीय स्टेट बैंक (गैर –एफसीआरए)	8,38,65,824		11,37,34,550	
vii)	आरआईएस पीएफ की ओर से प्राप्त राशि						सावधि जमा– भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	1,09,48,003		2,70,34,864	
	कुल ई		40,56,063		38,40,327						
F	Others					iii)	बचत खाते में– भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	1,21,056		92,539	
	मूर्त आस्तियों का निपटान										
	मूर्त आस्तियों और विविध मदों का निपटान (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को लौटाने योग्य)	16,468		49,525			डाक टिकट– फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)		28,26,02,690		30,95,66,472
ii)	आय कर रिफंड	28,27,961									
	कुल एफ		28,44,429		49,525		कुल ई				
	कुल		59,00,32,018		66,62,26,703		कुल		59,00,32,018		66,62,26,703

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण नीतियां एवं खातों पर टिप्पणियां अनुसूची 16

अनुसूची 1 से 16 खातों का अत्यावश्यक भाग हैं
समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है

कृते जीएसए एंडएसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/ N500339

(सीए तनुज चुघ)
साझेदार
एम संख्या :529619

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

अनिल कांत शर्मा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

प्रो. सचिन कुमार शर्मा
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

आरआईएस को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में विशेषज्ञता प्राप्त है। इसकी परिकल्पना विकासशील देशों के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर प्रभावी नीतिगत संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में की गई है। आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य फोकस दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्ताओं में विकासशील देशों के साथ सहयोग करना है। अपने निम्नलिखित केंद्रों/मंचों के माध्यम से, आरआईएस क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत संवाद और तालमेल को बढ़ावा देता है।

DAKSHIN
Development and Knowledge Sharing Initiative
GLOBAL SOUTH CENTRE OF EXCELLENCE

"दक्षिण" मूलतः संस्कृत का शब्द है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवम्बर 2023 में दक्षिण – ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यह पहल वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों के दौरान ग्लोबल साउथ नेताओं की चर्चाओं से प्रेरित थी। दक्षिण का पूरा नाम–डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव है। आरआईएस स्थित दक्षिण ने ग्लोबल साउथ के प्रमुख थिंक टैंक्स और विश्वविद्यालयों के साथ संबंध स्थापित किए हैं और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर काम करने वाले विद्वानों का एक गतिशील नेटवर्क तैयार कर रहा है।

AIC
ASEAN-India Centre at RIS

आरआईएस स्थित एआईसी आसियान समुदाय की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और आसियान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। आरआईएस में एआईसी भारत और आसियान देशों के संबंधित संगठनों और थिंक–टैंक्स के साथ अनुसंधान, नीतिगत समर्थन और नियमित नेटवर्किंग गतिविधियां करता है। इसका उद्देश्य आसियान–भारत साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत सुझाव, नवीनतम जानकारी और डेटा संसाधन उपलब्ध कराना तथा निरंतर संवाद बनाए रखना है।

सीएमईसी को आरआईएस में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसएंडडब्ल्यू) के अधीन स्थापित किया गया है। सीएमईसी, आरआईएस और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (आईपीए) के बीच एक सहयोग है। इसे एमओपीएसडब्ल्यू का सलाहकार/प्रौद्योगिकी केंद्र बनने और नीतियों तथा उनके क्रियान्वयन पर विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है।

FITM
Forum on Indian Traditional Medicine

एफआईटीएम भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और आरआईएस की संयुक्त पहल है। इसकी स्थापना पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), व्यापार, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर नीतिगत अनुसंधान करने के उद्देश्य की गई। एफआईटीएम उभरते राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर आयुष मंत्रालय को नीति और रणनीति संबंधी विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान करता है।

BEF
BLUE ECONOMY FORUM

बीईएफ का उद्देश्य हिंद महासागर और अन्य क्षेत्रों में नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए संवाद के समर्पित मंच के रूप में योगदान देना है। यह मंच नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाओं, अवसरों और चुनौतियों के बारे में अध्ययन करने, सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत पेशेवरों को नियमित जानकारी और सुझाव देने, और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में इसे सुचारू रूप से अपनाने के लिए प्रचार–प्रसार करने पर केंद्रित है।

FIDC
FORUM FOR INDIAN DEVELOPMENT COOPERATION
भारतीय विकास सहयोग मंच

एफआईडीसी अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग के परिदृश्य की पृष्ठभूमि में दक्षिण–दक्षिण सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत के विकास सहयोग कार्यक्रम की बारीकियों का अध्ययन करने में संलग्न रहा है। यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए), शैक्षणिक संस्थानों और सिविल सोसायटी संगठनों की त्रिपक्षीय पहल है।

FISD

एफआईडीसी का उद्देश्य भारत की विकास और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कूटनीति, विदेश नीति और विकास सहयोग के बीच पूरी क्षमता और तालमेल का उपयोग करना है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत की भागीदारी को मजबूती प्रदान करने में भी संलग्न है।

SACEP

आरआईएस अपनी कार्य योजना के अंतर्गत, दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने में सक्रिय रूप से संलग्न है। इस संदर्भ में साउथ एशिया सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज (एसएसीईपीएस) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एसएसीईपीएस एक नेटवर्क संगठन है, जो दक्षिण एशिया में समान रूप से प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने में संलग्न है।

NeST
Network of Southern Think-Tanks

दक्षिणी साझेदारों के बीच आंतरिक रूप से उत्पन्न ज्ञान विभिन्न वैश्विक नीतिगत मंचों पर मजबूत साझा मुद्दों को एकजुट करने में मदद कर सकता है। एनईएसटी का उद्देश्य दक्षिणी थिंक–टैंक्स को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग के दृष्टिकोण पर सहयोगपूर्ण रूप से ज्ञान का सृजन कर सकें, उसे व्यवस्थित कर सकें, उसे समेकित और साझा कर सकें।

DST SPR
Department of Science and Technology Satellite Centre for Policy Research at RIS
STI Diplomacy

आरआईएस में डीएसटी – सैटेलाइट सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ऑन एसटीआई डिप्लोमेसी का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार (एसटीआई) और कूटनीति के संगम पर भारत की विकास प्राथमिकताओं और विदेश नीति उद्देश्यों के अनुरूप नीतिगत अनुसंधान को आगे बढ़ाना है।

ग्लोबल साउथ के विकास को सुनिश्चित करना

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत
दूरभाष: 91–11–24682177–80, ई–मेल: dgoffice@ris.org.वेबसाइट: http://www.ris.org.in

फोलो करें

www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi